

वीर अर्जुन

वर्षों से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

देश

थरूर का वित्त
मंत्री पर तंज



विविध: फिर तेज हुई रश्मिका की शादी की खबरें * नई दिल्ली, लखनऊ एवं देहरादून से प्रकाशित

जिल्द: 42, अंक: 62 पृष्ठ: 12 E-mail: newsdesk@virarjun.com Website: www.virarjun.com E-Paper: www.epapervirarjun.com
R.N.I. No. 511/57 D.L.(C)-05/1270/2024-26 (Posted at Delhi RMS) नई दिल्ली, सोमवार, 2 फरवरी 2026 मूल्य: ₹ 4.00 प्रभात संस्करण



बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज

सरकार का सुधार एक्सप्रेस के साथ किसानों, युवाओं, छोटे उद्योगों व पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया और सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा कंट्रोल के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। हालांकि, बजट में वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति सौदा कर बढ़ाये जाने से शेयर बाजार लगभग दो प्रतिशत तक लुढ़क गया। बीएसई सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 495 अंक की गिरावट आई। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अबतक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करती हुई। (एएनआई)

सस्ती होने वाली वस्तुएं-★ कैसर की दवाएं★ सात दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दवाएं, औषधियां और खाद्य पदार्थ★ व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाएं★ माइक्रोवेव ओवन के कलपुर्जे★ विमान के इंजन सहित कलपुर्जे★ सोलर ग्लास के कलपुर्जे★ परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान★ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान
महंगी होने वाली वस्तुएं★ कम लागत वाले आयातित छाते★ पोटेरियम हाइड्रोक्साइड★ एटीएम/कैश डिस्पेंसर मशीन और उसके कलपुर्जे★ विदेशी लोगों के लिए फिल्म और प्रसारण उपकरण★ चिड़ियाघर में बाहर से जानवर व पक्षी लाना★ अमोनियम फॉस्फेट/नाइट्रो-फॉस्फेट उर्वरक व नेफथा जैसे उर्वरक

होने वाले हैं, इसके बावजूद राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया गया। सीतारमण ने छूटों को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गयी है। साथ ही बैगेज नियमों में ढील दी है और व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाये रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर

दिया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों... औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री... में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के चैंपियन तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एएसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने की बात कही गयी है। बजट में घोषित उपाय पिछले वर्ष आयकर में छूट और जीएसटी कटौती के पूरक हैं।

रक्षा बजट के लिए 7.84 लाख करोड़ रुपए आवंटित

नई दिल्ली, (बिप्रा)। सरकार ने रविवार को 2026-27 के लिए रक्षा व्यय के रूप में 7,84,678 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी। कुल पूंजीगत व्यय 2,19,306 करोड़ रुपये आंका गया है। राजस्व व्यय 5,53,668 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपये शामिल है। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने 2025-26 में रक्षा बजट के लिए 6,81,210 रुपये आवंटित किए थे। पूंजीगत

व्यय 1,80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जो संशोधित अनुमान चरण में बढ़कर 1,86,454 करोड़ रुपये हो गया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अस्त्र, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क माफ करने की भी घोषणा की। इन दोनों फैसलों से रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग को मदद मिलने की उम्मीद है।

बजट महत्वाकांक्षी, भविष्योन्मुखी: मोदी

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आम बजट 2026-27 को महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा, क्योंकि देश के 140 करोड़ नागरिक इसके सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं और राष्ट्र जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि यह एक अनूठा बजट है, जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही साथ उच्च पूंजीगत व्यय एवं उच्च विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा, यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से मजबूत करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक देश के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से



बजट पेश किए जाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। (एएनआई)

संतुष्ट नहीं हैं, और राष्ट्र जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से हाल में किए गए प्रमुख व्यापार समझौतों का उद्देश्य देश के युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्यमों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है तथा इस बजट में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मोदी ने कहा, आज का बजट ऐतिहासिक है और देश की महिलाओं की सशक्त भावना को दर्शाता है।

एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ आवंटित

नई दिल्ली (बिप्रा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को चैंपियन बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि बजट की रीति-नीति तीन कर्तव्यों पर आधारित है जिसमें आर्थिक वृद्धि

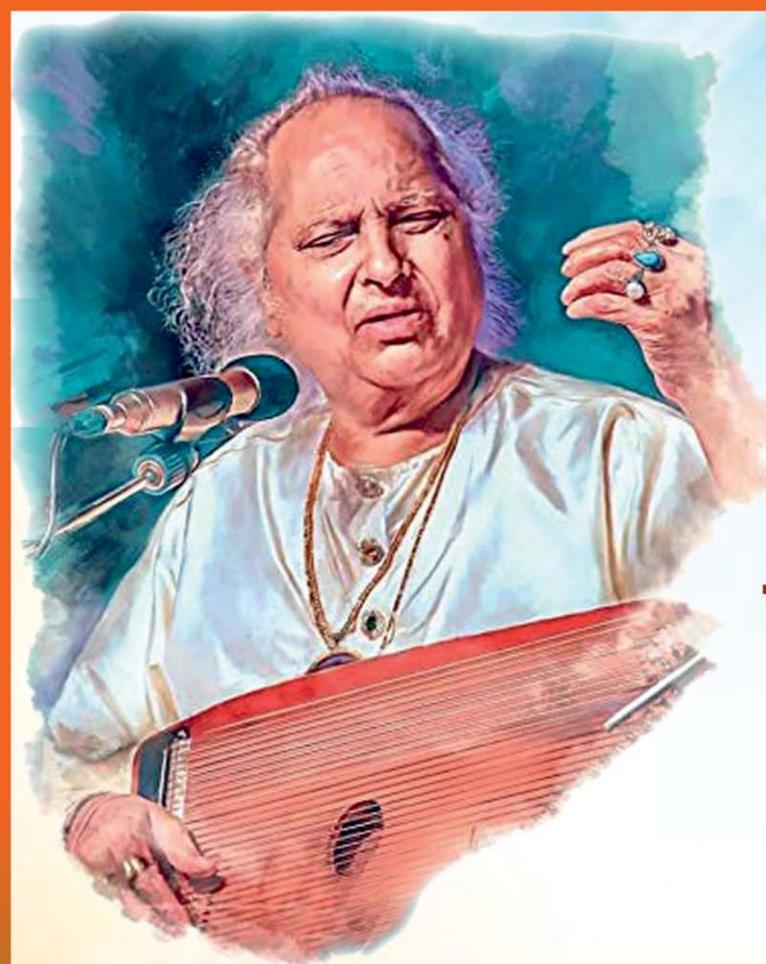
को तेज और स्थायी बनाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण तथा सबका साथ, सबका विकास। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इट्रिटी समर्थन, नगदी समर्थन और पेशेवर समर्थन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक्विटी समर्थन के तहत 10,000 करोड़ रुपये के एएसएमई विकास कोष के माध्यम से चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तरलता समर्थन के लिए ट्रेड्स मंच की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा।



हरियाणा सरकार

संगीत सम्राट पंडित जसराज जी की स्मृति में

राज्य स्तरीय कार्यक्रम



मुख्य अतिथि

श्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री, हरियाणा

2 फरवरी, 2026 | दोपहर 1 बजे | पीली मंदोरी, फतेहाबाद

आप सादर आमंत्रित हैं



“हमारे यहां संगीत, सुर और स्वर को अमर माना गया है। पंडित जसराज जी ने संगीत को ही जिया है, संगीत ही जिसके अस्तित्व के कण-कण में गूँजता रहा हो, वो शरीर त्यागने के बाद भी ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना में अमर रहता है।”
- नरेन्द्र मोदी

कार्यक्रम से जुड़ने के लिए
क्यू आर कोड स्कैन करें



सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | Follow us on [Social Media Icons] | @dipharyana

शिक्षा: बजट में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप, हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास की घोषणा

विशेष प्रतिनिधि
नई दिल्ली। केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई प्रस्तावों की घोषणा की गई है। इनमें प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कार्रिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना, हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करना तथा शिक्षा के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर को घटाकर दो प्रतिशत करना शामिल है। इस क्षेत्र के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल हैं। लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कार्रिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव

नई दिल्ली, (विप्र)। सरकार ने रविवार को श्रम-गहन कपड़ा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की और मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। अपने बजट भाषण में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, श्रम-गहन कपड़ा क्षेत्र के लिए, मैं पांच उप-खंड के साथ एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ। इन पांच उप-खंड के तहत, उन्होंने रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए 'नेशनल फाइबर स्कीम (राष्ट्रीय धागा योजना)' की घोषणा की। सरकार ने मशीनों के लिए पूंजी सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य जांच और प्रमाणिकरण केन्द्र के साथ पारंपरिक कलस्टर को आधुनिक बनाने के लिए टेक्सटाइल विस्तार एवं रोजगार योजना का प्रस्ताव दिया। मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं मजबूत करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया है।

	अधिकतम न्यूनतम	17.00 7.00	
	वीएसई एमएसई	82,269.78 25,320.65	
	डॉलर यूरो	91.68 108.70	
अपने विचार भेजें			
क्या केंद्रीय बजट में सुधार का संकल्प है?			
क्या बजट में मध्यम वर्ग पर सरकार का ध्यान रहना चाहिए?			
	हां	नहीं	पता नहीं
	75%	15%	10%
* कृपया जनमत हेतु अपना मत www.vivaran.com पर भेजें			

वीर अर्जुन न्यूज पेपर्स (प्रा) लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक अनिल नरेंद्र द्वारा वीर अर्जुन प्रेस, प्रताप भवन, 5, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2 से मुद्रित एवं प्रकाशित

प्रधान सम्पादक: अनिल नरेंद्र
ज्वाइंट एडिटर: आदित्य नरेंद्र
सहायक सम्पादक:
सदानन्द पाण्डेय *
संपादकीय :
फोन: 011-23318276
फैक्स: 011-23730544
: 011-41509000
E-mail: newsdesk@virarjun.com
विज्ञापन
फोन : 011-44718542
011-23357216
E-mail: advt@virarjun.com
virarjun10@gmail.com
प्रसार: 011-23724452
हवाई शुल्क: 150 पैसे
* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु वीरारजू एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी।
● किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा।

सीतारमण ने देश के प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षा के एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) संस्थानों में, लंबे समय तक अध्ययन और प्रयोगशाला कार्य करने से छात्राओं को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय बजट में वीजीएफ या पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और निदान प्रयोगशालाओं के लिए ठुण-आधारित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। बजट में मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट लैब स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को विकसित भारत का बजट बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा, यह बजट शिक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाला और विकास के अगले चरण के लिए एक खाका

प्रस्तुत करता है। भारत के कोने-कोने में शिक्षा और भविष्य के लिए तैयार कौशल को मजबूत करने के संबंध में बड़े और साहसिक निवेश प्रस्तावित किए गए हैं। बजट में पूर्वी क्षेत्र में एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा। एलआरएस के तहत 10 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल प्रेषण पर शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से टीसीएस की दर को मौजूदा पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। एलआरएस के तहत सभी निवासी व्यक्ति, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, किसी भी मान्य चालू या पूंजी खाते के लेनदेन अथवा दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि स्वतंत्र रूप से भेज सकते हैं। हालांकि, शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए टीसीएस दर पर 20 प्रतिशत कर बरकरार रहेगा।

पत्रकारिता में नेशंस बेस्ट एजुकेंटर अवार्ड के एकमात्र विजेता बने डॉ. एसके पांडेय

नई दिल्ली (वीअ)। वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया एजुकेंटर डॉ. एस.के. पांडेय को प्रतिष्ठित 'नेशंस बेस्ट एजुकेंटर अवार्ड' से सम्मानित किया गया है, जो भारत में पत्रकारिता शिक्षा में उनके योगदान को एक महत्वपूर्ण पहचान है। डॉ. पांडेय देश भर में पत्रकारिता शिक्षा के लिए 'नेशंस बेस्ट एजुकेंटर अवार्ड' के तहत चुने गए अकेले व्यक्ति हैं। अलग-अलग कैटेगरी में इस सम्मान के लिए चुने गए राष्ट्रीय स्तर की 27 जानी-मानी हस्तियों में उनका नाम शामिल है। यह अवार्ड हेमाश्री पब्लिकेशन, सीकर और जीवन आशीष समिति, कोटा (राजस्थान) ने मिलकर दिया। हेमाश्री पब्लिकेशन की डायरेक्टर डॉ. खुशबू गुप्ता के अनुसार, 'नेशनल प्राइड अवार्ड' के लिए देश भर से कुल 693 नॉमिनेशन मिले



थे। कड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, चयन समिति ने 'नेशन प्राइड अवार्ड' के तहत चुने गए अकेले अलग-अलग अवार्ड कैटेगरी के लिए कुल 27 बेहतरीन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। इन कैटेगरी में शिक्षा, रिसर्च, हेल्थकेयर, कला, नेतृत्व, इनोवेशन, जनसेवा आदि शामिल थे। चयन समिति ने कहा कि डॉ. एस.के. पांडेय को पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और ऊर्जावान मेहनत के लिए 'नेशंस बेस्ट एजुकेंटर अवार्ड' दिया गया है।

चुनावी वर्ष में भी सीतारमण ने तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया : द्रमुक

चेन्नई, (भाषा)। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने रविवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में राज्य को एक बार फिर कुछ नहीं दिया है। द्रमुक ने बजट को दिशाहीन करार दिया है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक प्रवक्ता ने कहा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां के लोगों की उम्मीदें अलग हैं, लेकिन जब हम पूरे बजट को देखते हैं तो उसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों समेत किसी भी क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। बजट का कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। बजट ने देश की जनता के बीच समग्र तिता पैदा कर दी है, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तमिलनाडु में चुनाव प्रस्तावित होने के बावजूद केंद्र सरकार ने दक्षिणी राज्य पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है।

रणबीर कपूर रामायण में भगवान राम के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं: अरुण गोविल

मुंबई, (भाषा)। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक रामायण में भगवान राम की अपनी यादगार भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता अरुण गोविल ने इस महाकाव्य पर आधारित फिल्म की सराहना करते हुए इसके मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर की तारीफ की। गोविल ने कहा कि पर्दे पर भगवान की भूमिका वही व्यक्ति विश्वसनीय रूप से निभा सकता है, जो अच्छा अभिनेता और अच्छा ईशान हो। महत्वाकांक्षी सिनेमाई प्रस्तुति के रूप में पेश की जा रही इस फिल्म में केजीएफ के अभिनेता यश रावण की भूमिका में हैं, साईं पल्लवी देवी सीता, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे भगवान लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन दंगल से ख्याति पाने वाले नितेश तिवारी कर रहे हैं। गोविल ने पीटीआई-

इन्दिरा आईवीएफ का मलाड मुम्बई में नया फ़र्टिलिटी क्लिनिक शुरू

मुम्बई (वीअ)। इन्दिरा आईवीएफ हॉस्पिटल लिमिटेड ने मुंबई में अपनी उपस्थिति को और सशक्त करते हुए मलाड में एक नए फ़र्टिलिटी क्लिनिक की शुरुआत की है। इस सेंटर के उद्घाटन के साथ, शहर के पश्चिमी उपनगरों में संगठित फ़र्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंच और सुलभ हो सकेगी। नया इन्दिरा आईवीएफ क्लिनिक, यूनिट नंबर 104, फ़र्ट प्लोर, अनुपम अपार्टमेंट, एस.वी. रोड, रेशम ऑफिस के सामने, मलाड (मुम्बई) पर शुरू किया गया है। यह सेंटर सभी तरह की फ़र्टिलिटी और आईवीएफ सेवाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। यह सेंटर इन्दिरा आईवीएफ के स्पेण्डर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल, तकनीकी प्रणालियों और अनुभवी विशेषज्ञ टीम के द्वारा संचालित होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि

फिर तेज हुई रश्मिका की शादी की खबरें

वीर अर्जुन समाचार व्यूरो
नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि कपल 2 फरवरी को उदयपुर के एक पैलेस में शादी करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।

हाल ही में उदयपुर के पैलेस से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पैलेस में डेकोरेशन लेकर अन्य तैयारियां जारी हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए एक इम्प्लूमेंटर ने दावा किया है कि ये डेकोरेशन विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के लिए की जा रही है। इम्प्लूमेंटर का दावा है कि उन्होंने पैलेस में मौजूद स्टाफ से डेकोरेशन की वजह पूछी, जिस पर उन्हें बताया गया कि 2 फरवरी को यहां विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी होगी। डेकोरेशन का वीडियो सामने आने से पहले दिसंबर में भी खबरें रही कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका फरवरी में शादी करने वाले हैं। उस समय शादी की बेन्चू की उदयपुर ही बताई गई थी। एनडीटीवी की रिपोर्टों के मुताबिक करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि कपल की शादी उदयपुर के पैलेस में 26 फरवरी



को होने वाली है। इसके बाद कपल अलग-अलग जगह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए रिसेप्शन रखेंगे। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 3 अक्टूबर को हैदराबाद में सगाई की है। ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी, जिसमें कपल के परिवार के चंद लोग ही शामिल हुए थे। इसके

बाद रश्मिका को कई मौकों पर एंजोमेंट रिंग के साथ सॉट किया गया था, हालांकि कपल ने अब तक सगाई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। सगाई की खबरों के बीच रश्मिका मंदाना ने हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं शादी के कर्म या खारिज नहीं करना चाहूंगी।

जम्मू-कश्मीर: भारी बर्फबारी के दौरान फंसे बंदरों को बचाया

जम्मू, (भाषा)। जम्मू-कश्मीर के पटनोटॉप इलाके में भारी बर्फबारी के कारण फंसे कुछ बंदरों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के राजमार्ग रखरखाव कर्मचारियों ने सुरक्षित निकालकर उन्हें भोजन कराया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाशरी-पटनोटॉप-चेनानी खंड के नियमित निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों ने बंदरों को फंसे हुआ पाया था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एनआरएम कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों ने बर्फ से ढकी सड़क के किनारे और आसपास के वन क्षेत्रों में कई बंदरों को फंसे हुए देखा।

वीबी-जी राम जी के लिए 95,000 करोड़ आवंटित

विशेष प्रतिनिधि
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई योजना वीबी-जी राम जी को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत-गारटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत साल में 125 दिनों के काम का वादा किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के तहत बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल की दो दशक पुरानी ग्रामीण रोजगार योजना का स्थान लेगी। ग्रामीण

विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा योजना तब तक जारी रहेगी, जब तक वीबी-जी राम जी पूरी तरह अमल में नहीं आ जाती और इसके तहत लॉबित कार्य पूरे नहीं हो जाते। बजट दस्तावेजों के अनुसार, मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल 1,94,368.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है। वर्ष 2026-27 के लिए भूमि संसाधन विभाग को 2,654.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में इस विभाग के लिए 2,651 करोड़ रुपये का आवंटन था, जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार वास्तविक खर्च 1,757.4 करोड़ रुपये रहा।

मोदी ने संत रविदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी नई दिल्ली, (विप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संत रविदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि करुणा और न्याय पर उनके विचार सरकार के कल्याणकारी कदमों का मूल आधार हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मानवता के अनन्य उपासक महान संत श्री गुरु रविदास महाराज जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। मोदी ने कहा, उनके विचारों में न्याय और करुणा का भाव सर्वोपरि था, जो जनकल्याण की हमारी योजनाओं के मूल में है। उन्होंने सामाजिक समरसता और सद्भावना के जिस दीप को प्रज्वलित किया, वह देशवासियों के पथ को सदैव आलोकित करता रहेगा। प्रधानमंत्री संत रविदास के अनुयायियों, रविदासिया समुदाय के एक पवित्र स्थान डेरा सचखंड बल्ला का दौरा कर रहे हैं। उनका डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास से भी बातचीत का कार्यक्रम है, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

फोन टैपिंग मामले: तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री राव हैदराबाद में एसआईटी के सामने पेश हुए

हैदराबाद, (भाषा)। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) रविवार को बीआरएस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कथित फोन टैपिंग से संबंधित एक मामले के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष अपने आवास पर पूछताछ के लिए पेश हुए। पूछताछ से कुछ घंटे पहले, राव हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर येवेल्ली स्थित अपने फार्महाउस से निकले और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नंदी नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। एसआईटी अधिकारियों का एक दल भी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) अध्यक्ष के आवास पहुंचा। राव के आवास के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और गली को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। केसीआर के नाम से चर्चित राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगाया। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस सरकार द्वारा उनके नेता के राजनैतिक उत्पीड़ने के विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन किया।

केंद्रीय बजट से गरीबों और किसानों का जीवन बेहतर होगा : चंपई सोरेन

जमशेदपुर, (भाषा)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए रविवार को कहा कि इससे गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और छात्रों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह व्यापक, सर्वव्यापी और समावेशी बजट, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए एक खाका के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा, यह बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। यह प्रत्येक परिवार को पर्याप्त संसाधन और कमाई के अवसर प्रदान करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करना बजट की प्राथमिकताओं में से एक है। सोरेन ने कहा कि काजू, अखरोट, बादाम, नारियल, कॉफी और मछली पालन से संबंधित पहल के माध्यम से किसानों और छोटे व्यवसायियों को आय बढ़ाने पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए विशेष प्रावधान बुनकरों के जीवन में समृद्धि लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सोरेन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाने के उद्देश्य से पेश किए गए बजट के लिए बधाई दी।

आज का भविष्यफल

मेष: धैर्य से काम लेने पर परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। मानसिक शांति बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद और अंक 7 सौभाग्य बढ़ाएँगे।
वृषभ: रिश्तों में स्पष्टता आएगी और विश्वास बढ़ेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। सुनहरा रंग और अंक 33 सफलता में सहायक होंगे।
मिथुन: धैर्य से काम लेने पर परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। छोटे निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे। सफेद रंग और अंक 85 सफलता में सहायक होंगे।
कर्क: कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी और निर्णय सफल रहेंगे। धन संबंधी चिंता कम होगी। ग्रे रंग और अंक 21 सफलता में सहायक होंगे।
सिंह: रिश्तों में स्पष्टता आएगी और विश्वास बढ़ेगा। धन संबंधी चिंता कम होगी। शुभ रंग भूरा और अंक 85 सौभाग्य बढ़ाएँगे।
कन्या: धैर्य से काम लेने पर परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। धन संबंधी चिंता कम होगी। गुलाबी रंग और अंक 3 सफलता में सहायक होंगे।
तुला: कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी और निर्णय सफल रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज लाल रंग धारण करें, अंक 3 शुभ रहेगा।
वृश्चिक: आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और लाभ संभव है। छोटे निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे। पीला रंग और अंक 85 सफलता में सहायक होंगे।
धनु: रिश्तों में स्पष्टता आएगी और विश्वास बढ़ेगा। धन संबंधी चिंता कम होगी। नारंगी रंग और अंक 33 सफलता में सहायक होंगे।
कुंभ: आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और लाभ संभव है। दैनिक कार्य सहजता से पूरे होंगे। पीला रंग और अंक 3 सफलता में सहायक होंगे।
मीन: सकारात्मक सोच से सप्ताह सफल बनेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद और अंक 44 सौभाग्य बढ़ाएँगे।
डा.सुनील भारती दैवज्ञ: मो. 09891192750

सूचना
हमारे यहां अखबारों की प्रिंटिंग व डिस्पैच की सुविधा देश के कोने-कोने के लिए उपलब्ध है : सम्पर्क करें :-
आदित्य ग्राफिक्स
9868475104
प्रताप भवन, 5, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
वीर अर्जुन
आवश्यकता है
नई दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी/दैनिक समाचार पत्र के लिए आवश्यकता है महिला एवं पुरुष विज्ञापन प्रतिनिधियों की। विज्ञापन के क्षेत्र में अनुभवी एवं फ़ेशर भी आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण विवरण सहित आवेदन करें:-
dpks0008@gmail.com
तथा
mehta.virarjun@gmail.com
9871763690, 8130704757

विकसित भारत की सशक्त नींव है यह बजट, दिल्ली को मिलेगी नई ऊंचाइयां: रेखा गुप्ता

★ प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतिबिंब है आम बजट, दिल्ली को मिलेगा बहुआयामी लाभ

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने एक फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट की सराहना करते हुए इसका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊंचाई देने वाला है। मुख्यमंत्री के अनुसार, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट आदर्शपूर्ण प्रतिभामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतिबिंब है, जो हर नागरिक को सशक्त बनाने, समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने और देश को सतत व मजबूत आर्थिक वृद्धि को गति देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट तीन स्पष्ट कर्तव्यों पर केंद्रित है। पहला, आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना, जिसके लिए निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत आधार दिया गया है ताकि विकास व्यापक और टिकाऊ हो सके। दूसरा, देशवासियों को उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना, जिससे आम आदमी का जीवन अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बने। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि विकास और संसाधनों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और 'सबका साथ, सबका विकास' का संकल्प वास्तविकता में बदले। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग के हितों



दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता

को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खासकर अन्नदाता किसानों, युवा शक्ति, नारी शक्ति और वंचित वर्गों के लिए। किसानों को आय बढ़ाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया है। घरेलू निर्माण और मैनुफैक्चरिंग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का स्पष्ट रोडमैप भी इस बजट में नजर आता है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट में स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे भविष्य के क्षेत्रों में इनोवेशन और विकास को प्रोत्साहित किया गया है।

इससे न सिर्फ रोजगार और समृद्धि के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता भी और मजबूत होगी। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर जिस स्पष्टता और गंभीरता के साथ बात रखी गई है, वह वास्तव में सराहनीय है। इसी तरह देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर उसे मजबूत और आकर्षक पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित करने की सोच को भी मुख्यमंत्री ने बेहद प्रभावी बताया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खेलो इंडिया मिशन को लेकर आदर्शपूर्ण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के विजन की साफ झलक इस बजट में दिखाई देती है। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विदेश जाने वाले नागरिकों को मिलने वाली रियायतें मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए बड़ी राहत हैं। आपदा प्रबंधन के लिए शहरों को दिए जाने वाले अनुदानों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली को भी ख़ासा लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्यों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान एक सकारात्मक और दूरगामी कदम है, जो सभी राज्यों को विकास की नई गति देगा।

दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा को मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक बताया हुए कहा कि यह केवल रेल परियोजना नहीं है, बल्कि यह गति, प्रगति और जनविश्वास का प्रतीक है।

दिल्ली में फरवरी की शुरुआत ठंडी रही, अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी की शुरुआत ज्यादा ठंडी रही और रविवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारत मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान पिछले वर्ष के 26.2 डिग्री सेल्सियस से कम है, जबकि मौसम के औसत से 2.3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से लगभग 3.7 डिग्री अधिक है। शहर की प्रमुख वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस में दर्ज किया गया जबकि पालम में 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। लोधी रोड पर 11.8 डिग्री सेल्सियस, रिज पर 12.1 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में

11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शहर में अधिकतम तापमान 22.6 से 24.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। विभिन्न स्टेशनों में, सफदरजंग में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद आयानगर में 23.6 डिग्री सेल्सियस और रिज में 23.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि लोधी रोड में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और पालम में 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम साढ़े पांच बजे सापेक्ष आर्द्रता 82 प्रतिशत थी।

मौसम विभाग ने इस महीने न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे ठंडी रातों की संख्या कम होगी और दोपहर गर्म रहेंगी, क्योंकि सर्दियों की स्थिति सामान्य से पहले समाप्त हो रही है। इस बीच, राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई है, जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 265 दर्ज किया गया है, जो दिन के समय लगभग 315 होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने पूर्वानुमान लगाया है कि एक से तीन फरवरी तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम कोहरे का अनुमान लगाया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 21 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

दिल्ली को वित्तवर्ष 2026-27 में भी गृह मंत्रालय से 1348 करोड़ मिलेंगे

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली के लिए आवंटन पिछले वर्ष के समान ही 1,348 करोड़ रुपये है। यह दिल्ली में नई भाजपा सरकार के तहत पहला बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली को कुल 1348.01 करोड़ रुपये आवंटित होंगे, जिनमें राजस्व मद के तहत 968.01 करोड़ रुपये और भू-पूंजीगत व्यय मद के तहत 380 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। ये आंकड़े 2025-26 वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों को दर्शाते हैं। बजट दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों के

लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 951 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी सरकार की विभिन्न योजनाओं को वित्त पोषित करना है। चंद्रावल जल उपचार संयंत्र को 380 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य मौजूदा जल आपूर्ति अवसरचना में सुधार करना, कमान क्षेत्र में समान जल वितरण सुनिश्चित करना और चौबीस घंटे जलापूर्ति आपूर्ति प्रणाली स्थापित करना था। दिल्ली को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान और भू-पूंजीगत व्यय मद के तहत 380 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। ये आंकड़े 2025-26 वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों को दर्शाते हैं। बजट दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों के

विधानसभा सदस्यों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण 2 से 14 तक : विजेन्द्र गुप्ता

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण निवारक स्वास्थ्य सेवा और संस्थागत उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण अंग है

★ यह प्रक्रिया पूरी तरह से मौजूदा सरकारी मानदंडों के अनुसार होगी

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आज जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा के सभी वर्तमान माननीय सदस्यों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण 2 फरवरी से 14 फरवरी 2026 तक संत परमानंद अस्पताल कश्मीरी गेट में कराया जाएगा। यह परीक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) की मौजूदा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

अध्यक्ष ने कहा कि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण निवारक स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सार्वजनिक संस्थानों के सुचारु, निरंतर और प्रभावी संचालन में सहायक होता है। समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से बीमारियों को प्रारंभिक पहचान संभव होती है, जिससे भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया है, जो स्वास्थ्य महानिदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के



दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता

अनुसार संचालित की जा रही है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की नई सुविधा, विशेष रियायत या अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं किया गया है। सभी परीक्षण निर्धारित सरकारी मानकों, प्रक्रियाओं और सीमाओं के अनुसार ही किए जाएंगे। संत परमानंद अस्पताल, जो उच्च द्वारा अधिकृत और सूचीबद्ध है, को प्रशासनिक सुविधा और निकटता को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। अस्पताल से अनुरोध किया गया है कि वह योजना के अंतर्गत पात्र सदस्यों को केशलेस स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान करे। जहां सरकारी अधिकारियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन अथवा स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान है, वहीं दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए यह वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण मौजूदा उच्च स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, अध्यक्ष की पहल पर, एक समान एवं विशिष्ट व्यवस्था के रूप में किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आयु की परवाह किए बिना सभी सदस्यों, जिनमें 40 वर्ष से कम आयु के सदस्य भी शामिल हैं, को वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के दायरे में लाया गया है। इससे सभी सदस्यों को समान रूप से निवारक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करें, ताकि यह प्रक्रिया नियमानुसार और सुचारु रूप से पूरी की जा सके।

बजट घोषणा में प्रदूषण झेलती दिल्ली के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी : देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली, (वीर अर्जुन)। बजट में कोई पहल दिखाई नहीं देती। देवेन्द्र यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट के पास होने के बाद दिल्ली वालों को निराशा हाथ लगी है। दिल्ली में भाजपा की सरकार होने पर दिल्ली वालों को महंगाई और बेरोजगारी से राहत मिलने की दिशा में निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पारित बजट के बाद दिल्ली के लिए बजट आवंटन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, मूलभूत सुविधाओं और दिल्ली के इफ़ेक्टिवर के लिए जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही आक्षेप दिखाई नहीं दी। तो दिल्ली की जनता की उम्मीदें और जरूरतें आगामी वित्त वर्ष में कैसे पूरी होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता ने केंद्र प्रशासित राज्यों को 1.4 करोड़ के बजट पर सिर्फ गोमोल बाते करती दिखाई दी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली को मोदी सरकार ने बजट में कुछ खास नहीं दिया है। प्रदूषण के लिए केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारों को जमीनी हालात के महानजर निर्णय लेने होंगे, क्योंकि



देवेन्द्र यादव

यदव ने कहा कि मेट्रो के चौथे और पांचवें फेज की जो घोषणा और बजट की घोषणा पहले हो चुकी है, आर.के. आश्रम से इन्द्रप्रस्थ सेन्ट्रल विस्टा कारिडोर पर सिर्फ फंड बढ़ाकर वाहवाही लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोजगार सृजन, युवाओं को अवसर और महंगाई पर नियंत्रण, लोगों की अजीबिका के साधन बढ़ाने पर ध्यान न देकर हवा हवाई घोषणा की है। साईकिल ट्रैक, स्मार्ट शहर, पैदल यात्री के लिए पथ आदि से दिल्ली की 75 प्रतिशत गरीब और मध्यम वर्गीय जनता का क्या मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में वर्तमान छोड़ भविष्य की बात की है।

प्रदूषण का मुख्य कारण सरकार और अधिकारियों को मालूम है, सिर्फ उन कारणों पर नियंत्रण करने के लिए काम सिर्फ दस्तावेज में होता है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि मेट्रो के चौथे और पांचवें फेज की जो घोषणा और बजट की घोषणा पहले हो चुकी है, आर.के. आश्रम से इन्द्रप्रस्थ सेन्ट्रल विस्टा कारिडोर पर सिर्फ फंड बढ़ाकर वाहवाही लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोजगार सृजन, युवाओं को अवसर और महंगाई पर नियंत्रण, लोगों की अजीबिका के साधन बढ़ाने पर ध्यान न देकर हवा हवाई घोषणा की है। साईकिल ट्रैक, स्मार्ट शहर, पैदल यात्री के लिए पथ आदि से दिल्ली की 75 प्रतिशत गरीब और मध्यम वर्गीय जनता का क्या मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में वर्तमान छोड़ भविष्य की बात की है।

अमृत उद्यान कल से आमजन के लिए खुलेगा: राष्ट्रपति भवन

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान के शीतकालीन वार्षिक संस्करण 2026 का रविवार को उद्घाटन किया और इसके साथ ही यह उद्यान मंगलवार से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया कि लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम छह बजे के बीच (अंतिम प्रवेश शाम पांच बजे) उद्यान में जा सकेंगे। यह रखरखाव के लिए सोमवार को और होली के कारण चार मार्च को बंद रहेगा। इसमें कहा गया, आम लोग राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान देखने के लिए तीन फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आ सकेंगे। हालांकि, इस बार मौके पर बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। आगंतुक केवल ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। उद्यान के लिए बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है।

सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अंतिम शटल बस सेवा शाम चार बजे उपलब्ध होगी। आगंतुकों के लिए मांग बाल वाटिका-व्यूमेरिया गार्डन-बैयन गार्डन-बॉसाई गार्डन-बैबलिंग बुक-सेंट्रल लॉन-लॉन गार्डन-सर्कुलर गार्डन होगा। अमृत उद्यान में गुलाब की 145 किस्म हैं, जिनमें भीम, अर्जुन और मंदर टेरेंसा शामिल हैं। आगंतुक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स/हैडबैग, पानी की बोतल और शिशुओं के लिए दूध की बोतल साथ ले जा सकेंगे। सार्वजनिक मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचाराचिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। अमृत उद्यान के अलावा लोग सप्ताह में छह दिन (मंगलवार से रविवार) राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी देख सकेंगे। वे प्रत्येक शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाला चेंज-ऑफ-गार्ड समारोह भी देख सकेंगे। केंद्रीय

गुरु रविदास जी की जयंती पर नरेला में आयोजित हुआ भंडारा एवं शोभायात्रा

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के पावन अवसर पर आज नरेला स्थित गुरु रविदास मंदिर में आयोजित 31वें भव्य भंडारा एवं शोभायात्रा कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सहभागिता कर श्रद्धालुजनों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचार समता, सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और भाईचारे पर आधारित हैं, जो आज भी एक समरस, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में हमें निरंतर प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी के

आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उल्लेखनीय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर इससे पूर्व दिल्ली सचिवालय में श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह के नेतृत्व में एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संत रविदास जी के विचारों, सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। मंत्री श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार गुप्ता जी के नेतृत्व में समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और संत रविदास जी के विचार सरकार की नीतियों और कार्यों के मूल में हैं।

उद्योग, विनिर्माण एवं लघु उद्योगों को सशक्त करने वाला बजट : दिल्ली मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन

नई दिल्ली, (वीर अर्जुन)। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की आर्थिक प्रगति की धुरी विनिर्माण उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ही हैं। दिल्ली मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन इस बजट का स्वागत करती है और इसे उद्योग जगत के लिए विश्वास, स्थिरता और दीर्घकालिक विकास का बजट मानती है। एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि इस बजट में एमएसएमई क्षेत्र को केवल सहायता प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास का सक्रिय भागीदार माना गया है। 70,000 करोड़ के समर्पित एमएसएमई विकास कोष की घोषणा से उद्योगों को इन्क्यूबी आधारित विस्तार पूंजी उपलब्ध होगी, जो नए निवेश और रोजगार सृजन को गति देगी। इसके साथ ही स्वावलंबी भारत कोष में 22,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान विकासशील उद्योगों को मिश्रित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। डॉ. गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोगों द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली खरीद को व्यापार देय रसीद लूट प्रणाली (टी-रेड्स) मंच पर अनिवार्य करना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। साथ ही ऋण गारंटी



डॉ. अनिल गुप्ता

न्यास योजना के अंतर्गत बिना संपांक्षिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना एमएसएमई क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनीत जैन ने कहा कि उर्श और टी-रेड्स के एकीकरण से ऑर्डर से भुगतान तक एक पारदर्शी और तेज डिजिटल प्रक्रिया बनेगी। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहरों में प्रस्तावित 'कॉरपोरेट मित्र' पहल से अनुपालन लागत कम होगी और छोटे उद्योगों को सस्ती पेशेवर सहायता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि कई औद्योगिक कच्चे माल और पुर्जों पर आयात शुल्क में राहत से



विनीत जैन

उत्पादन लागत घटेगी। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन की योजना से स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। निर्यात उन्मुख एमएसएमई के लिए शुल्क राहत और समयसीमा विस्तार से कार्यशील पूंजी पर दबाव कम होगा। सेवा क्षेत्र के लघु उद्योगों के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था, चिकित्सा मूल्य पर्यटन, एबीजीसी (एनोमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गैमिंग और कॉमिक्स), डिजाइन तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे, जिससे रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

ज्योति नगर में विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन



नई दिल्ली, (वीर अर्जुन)। हिंदू समाज में जागरण, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में पश्चिमी ज्योति नगर क्षेत्र में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों और हिंदू समाज की संगठित शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख सतीश ने संत शिरोमणि संत रैदास जी के विचारों का उल्लेख करते हुए समाज में सामाजिक समरसता, समानता और पारस्परिक सम्मान का संदेश दिया। दयालु जी महाराज का वक्तव्य हुआ, उन्होंने अपने सरल एवं प्रेरणादायी वचनों में प्रेम, करुणा और सामाजिक सौहार्द को हिंदू समाज की मूल शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जब समाज संतों के मार्गदर्शन और संगठन की शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, तब राष्ट्र स्वतः सशक्त बनता है। उनके उद्बोधन ने उपस्थित जनसमूह को आत्मचिंतन और सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव से प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त अनेकों वक्ताओं ने समाज को एकजुट करने हेतु प्रेरणादायक उद्बोधन दिए।

आजादपुर ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठक आयोजित : भारत राघव



नई दिल्ली, (वीर अर्जुन)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के निर्देश अनुसार और आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ राव के नेतृत्व में आजादपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष भारत सिंह राघव की अध्यक्षता में हुई। इसमें सुरेंद्र मनीषा, साबिर अल्वी, लाल बाबू पासवान, सुल्तान, हनी शीकान, मनीषा, मन्मोहन कौर, कोमल, इंद्रपाल सिंह, दीपक कुमार, तरुण धवन, होतम सिंह, जसवंत सिंह बिट्टू रामजी, साहिल सलमानी, परसराम, सोहेल कुरेशी, प्रमोद दिवाकर शंकर पासवान आदि नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भारत सिंह राघव ने कहा कि इस तरह से जन नायक राहुल गांधी देशभर में कांग्रेस की मजबूती के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव दिल्ली में पार्टी की मजबूती के संघर्ष कर रहे हैं और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। भारत सिंह राघव ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा इस बजट से दिल्ली के लोगों को निराशा मिली है। भाजपा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली की जनता से जो वायदे किये थे उन्हें पूरा करने की ओर इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई।

श्री हनुमान मंदिर, ब्रह्मपुरी में धूमधाम से मनाया गया बसंतोत्सव

नई दिल्ली, (वीअ)। श्री हनुमान मंदिर (रजि.) समिति,ई-3,गली नंबर 6, ब्रह्मपुरी, दिल्ली में दो दिनी बसंतोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। समिति के प्रधान विजय शर्मा ने बताया कि बसंतोत्सव से पूर्व अखण्ड रामायण पाठ का समापन हुआ। तत्पश्चात हवन यज्ञ कर मां सरस्वती जी की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में श्री हनुमान संकीर्तन, हनुमान बाबा की 5 सवामनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हेमंत अवस्थी चिदू, पंकज उमाकांत गुप्ता, परशुराम रावत, सत्यनारायण बंसल, राहुल कपूर, पं.सचिन शर्मा, भरत कश्यप, अभिषेक तिवारी, भवजित अरोड़ा सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे।

शिकायतें आपकी समाधान हमारा

पाठकों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दैनिक वीर अर्जुन अपने पाठकों की निजी समस्याओं को प्रकाशित करने एवं उनके समाधान की कोशिश करने का प्रयास करेगा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी समस्याएं pandey.virarjunnews@gmail.com अथवा pathakvirarjun@gmail.com पर भेजें ताकि दैनिक वीर अर्जुन आपकी समस्याओं के समाधान में भूमिका निभा सके।

- सम्पादक

बजट 'विकसित भारत' की दिशा में मील का पत्थर : विजेंद्र गुप्ता

कहा-बजट 2026-27 में विश्वास-आधारित शासन और भविष्य-तैयार भारत की झलक है

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए लगातार नौवें केंद्रीय बजट पर उन्हें बधाई देते हुए इसे 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों को सुदृढ़ करने, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने तथा विश्वास-आधारित शासन के माध्यम से अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह बजट उच्च विकास दर को समावेशी विकास के साथ संतुलित करते हुए समाज के सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने अवसरचना क्षेत्र में 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का स्वागत करते हुए कहा कि यह विशाल निवेश आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत भौतिक और डिजिटल आधार तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि अवसरचना पर निरंतर बल से रोजगार सृजन को गति मिलेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

श्री गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री



दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता

श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के दूरदर्शी नेतृत्व और 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के संकल्प को साकार करने की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री का विकास दृष्टिकोण चार प्रमुख दूरदृष्ट-श्रद्ध, किसान, युवा और न्हाह-ब आधारित है और यह बजट अवसरचना, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, मानव पूंजी और सामाजिक सुरक्षा में निरंतर निवेश के माध्यम से इस दृष्टि को ठोस नीतियों में रूपांतरित करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने डीप-टेक और उन्नत विनिर्माण पर रणनीतिक फोकस की सराहना करते हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (एए) 2.0 की शुरुआत तथा खनिज-समृद्ध राज्यों में रेयर अर्थ कारिडोर के विकास को देश की

तकनीकी संभ्रमता को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये पहले भारत को उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करेंगी। एमएसएमई, निर्यात और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर विनिर्माण योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स योजना, बायोफार्मा को प्रोत्साहन तथा कूरियर निर्यात सीमा हटाने जैसे उपायों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारतीय उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ेगा और छोटे उद्योगों व कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलेगी। बजट की जन-हितैषी और गरीब-हितैषी भावना को रेखांकित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि गरीबों, किसानों, पशुपालकों और महिलाओं पर केंद्रित पहले समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने प्रौद्योगिकी-सक्षम कृषि परामर्श सेवाओं के लिए भारत-विस्तार (भारत-व्यूई) कार्यक्रम, मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु जलसाधनों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, पशुपालन में उद्यमिता समर्थन, नारियल मिशन तथा काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों को वैश्विक प्रीमियम मूल्य श्रृंखलाओं के रूप में विकसित करने के प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उच्च शिक्षा के एस्टीमेट संस्थानों में छात्रावासों की स्थापना सहित 'नारी शक्ति' पर विशेष बल की भी सराहना की।

रामनगर के लोगों ने गली के निर्माण में हो रही देरी पर रेखा गुप्ता को लिखा पत्र : नवीन चन्द्रा

नई दिल्ली, (वीर अर्जुन)

रोहताश नगर विधानसभा के तहत पूर्वी रामनगर गुरु नानक स्कूल के पास वाली गली नंबर 16 में एक माह से भी ज्यादा समय पहले गली का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और पूरी गली को तोड़ कर गली बनाने का काम शुरू किया था लेकिन नालियां बनाकर गली निर्माण का काम बीच में ही छोड़ दिया गया है जिसके चलते ना केवल उस गली के बल्कि आसपास की गलियों के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। गली के निवासी नवीन चन्द्रा कहते हैं गली के छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। आलम यह है की तकरीबन रोजाना ही कोई ना कोई गली में गिरता पड़ता रहता है और कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। नवीन चन्द्रा कहते हैं गली में पत्थर तोड़ कर डाले हुए हैं जिसके चलते उनके ऊपर से चलना बहुत परेशान



कर रहा है। नवीन चन्द्रा कहते हैं गली टूटी होने की वजह से लोगो को अपनी कारों व अन्य वाहन दूसरी गलियों में खड़े करने पड़ते हैं। लिहाजा उनकी वजह से दूसरी गली के लोगो को भी परेशानी हो रही है। अपरेशन होकर गली के लोगो में स्थानीय विधायक जितेंद्र

पुलिस द्वारा त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बैठक आयोजित

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। डीसीपी (पूर्व) अभिषेक धनिया, आईपीएस के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-1, पूर्वी जिला, माननीय श्री विनित कुमार, आईपीएस की अध्यक्षता में आने वाले प्रमुख त्योहारों - महाशिवरात्रि, शब-ए-बारात और रमजान - के दौरान शांति, सुरक्षा एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने तथा आतंकवाद-रोधी उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल, डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, मंडावली फाजलपुर, दिल्ली में किया गया।

बैठक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता अमन कमेटी, आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए, विभिन्न सिविक एजेंसियों के प्रतिनिधियों, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एवं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इसके

अतिरिक्त सभी सब-डिवीजन के एसीपी एवं पूर्वी जिला के एसएचओ भी बैठक में उपस्थित रहे। सभी सक्षि सदस्यों एवं प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान त्योहारों के समय कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, संबंद्धनशील क्षेत्रों में सतर्कता तथा संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत सूचना पुलिस को देने पर जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा, सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की।

इस अवसर पर हाल ही में पदोन्नत होकर जॉईंट कमिश्नर, दिल्ली पुलिस नियुक्त किए गए माननीय श्री अभिषेक धनिया, आईपीएस को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-1 पूर्वी जिला श्री विनित कुमार, आईपीएस द्वारा शुभकामना संदेश पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

हर वर्ग के लिए सौगात दी गई है केंद्र के बजट में : मास्टर विनोद

★ युवाओं के लिए नए अवसर लाएगा : बिन्नी वर्मा

नई दिल्ली, (वीर अर्जुन) :

केंद्र सरकार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर किया गया है यह कहना है भारतीय जनता पार्टी नवीन शाहदरा जिले के अध्यक्ष मास्टर विनोद का 'मास्टर विनोद' में जिला कार्यालय में बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मौके पर जिला भाजपा प्रभारी लता गुप्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बिन्नी वर्मा, सहित अनेक पदाधिकारी तथा जिले के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

लता गुप्ता ने कहा कि वित्त मंत्री ने देश की समृद्धि आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बजट को 100 में से 100 नंबर देती हूं। नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने सबसे पहले वित्त मंत्री



मास्टर विनोद

और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों के लिए है जिसमें किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कपड़ा, जूता, और प्रकार के व्यापार को राहत दी गई है। आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। पांच विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है। बिन्नी वर्मा ने कहा भारत बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी



बिन्नी वर्मा

तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है बहुत जल्द भारत मेडिकल हब बनेगा। दवाइयां उपकरण जो हम निर्यात करेंगे, और भारत बहुत जल्द ही टूरिज्म डेवलप होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां पर 22 जल मार्ग जल्द ही डेवलप किए जाएंगे और साथ ही स्प्रीड कॉरिडोर बनेंगे। बिन्नी वर्मा ने कहा यह बजट युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

यह पहला बजट भारत सरकार के जनता के प्रति दायित्वों का निर्वहन करता है : वीरेन्द्र सचदेवा

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के 13वें बजट प्रस्ताव को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी डा. अल्का गुर्जर, प्रदेश महामंत्री श्री विष्णु मिश्र, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर के साथ प्रदेश कार्यालय के सभागार में सुना।

वीरेन्द्र सचदेवा के साथ सभागार में प्रदेश भाजपा बजट समिति सदस्यों प्रवक्ता श्री यासिर जिलानी, मीडिया रिलेशन प्रमुख श्री विष्णु मिश्र, सी.ए. प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री दीनदयाल, आई.टी. सेल अध्यक्ष श्री पुनीत अग्रवाल, दिल्ली भाजपा के आठों मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों और सी.ए. प्रकोष्ठ सदस्यों ने भी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नौवें बजट को टी.वी. पर देखा एवं सुना। बजट सुनने के



दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा

बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की कर्तव्य भवन में बना यह पहला बजट भारत सरकार के जनता के प्रति दायित्वों का निर्वहन करता है। श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की निर्माण उद्योग, पर्यटन, तीर्थस्थल विकास, मेडिकल टूरिज्म विकास को बढ़ावा देता बजट 2026 युवा भारत को नये पंख लागायेगा। वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ते विकास के ध्वजवाहकों निजी बिल्डरों के ऋणों को सुरक्षा कवर देने के

साथ ही भारत सरकार ने तीर्थस्थलों के विकास को पंख लगाये हैं जिन

से निर्माण उद्योग को लाभ होगा और भवन निर्माण बढ़ेगा। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बुजुर्गों की चिकित्सा को बढ़ावा देते इस बजट 2026 में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया जिससे मेडिकल क्षेत्र में हजारों नौकरियों का सृजन होगा। ए.बी.जी.सी. के विकास को बढ़ावा देते बजट से लाखों पेशेवरों को नया उत्साह एवं काम मिलेगा।

राष्ट्रीय हॉटल उद्योग के बढ़ने, तीर्थस्थल विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण से हजारों नौकरियों की सृजित होगी। श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की खेलों एवं खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता यह बजट युवा फ्रेडली है। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इन्कम टैक्स एक्ट स्वागत योग्य।

युवा और व्यापारियों को बजट से हुई घोर निराशा : अजय अरोड़ा

-हर्ष भारद्वाज-

नई दिल्ली, केंद्र के बजट से वैसे तो सभी वर्गों को निराशा ही मिली है। लेकिन व्यापारियों और युवा वर्ग को इस बजट में बेहद निराशा किया है। यह कहना है दिल्ली स्टेट ट्रेडर्स कांग्रेस के चेयरमैन अजय अरोड़ा का। अजय अरोड़ा कहते हैं पिछले साल वित्तमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ, उस बारे में तो जिज्ञा तक नहीं किया गया। बजट से देश के व्यापारियों को कुछ नहीं मिला, खाली डिब्बा और खली बोतल ही साबित हुआ यह बजट। अजय अरोड़ा कहते हैं इसी तरह युवाओं के हाथ भी निराशा ही लगी है। पिछले बजट में युवाओं को रोजगार देने के सपने दिखाए गए थे उसका क्या हुआ देश के किसानों के साथ भी धोखा है यह बजट, प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय डबल कराने देंगे उसका क्या हुआ हमारे रूपये की कीमत लगातार घट रही है वहीं डालर की कीमत बढ़ती जा रही है आज बेरोजगारी चरम पर है, पिछले

★ इस बजट से कोई नई दिशा नहीं दिखती



अजय अरोड़ा

बजट में जो योजनायें बताई गई थी उनका क्या हुआ। अजय अरोड़ा कहते हैं केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई है। ना तो पिछली घोषणाओं पर अमल हुआ और ना ही कोई नई प्रभावशाली घोषणा की गई। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आने वाले वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। अजय अरोड़ा कहते हैं भारतीय

अर्थव्यवस्था में ढांचागत समस्याएं हैं जिन्हें एक दशक से ठीक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हुआ है, फरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है। अजय अरोड़ा कहते हैं सर्वे दावा करते हैं है कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है लेकिन यह प्रति व्यक्ति आय और रोजगार सृजन से मेल नहीं खाता। वह विकास को कैसे बढ़ावा देंगे ताकि नौकरियां पैदा हो सकें। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, जबकि लोगों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। उनके पास पैसा कैसे आएगा और उनकी बचत और निवेश कैसे बढ़ेगा, ताकि वे अपने भविष्य की योजना बना सकें। अजय अरोड़ा ने कहा यह बजट कोर्नामिक सर्वे कहता है कि उच्छेद लगातार बढ़ रही है लेकिन यह प्रति व्यक्ति आय और रोजगार सृजन से मेल नहीं खाता। वह विकास को कैसे बढ़ावा देंगे ताकि

नौकरियां पैदा हो सकें? महंगाई ज्यादा चुभती है क्योंकि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनका खर्च बढ़ रहा है। उनके पास पैसा कैसे आएगा और उनकी बचत और निवेश कैसे बढ़ेगा, ताकि वे अपने भविष्य की योजना बना सकें। अजय अरोड़ा ने कहा यह बजट निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है और इससे किसी बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। और ना ही इस बजट से कोई नई दिशा दिखती है।

एनजीटी ने यमुना में मछली की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों को यमुना नदी में पाई जाने वाली मछलियों की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र की सिफारिशों को शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया है।

अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएसजी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को यमुना नदी के किनारे स्थित शहरी स्थानीय निकायों विकास को कैसे बढ़ावा देंगे ताकि नौकरियां पैदा हो सकें? महंगाई ज्यादा चुभती है क्योंकि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनका खर्च बढ़ रहा है। उनके पास पैसा कैसे आएगा और उनकी बचत और निवेश कैसे बढ़ेगा, ताकि वे अपने भविष्य की योजना बना सकें। अजय अरोड़ा ने कहा यह बजट निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है और इससे किसी बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। और ना ही इस बजट से कोई नई दिशा दिखती है।

आई है। सर्वेक्षण के अनुसार, कतला, रोहू, नयन, पैडिन पब्बा, गोच, चीतल, रंगन टेंगरा, रीठा, बाम या ईल व महाशीर जैसी भारतीय प्रजातियों की मछलियों की संख्या में कमी आई है, जबकि आठ प्रकार की विदेशी प्रजातियों की मछलियों, जैसे- कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, विंग हेड, थाई मांगूर, ग्रास कार्प, तिलापिया, क्रोकोडाइल फिश और बास की संख्या में वृद्धि हुई है और इसने भारतीय प्रजातियों की मछलियों को प्रभावित किया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने 29 जनवरी को अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि भारतीय प्रजातियों की मछलियों की संख्या में गिरावट नदी में प्रदूषण के कारण हुई है।

पीठ ने कहा, ऐसा पाया गया है कि हालांकि विभिन्न एजेंसियों ने यमुना नदी में पाई जाने वाली मछली की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों के बावजूद स्थानीय प्रजाति की मछलियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अधिकरण ने

स्थानीय सरकारों द्वारा अनुपालन के लिए आईसीएआर-सीआईएफआरआई, प्रयागराज की सिफारिशों पर ध्यान दिया। इनमें अवैध मछली पकड़ने के उपकरणों पर प्रतिबंध, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान बेहतर निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण, रणनीतिक मछली पालन प्रथाओं को लागू करना, निर्दिष्ट क्षेत्रों में श्वस लेने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करने वाली मछलियों का पालन-पोषण करना और मछली पकड़ने के आंकड़ों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल था। इन सिफारिशों में परटे पर दिए गए क्षेत्रों में मछली पालन के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना, अनुष्ठानों के लिए विदेशी मछलियों को छोड़ने पर प्रतिबंध लगाना, जन जागरूकता बढ़ाना, पानी का निरंतर प्रवाह बनाए रखना और जैव विविधता की रक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए औद्योगिक और जैविक अपशिष्टों के प्रोत् प्रबंधन के लिए कार्रवाई करना भी शामिल था।

अधिकरण ने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सुझावों पर विधिवत विचार करने और उन्हें शीघ्रता से लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया।

ठंड-कोहरे के साथ स्मॉग का कहर, साफ नहीं हुई है अभी भी हवा शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है

-रविंद्र कुमार-

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण और ठंड के दोहरे संकट में फंस गई है। शहर के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा और स्मॉग छाया हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालात ऐसे हैं कि सुबह और शाम घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि धूप भी खिल रही है बावजूद इसके ठंडी हवाएं परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार शीत लहर और हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषित कण वातावरण में जमा हो गए हैं। इससे दिल्ली-एनसीआर में धुंध और धुएं की मोटी परत छा गई है। सड़कों पर दृश्यता घटने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई इलाकों में ट्रैफिक



डॉ. तरुण कुमार

की रफ्तार धम सी गई है। प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। सरकारी अस्पतालों में खांसी, दमा, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक इस जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़ों को भारी नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है ऐसे में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण ने भी लोगों का बुरा हाल किया हुआ है। स्वामी दयानंद अस्पताल के चीफ

मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तरुण कुमार ने एहतियात के तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय व सांस के मरीजों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। सुबह की सैर पर निकलने वालों को भी फिलहाल बाहर न निकलने को कहा गया है। डॉक्टर तरुण कुमार का कहना है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क का प्रयोग करें। ट्रैफिक विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों तक हालात में खास सुधार की संभावना नहीं है। यदि तेज हवा चलती है या मौसम में बदलाव आता है तो ही प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल राजधानी वासियों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की जरूरत है।

बजट विकसित भारत की ओर मजबूत कदम : मनोज जैन

नई दिल्ली, (वीर अर्जुन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट विकसित भारत के संकल्प को नई गति देता है। यह कहना है मनोनीत निगम पार्षद मनोज कुमार जैन का। श्री जैन कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। एएमएस को बढ़ावा, 17 कैसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त, हाई स्पीड रेल और किसानों युवाओं के लिए नई योजनायें भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जायेंगी। मनोज कुमार जैन ने केंद्रीय बजट को युवा शक्ति, सुधार और राष्ट्र निर्माण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जन-आकांक्षाओं की स्पष्ट झलक है। खेलों, इंडिया मिशन, स्किल डेवलपमेंट, लेब्स और रोजगार से



मनोज कुमार जैन

जुड़े प्रबंधनों को युवाओं के भविष्य के लिए गेमचेंजर साबित होगा यह बजट। यह बजट भारत को वैश्विक इनोवेशन और फिटिडव इकोनॉमी का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

मंगोलपुर खुर्द में टैक्स व नगर निगम मुद्दों को लेकर हुई पंचायत

★ बजट में प्रस्तावों पर जताया आभार, गांवों को पूर्ण राहत की मांग

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। मंगोलपुर खुर्द गांव में आज हाउस टैक्स से नगर निगम से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता बिजेन्द्र पहलवान ने की। पंचायत में दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव, पालम 360 गांव खाप के अध्यक्ष रामकुमार सोलंकी, साइकिल संस्था के अध्यक्ष पारस त्यागी, युवा सभा दिल्ली 360 गांव अध्यक्ष विजयमान, मंगोलपुर खुर्द गांव के गौरव शौकीन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पंचायत में दिल्ली के लगभग 25 गांवों के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इनमें हरेजान (सुल्तानपुर), संजय शौकीन (पुठकला), मंगोलपुर बालकिशन, रविंदर शौकीन सहित अन्य गांवों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस अवसर पर दिल्ली



पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने पंचायत को अवगत कराया कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा द्वारा आगामी बजट में गांवों के 200 वर्ग मीटर (ढाई सौ गज) तक के आवासीय प्लॉट का हाउस टैक्स से मुक्त रखने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही इस श्रेणी के प्लॉट पर केवल व्यावसायिक एरिया पर ही हाउस टैक्स लगाने तथा भवन उपनियमों में गांवों को राहत देने की पहल का प्रस्ताव रखने पर पंचायत ने इस सकारात्मक पहल का सर्वसम्मति से स्वागत करते हुए

आभार व्यक्त किया। पंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मांग की गई कि वैल्यूएशन कमेटी में दिल्ली देहात के गांवों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। साथ ही गांवों को हाउस टैक्स, पार्किंग चार्ज, कर्बज चार्ज एवं अन्य सभी प्रकार के टैक्सों से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए। पंचायत ने यह भी मांग की कि गांवों को रोजगार सृजन के उद्देश्य से व्यावसायिक श्रेणी में रखा जाए, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

सुधार का संकल्प

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना नौवां बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार के उद्देश्य से 'लोगों का' बजट पेश किया है किन्तु स्पष्ट रूप से यह लोकप्रियता या लोकलुभावन बजट बिल्कुल नहीं है।

दरअसल इस बजट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आतंक की छाया तो है ही साथ ही अभी तक यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन एवं दूसरे देशों के साथ हुए और होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर आर्थिक पटरी को मजबूत करने की कोशिश की गई है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कमी आने के कारण भी सरकार को बजट में लीक से हटकर प्रावधान करने की जरूरत पड़ी। इसलिए सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने, सहभागिता बढ़ाने, क्रय की क्षमता बढ़ाने, वित्तीय क्षेत्र में लचीलापन लाने की जो कोशिश की है उसे वित्त मंत्री से 'विकास एक्सप्रेस' कहलवाया है। सरकार ने 2025 के वित्त वर्ष के दौरान ही जीएसटी में भारी कटौती करके उपभोक्ताओं को राहत दिया था ताकि ट्रंप टैरिफ के कारण बाजार को मंदी से न जूझना पड़े। यही कारण है कि अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पाद के महंगा होने के बावजूद भारत में उत्पादकता बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। बजट में टेक्सटाइल इकोसिस्टम को विकसित एवं मजबूत करने के लिए ही सरकार ने बुनकरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी हैण्डलूम योजना में पूंजीगत सहायता योजना का एलान करके न सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा दिया बल्कि छोटे स्तर पर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराने की कोशिश की है।

एमएसएमडी के बिना इतनी विशाल जनसंख्या को रोजगार दे पाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करके कि विकास का वाहन कुटीर उद्योग ही बन सकता है, बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने की पहल भी एमएसएमडी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल है।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि वह बजट के माध्यम से आर्थिक प्रोथ, सबकी उम्मीदों को पूरा करने और सबका साथ व सबका विकास करे इसलिए सरकार ने तटीय क्षेत्र में नारियल, काजू, चंदन की लकड़ी के पेड़ों को बढ़ाने के लिए उसकी खेती के प्रोत्साहन पर बल दिया है। इस खेती से कृषि क्षेत्र में जबरदस्त आर्थिक विकास दर में उछाल की उम्मीद है।

सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में कैसर एवं शुगर जैसी सात गंधीर बीमारी की दवाओं को सस्ता तथा टैस्टिंग सुविधा में विस्तार करके अपने सामाजिक दायित्वों का एहसास कराया है। एक जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था में बुजुर्गों, कमजोर आर्थिक वर्ग, महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार को इस तरह के प्रावधान करने ही होते हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ा प्रावधान जैसा तो कुछ नहीं किया है किन्तु निजी विश्वविद्यालयों के खोलने में मदद करने की बात जरूर कही है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20 पर्यटन स्थलों को चुना है जिसमें 10 हजार गाइड प्रशिक्षित किए जाएंगे। लेकिन बौद्ध सर्किट के माध्यम से मणिपुर से मिजोरम तक जो बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव किया है उससे भारत में चीन, जापान, कोरिया एवं आसियान देशों के पर्यटकों का भारत आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस विदेशी मुद्रा की आवक भी बढ़ेगी।

सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब को तो नहीं बढ़ाया किन्तु करदाताओं को राहत देते हुए इतना जरूर किया कि आर्थिक दंड भुगतान करके जेल जाने से छूट हासिल कर सकते हैं। सरकार ने बजट भाषण के दौरान इस बात का एलान किया कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू कर दिया जाएगा। इसी तरह बजट में प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक विदेश में अपनी संपत्ति की घोषणा करके आनुपूर्विक कार्रवाई से बच सकते हैं बशर्ते उन्हें 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। सरकार ने वित्तीय घाटे के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में जो 4.5 प्रतिशत का वादा किया था उसे पूरे वित्तीय वर्ष में वित्तीय अनुशासन के माध्यम से पूरा कर लिया और वर्ष 2026-2027 के बजट में 4.3 प्रतिशत वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हासिल करने के संकल्प में आत्मविश्वास भी दिखाता है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार करदाताओं को परेशानी से बचाने के लिए जो प्रावधान लाई है, उसका सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है।

इस बात से सरकार निश्चित दिखती है कि 7 प्रतिशत प्रोथ रेट 4.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति वाली तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इस वक्त चौथे स्थान पर पहुंच कर वैश्विक बाजार में परचम लहराना चाहती है। यही कारण है कि रणनीतिक विनिर्माण और सैन्य बजट में बढ़ोत्तरी की गई है। पिछले बजट में 6.81 लाख करोड़ था जो इस बार 7.8 लाख करोड़ हो गया है। जरूरत के मुताबिक यह पर्याप्त नहीं है। रेलवे व 7 हाईस्पीड कारीडोर और शिप निर्माण कारखाने के जरिए द्वांचागत विकास की बात तो की गई है किन्तु मुफ्त रेवडिया की घोषणा से बचा गया है। इसी से लगता है कि सरकार पहले से ही चल रही तमाम योजनाओं की चुनौतियों से कैसे निपट रही है।

लम्बोल्डआव यह है कि मोदी सरकार का यह बजट आर्थिक सुधारों के लिए ही जाना जाएगा जिसकी सामान्य जनता आलोचना और आर्थिक मामलों के जानकार प्रशंसा करेंगे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बजट के आलोचकों की संख्या ज्यादा और समर्थकों की कम होगी। कुल मिलाकर सरकार की आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कोल कांटे फिट करने का संकल्प है।

newsdesk@virarjun.com



चिड्डी आई है

बजट 2026 आम आदमी की उम्मीदें और सरकार की प्राथमिकताएं

केंद्रीय बजट 2026 ऐसे समय में आया है जब देश की अर्थव्यवस्था स्थिर विकास की राह पर है लेकिन आम आदमी महंगाई रोजगार और आय के दबाव को रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार महसूस कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट निरंतरता और भविष्य निर्माण के नरिये से पेश किया है। इसमें बड़े द्वांचागत निवेश स्वास्थ्य शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर जोर है लेकिन सवाल यही है कि इस बजट से आम आदमी की जेब को कितनी राहत मिलती है और उद्योग धंधों के लिए

यह कितना अनुकूल है। सबसे पहले आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद यानी इनकम टैक्स की बात करें तो बजट ने यहां निराशा किया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। महंगाई बढ़ने के बावजूद टैक्स में राहत न मिलना मध्यम वर्ग और नौकरपेशा लोगों के लिए झटका है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च करना एक प्रशासनिक सहूलियत है लेकिन इससे जेब में पैसा बढ़ने जैसा सीधा फायदा नहीं होता। न्यू इनकम टैक्स एक्ट को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने और फॉर्म को सरल बनाने की घोषणा जरूर की गई है जिससे भविष्य में टैक्स सिस्टम आसान हो सकता है लेकिन फिलहाल आम आदमी को इससे तत्काल राहत नहीं मिलेगी। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को खास महत्व दिया गया है। कैसर की 17 दवाओं और कुछ दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्रग्टी से मुक्त करना एक बड़ा मानवीय कदम है। इससे गंधीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

—कांतिलाल मांडोट, सूरत, गुजरात।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट: थाई पूसम की तीक्ष्णता और माघ पूर्णिमा की पूर्णता का अनूठा संगम



डॉ. प्रदीप कुमार केशरी

राजनीति और अर्थशास्त्र के गलियारों में प्रायः आंकड़ों का कोलाहल गुंजाता है, किंतु रविवार, 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 केवल संख्याओं का दस्तावेज नहीं रहा। यह समय, संस्कृति और नीति के एक दुर्लभ संगम का साक्ष्य बना।

यह दिन भारत की सभ्यतागत धड़कनों के उत्तर-दक्षिण संवाद का प्रतीक था। दक्षिण भारत में यह थाई पूसम का पावन पर्व था- भगवान मुरुगन की विजय, ज्ञान और साहस का उत्सव-तो उत्तर भारत में माघ पूर्णिमा-कल्पवास की पूर्णता, दान और चंद्रमा की शीतल करुणा का दिन।

दोहरे अंकों की वृद्धि की आकांक्षा रखने वाले भारत के सामने मदुरै की बेटी ने एक सात्विक, संपूर्ण और विचारपूर्ण आर्थिक थाली परोसी है। अब असली परीक्षा इस प्रश्न में निहित है- क्या हमारी कार्यान्वयन प्रणाली इसे पचा पाने के लिए तैयार है?

मदुरै की सांस्कृतिक मिट्टी से जुड़ी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह केवल एक तिथिगत संयोग नहीं था। जैसे माता पार्वती ने भगवान मुरुगन को अधर्म और अज्ञान के विनाश हेतु 'वेल' (भाला) प्रदान किया था, उसी प्रतीकात्मक शक्ति के साथ यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ बाधाओं को भेदने वाला नीतिगत वेल और विकास को पोषण देने वाला आर्थिक अमृत बनकर सामने आया।

अपने भाषण में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया "यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं है। जिस प्रकार 'वेल' बाधाओं को भेदता है और 'पूर्णमा' पूर्णता का बोध कराती है, उसी प्रकार हमारा उद्देश्य नियमों की जटिलता को समाप्त कर

उत्पादकता को पोषित करना है।" 'वेल' की रणनीति: सुधारों की धार, बाधाओं का संहार उद्योग जगत और करदाताओं के लिए बजट का 'वेल' प्रत्यक्ष कर संहिता 2026 के रूप में सामने आया। छह दशकों से अधिक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को समाप्त करने की घोषणा यह संकेत देती है कि विकास अब मुकदमों और अस्पष्टताओं के बोझ तले नहीं पनपेगा।

एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के शब्दों में, "यह बजट प्रशासनिक जड़ता पर सीधा प्रहार है। 350 से अधिक पुराने प्रावधानों को हटाकर कर व्यवस्था को विवाद-मुक्त बनाना वास्तव में नौकरशाही पर 'वेल' चलाने जैसा है।"

इसी क्रम में सरकार ने 'निर्विघ्न मिशन' की घोषणा की- एक एकल-खिड़की डिजिटल स्वीकृति प्रणाली, जिसका उद्देश्य औद्योगिक अनुमोदनों में लगने वाले महीनों को मिनटों में बदलना है। यह थाई पूसम की उस भावना का आधुनिक रूप है, जिसमें भक्त जीवन की बाधाओं से मुक्ति की कामना करता है-यहां उद्यमी को लालफीताशाही से मुक्ति दी गई है।

'माघ पूर्णिमा' का प्रसाद: जड़ों का पोषण यदि 'वेल' कार्रपोरेट और निवेश जगत के लिए था, तो पूर्णिमा का सौम्य प्रकाश किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आरक्षित था। माघ पूर्णिमा को

दान, संतुलन और पोषण का पर्व माना जाता है। बजट ने भी सब्सिडी-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर स्थायी पोषण का मार्ग चुना।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा भारत-विस्तार एआई-आधारित कृषि सलाह मंच, जो 12 करोड़ किसानों को उनकी स्थानीय भाषाओं में मौसम, मिट्टी और बाजार की सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा।

वित्त मंत्री के शब्दों में, "अब हम केवल पौधे को पानी नहीं दे रहे, बल्कि मिट्टी को पोषित कर रहे हैं। असली समावेशी विकास तब है जब छोटे किसान के हाथ में भी वही ज्ञान और तकनीक हो जो बड़े एग्री-बिजनेस के पास है।"

इसके साथ ही 'अन्नपूर्णा बायो-ग्रिड' का प्रस्ताव रखा गया-शीत गृहों और खाद्य प्रसंस्करण का विकेंद्रीकृत नेटवर्क, ताकि फसल बाजार तक पहुंचने से पहले नष्ट न हो। यह माघ पूर्णिमा की प्रचुरता और अन्नदान की भावना का नीतिगत अनुवाद है।

'सप्तऋषि' संतुलन: बुनियादी ढांचा, उद्योग और हरित ऊर्जा 'पोषक विकास' का यह दर्शन केवल कृषि तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने बुनियादी ढांचे की अर्थव्यवस्था का प्रगतिमान मानते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.5 लाख करोड़ कर दिया। **इस रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं:**

एमएसएमडी 'उद्योग शक्ति' कोष: 15,000 करोड़ का विशेष फंड, जो सूक्ष्म इकाइयों को मध्यम उद्यम बनने में सहायता देगा।

बायोफार्मा संप्रभुता मिशन: भारत को बायोलाजिक्स और एपीआई का वैश्विक केंद्र बनाने की पहल।

हरित ऊर्जा कॉरिडोर: दक्षिण भारत की सौर-पवन क्षमता को उत्तर भारत के औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने की योजना-आर्थिक के साथ-साथ सांस्कृतिक एकीकरण का भी प्रतीक।

सांस्कृतिक कूटनीति का सूक्ष्म संदेश

रविवार को बजट प्रस्तुति पर उठे राजनीतिक प्रश्न तिथि के सांस्कृतिक महत्व के आगे फीके पड़ गए। थाई पूसम (तमिलनाडु) और माघ पूर्णिमा (उत्तर भारत) के प्रतीकों को एक साथ पिरोकर वित्त मंत्री ने उत्तर-दक्षिण के कथित विभाजन पर एक सभ्यतागत संतु निर्मित किया।

संसद के केंद्रीय कक्ष में एक विपक्षी सांसद ने अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया, "यह सांपट पावर की राजनीति थी-तमिल सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान और माघ स्नान की पवित्रता, दोनों को साथ साधने की कोशिश।"

बजट 2026: मुख्य अंश (प्रसाद)

प्रत्यक्ष कर संहिता 2026: आयकर अधिनियम 1961 का अंत भारत-विस्तार : एआई-आधारित कृषि सलाह

निर्विघ्न मिशन: सिंगल विंडो औद्योगिक स्वीकृति **पूंजीगत व्यय: 12.5 लाख करोड़**

उद्योग शक्ति कोष: एमएसएमडी के लिए विशेष ऋण्डिट समर्थन

निष्कर्ष: एक संपूर्ण थाली रायसीना हिल्स पर सूर्यास्त और माघ पूर्णिमा के चंद्र उदय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि बजट 2026-27 कोई तात्कालिक 'रेवड्डी' बजट नहीं है। यह एक पोषक, संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टि वाला दस्तावेज जिसमें बुनियादी ढांचे का प्रगति, डिजिटल सुधारों के विटामिन और अनावश्यक नियमों की वधा से मुक्ति है। दोहरे अंकों की वृद्धि की आकांक्षा रखने वाले भारत के सामने मदुरै की बेटी ने एक सात्विक, संपूर्ण और विचारपूर्ण आर्थिक थाली परोसी है। अब असली परीक्षा इस प्रश्न में निहित है- क्या हमारी कार्यान्वयन प्रणाली इसे पचा पाने के लिए तैयार है?

(लेखक : जेएनयू से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त विद्वान लेखक और विचारक हैं। उनका लेखन भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं पर केंद्रित है। वैकिंग क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों के अनुभव के साथ वे आईडीबीआई बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद से सेवा निवृत्त हुए हैं।)

बजट 2026: कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहन, वित्त मंत्री की दूरदर्शी पहल



विवेक शुक्ला

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को पेश किया गया। इस बजट में आर्थिक विकास,क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबका विकास पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज या 'अर्रिज इकोनॉमी'को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जो कंटेंट क्रिएटर्स को सीधे लाभ पहुंचाएंगी। अर्रिज इकोनॉमी का मतलब क्रिएटिव सेक्टर से है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स,गेमिंग, कॉमिक्स (AVGC) और डिजिटल कंटेंट शामिल हैं।

अर्रिज इकोनॉमी का महत्व और बजट में इसका स्थान : अर्रिज इकोनॉमी वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। भारत में यह सेक्टर न केवल रोजगार सृजन कर रहा है बल्कि सांस्कृतिक निर्यात को भी बढ़ावा दे रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा किउपडिस्ट्री को 2030 तक लगभग 20 लाख प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए,सरकार ने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा देने का फैसला किया है। यह पहल युवाओं को डिजिटल स्किल्स से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।

दिल्ली-एनसीआर के युवा वैज्ञानिक श्रेयांस जैन कहते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में नई रिसर्च करने वाले तमाम उत्साही युवाओं और अन्य लोगों को तोहफा दिया है। सरकारी सहयोग के अभाव में बहुत सारे लोगों के रिसर्च प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पर अब यह नहीं होगा। सेलेस्टियल एयरोस्पेस लसेस योरोनॉमिक बैलून-सहायता प्राप्त रॉकेट लॉन्च सिस्टम विकसित कर रहे हैं। इस तकनीक में एक बड़ा बैलून रॉकेट को ऊपरी वायुमंडल तक ले जाता है,जहां हवा पतली होती है और प्रतिरोध कम। वहां से रॉकेट प्रज्वलित होता है,जिससे ईंधन की बचत होती है और पेलोड क्षमता 2-3 गुना बढ़ जाती है। बजट में अर्रिज इकोनॉमी को फिएटिव जॉब्स का नया इंजन'कहा गया है। यह सेक्टर सेवाओं पर आधारित विकास को बढ़ावा देगा। पहले से ही भारत के फिएटिव सेक्टर में स्टार्टअप और ऑब्स की बढ़ा आ रही है,लेकिन स्किल गैप एक बड़ी चुनौती है। बजट इस गैप को भरने के लिए ठोस कदम उठाता है,जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लैब स्थापित करना। इससे कंटेंट क्रिएटर्स को स्कूल और कॉलेज स्तर से ही ट्रेनिंग मिलेगी,जो उन्हें प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटी के लिए तैयार करेगा। बजट की सबसे प्रमुख घोषणा है मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) को सपोर्ट देकर कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित

करना। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये लैब्स सेट अप किए जाएंगे। ये लैब्स छात्रों को एनिमेशन,विजुअल इफेक्ट्स,गेमिंग और कॉमिक्स बनाने की ट्रेनिंग देगे। ये लैब्स क्यों महत्वपूर्ण हैं?श्रेयांस जैन कहते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों कमाते हैं। लेकिन कई युवाओं को प्रोफेशनल टूल्स और ट्रेनिंग की कमी होती है। ये लैब्स वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और (एक्सटेंडेड रियलिटी) जैसी सारसूट स्तर पर टैलेंट को निहारेंगी,जिससे भारत का फिएटिव वर्कफोर्स मजबूत होगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गेम डेवलपर्स,आर्टिस्ट्स और स्टोरीटेलर्स की नई पीढ़ी तैयार होगी,जो भारतीय आईपी (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) पर आधारित कंटेंट बनाएंगी। इसके अलावा,बजट में ईस्टर्न रिजन में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देगा,जहां कंटेंट क्रिएटर्स विजुअल डिजाइनिंग सीख सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण पहल है डिजिटल नॉलेज ग्रिड का निर्माण,जो भारत को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संपत्तियों को डिजिटली डॉक्यूमेंट करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे हिस्टोरियंस,रिसर्चर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए जॉब्स बनेंगे। यह ग्रिड एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा,जहां कंटेंट क्रिएटर्स भारतीय हेरिटेज पर आधारित वीडियोज, डॉक्यूमेंट्रीज और डिजिटल कंटेंट बना सकेंगे।

यह पहल क्यों प्रोत्साहनकारी है? कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर ऑर्थेंटिक सोर्स की तलाश में रहते हैं। डिजिटल नॉलेज ग्रिड उन्हें हार्ड-क्वालिटी डेटा प्रदान करेगा,जिससे वे एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट बना सकेंगे। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा,क्योंकि 20 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को अपस्किल करने का पायलट प्रोग्राम शुरू होगा। कंटेंट क्रिएटर्स इन डेस्टिनेशंस पर वीडियोज बनाकर मोनेटाइज कर सकेंगे। बजट में क्रिएटिव सेक्टर के लिए अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन भी है।

इस बाबत 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं,जो क्रिएटिव स्टार्टअप को फंडिंग देगा। साथ ही, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए 100 करोड़ का इंसेंटिव बंडे शहरो में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में मदद करेगा,जो क्रिएटिव हब्स विकसित कर सकता है।दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो. प्रभांशु ओझा कहते हैं कि निर्मला सीतारमण का बजट कंटेंट क्रिएटर्स को एजुकेशन,स्किलिंग और जॉब फिएशन के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। येलेब्स और डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसी पहलें भारत को क्रिएटिव सुपरपावर बनाने की दिशा में कदम हैं। यह बजट युवा-केंद्रित है,जो विकसित भारत के विजन को मजबूत करता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)



डॉ. रवीन्द्र अरजिया

कलह का शंखनाद हो उठा। नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भी इसी तरह से सरकार का तख्ता पलट करवाने की सफल कोशिशों की जा चुकी हैं। देश के मीरजाफरों को चिन्तित करके उन्हें भौतिक सुविधाओं, संसाधनों और उज्ज्वल भविष्य की मुगुलगा के पीछे दौड़ा जाता रहा है। इस सोच से जकड़े लोग अब मीरजाफर की तात्कालिक घटनाओं और उनकी कष्टप्रद परिणति को नजरंदाज करके अपने आकाओं की गुलामी करने में ही अपना, परिवार का और स्वजनों का भला देखने लगे हैं।

इन भितरघाती मीरजाफरों की संख्या में निरंतर इजाफा होता जा रहा है। विदेशी खुफिया एजेंसियों से लेकर डीपस्टेट के संचालकों तक ने भारत के कोने-कोने में अपने स्लीपर सेल तैयार कर रखे हैं। अभी तक विपक्ष के लोगों पर ही मीरजाफर होने के आरोप लगते रहे हैं परन्तु इस बार तो सत्ता पक्ष के भितरघातियों ने ही अपने गोरे आकाओं के इशारे पर देश का वातावरण रक्तंरजित करने हेतु आधार तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालातों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के अन्दर सभी प्रमुख क्षेत्रों में भितरघातियों को एक बड़ी संख्या मौजूद है जो अवसर मिलते ही राष्ट्र को गुलामी की वेडियों में जकड़ने हेतु कामया जा रहे सीमापार के षडयंत्रों को अमली जामा पहनाने में जुट जाते हैं।

विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहे देश को आन्तरिक संघर्ष की आग में झोंकने हेतु जातिगत मुद्दे की आंधी चलाई गयी। उच्च शिक्षा में समानता लाने के दांत दिखाकर हाथों ने अन्दर के षडयंत्रकारी दांतों से देश को चबाने की शुरुआत कर दी है जिसे फिलहाल न्यायालय ने टाल दिया है मगर वह समाप्त नहीं हुआ है। इधर खाई उधर कुआ जैसी स्थिति सुरसा का मुंह बनकर जस की तस खड़ी है। शकाओं को बादल रिकुंज कर रहे हैं। शक्ति संकलन के प्रयास किये जा रहे हैं। जोर आजमाइस के दावपंचों के प्रशिक्षण निरंतर चल रहे हैं। आतंक की नई परिभाषायें गढ़ी जा रही हैं। हकीकत तो यह है कि पड़ोसी देशों की तर्ज पर जैन-जी को मोहरा बनाकर भारत की तेजी से बढ़ती साख को तार-तार करने वाले अब इशा अल्लाह के नारे नहीं लगवा रहे हैं बल्कि राम-राम और राधे-राधे में भेद पैदा करवाने के बाद भगवान और भीम के बीच खाई तैयार करने में जुट गये हैं। साम्प्रदायिक मुद्दे पर लड़े गये बिहार चुनाव के परिणामों को देखते हुए निकट भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए जातिगत मुद्दों को हवा देने का काम शुरू हो गया है ताकि बंटेंगे

तो कटेंगे, जैसे नारों को निक्किय किया जा सके। जातिगत संघटनों को सफिय करके वंशवाद की निष्ठा को तीव्रतम करने की कोशिशें होने लगी हैं। सघर्ष बनाम अन्य की स्थितियां पैदा की गईं। दूसरी ओर प्रयागराज में कथित शंकराचार्य और वहां पर तैनात कुछ खास अधिकारियों के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा करवाकर एक नयी समस्या को जन्म दे दिया गया ताकि सनातन

परम्परा, हिन्दू व्यवस्था और शाश्वत दर्शन को अपभ्रंश की गई किताबों के माध्यम से एक बार पुनः विकृत किया जा सके। हालात यहां तक पहुंच गये हैं कि चौराहों से लेकर चौपालों तक केवल और केवल सनातन के स्वरूप, उसके सिद्धान्त और वर्तमान मान्यताओं पर ही चर्चा होने लगी है। सनातन परम्परा के अनुयायियों को ही विभक्त करके भाई-भाई के आपसी युद्ध हेतु रणभूमि तैयार की जा रही है। वास्तविकता के अनजान लोगों को कथित धर्माचार्यों द्वारा जाति के महात्व, रक्त के वंशसूत्र और मृत्यु के उपरान्त के परिणामों की मनमानी व्याख्याओं से बरगलाया जा रहा है। व्यक्तिगत प्रतिभा के आधार पर निर्धारित की गई वर्ण व्यवस्था को हाथिपर पर पहुंचाकर जन्म के आधार पर नये समाज की रचना करने वाले चन्द चालाक लोगों ने हजारों साल पहले समसामयिक परिस्थितियों में विष पौध का रोपण किया था जो आज जहरीली बाढ़ बनकर अपने ही खेत को खाने की तैयारी में है। पैत्रिक विरासत में मिले हुनर को तुच्छ मानकर चाकरी की ओर अंधी दौड़ लगाने वालों को सरकारी गुलामी के बदलते स्वरूप ने खासा आकर्षित किया है। लोक सेवकों के रूप में नियुक्त लोगों ने स्वयं को शासक घोषित कर लिया है जिसके फलस्वरूप चाकरी, गुलामी और बंधनकारी सेवा का मासूम चेहरा अब शासन, मनमानी और निरंकुशता की कठोरता में परिवर्तित हो चुका है। अयोग्य, अकर्मण्य और अलाल लोगों की नियत अब सरकारी सेवा का मेवा खाने और सेवा के बाद भी मृत्यु के अन्तिम क्षणों तक करदाताओं की कमाई पर ऐश करने की हो चुकी है। इसमें अन्वद भी है जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता परन्तु उनकी संख्या इतनी कम है कि उनको दूंदना असम्भव नहीं तो बेहद कठिन अवश्य है। जातिगत खाई गहराने में राजनैतिक दलों का भरपूर योगदान रहा है जिसे जातिगत संघटनों ने अपनी कठूरता से सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दलों के अन्दर भी जातिगत मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। पक्षपात का नये युग शुरू हो चुका है।

चारों ओर परिवारवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे दवानल मुंह फाड़े खड़े हैं। ऐसे में आवश्यक है जातिविहीन समाज की नवीन संरचना। धरातल पर यह हो भी रहा है। पंडित शूस्ट्रो, अहिंसावादी भोजनालय, खान सब्जी मर्चेन्ट, कुशवाहा जनरल स्टोर, सिंह रेस्टोरेन्ट जैसे बोर्ड बाजारों में लगे देखे जा सकते हैं।

बीसवीं शताब्दी में विचार हान्ति अभियान के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने जातिगत विषेद समाप्त करके समस्त सनातनियों को वैदिक कर्मकाण्ड कराने का अधिकार दिया था। जातिगत और लिंगगत विभाजन को तिलांजलि देकर गायत्री परिवार ने हमेशा ही कथित शोषित जातियों तथा महिलाओं को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जिनके निर्देशन में सामान्य जातियों ने वैदिक कर्मकाण्ड सम्पन्न किये। योग्यता को पुरस्कार, अभावग्रस्तों को सुविधाएं और सभी को समान अवसर प्रदान किये बिना न तो देश का विकास सम्भव है और न ही सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण। इस हेतु आम आबाम को विचार हान्ति अभियान जैसे सूत्रों को जीवन में उतारना होगा और बदलना हांकी तुच्छ मानसिकता, संकीर्ण सोच और सिद्धान्तविहीन आकांक्षाएं।

थरूर का वित्त मंत्री पर तंज

विशेष प्रतिनिधि
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर क्रिकेट शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष किया कि वह गेंद खेलने से चूक गई और स्टंप हो गई। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि सीतारमण के बजट भाषण में विशेष बातें कम थीं और इसमें समग्र दृष्टिकोण का पूरी तरह अभाव था। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि इस बजट में खुश होने लायक कुछ भी नहीं है। थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न अब भी रोजगार का है, और बजट भाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि रोजगार कैसे पैदा किया



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर बजट पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए।

(एएनआई) जाएगा। जब थरूर से पूछा गया कि क्या वित्त मंत्री ने शानदार शॉट लगाया है या पूरी तरह से चूक गई और स्टंप हो गई, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वह स्टंप हुई है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गेंद चूक गई है। एक-दो

जगहों पर बल्ले का किनारा लगा हो सकता है, लेकिन मुझे अभी तक यह पक्का नहीं लग रहा है कि बल्ले के बीच से कोई शॉट लगा हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, बड़े मुद्दों पर, हमें बजट में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिला। राज्यों के लिए भी कुछ नहीं था। वास्तव में, राजकोषीय विकेंद्रीकरण 41 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है, और कई राज्यों ने शिकायत की है कि उनके पास अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रमुख पहलुओं, जैसे कि क्या स्थापित किया जाएगा और कहा, के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

बजट में भारत के वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई : राहुल

वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बजट घट रही है, किसान संकट में है, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि



लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में बजट पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए।

पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने साथ ही देश में बुनियादी

बजट विकास उन्मुखी, विपक्षी दल इस राजनीति पर नहीं करें : रीजीजू

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट विकास और प्रगति पर केंद्रित है। उन्होंने इसपर राजनीति करने के लिये विपक्षी दलों की आलोचना की। विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट की आलोचना की। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से निराशाजनक बताया और आरोप लगाया कि पूर्व में जैसा दावा किया गया था, वास्तविकता इसके विपरीत है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है रीजीजू ने विपक्षी दलों द्वारा बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं

बजट विकास उन्मुखी, विपक्षी दल इस राजनीति पर नहीं करें : रीजीजू

होने का दावा किये जाने पर कहा, सभी प्रावधान केवल आम लोगों के लिए ही किए गए हैं। अगर विपक्ष के लोग खुद को आम लोग नहीं मानते, तो हम क्या कर सकते हैं? मंत्री ने रेखांकित किया कि वित्तवर्ष 2026-27 का बजट विकास और प्रगति पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, देश खुश है। मेरा मानना है कि इस बजट की आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी, अगर कोई इसकी आलोचना करता है, तो वह राजनीति से प्रेरित होगा। रीजीजू ने कहा, मैं

यह बजट आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा: अमित शाह

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रविवार को पेश किया गया बजट भारत को वैश्विक मंच पर पारंपरिक से लेकर नये दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा। शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, विनिर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट एक ऐसा बजट है जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के सपनों को सशक्त बनाता है, ताकि वे उन

यह बजट आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा: अमित शाह

सपनों को साकार कर सकें। सरकार द्वारा राजकोषीय विवेक के साथ विकास और प्रगति को गति देने की प्रतिबद्धता पर जबर्दस्त तरीके से मुहर लगाये जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए शाह ने कहा कि बजट राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लक्ष्य को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को परिकल्पना और अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप पेश करता है। उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि

यह बजट आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा: अमित शाह

आत्मनिर्भर और विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। यह बजट न केवल हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, जो हर कदम पर इसका समर्थन करेगा। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का दृष्टिकोण है, जो विश्व के हर क्षेत्र में अग्रणी हो। गृह मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में योजना शुरू करने का एक ऐतिहासिक निर्णय बजट प्रस्ताव में लिया गया है।

यह बजट आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा: अमित शाह

संपन्न हो जाता है कि बजट को लेकर जो उम्मीदें की गई थीं, उन पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता। यह पूरी तरह फीका और निराशाजनक रहा। उन्होंने दावा किया, भाषण भी पारदर्शी नहीं था, क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई।

बजट में विकसित भारत की यात्रा के केंद्र में रखा गया है अवसरचना को : गडकरी

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

निर्णायक कदम रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित पहल एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाती है कि बुनियादी ढांचा सिर्फ भौतिक परिसंपत्ति के तौर पर नहीं, बल्कि लचीलापन, अवसर और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 2026-27 के बजट में किसानों, युवाओं और एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र पर केंद्रित एक निर्णायक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जो भारत के आगे बढ़ने के साथ-साथ समावेशी विकास, नवाचार और पूंजी निवेश की नींव को मजबूत करेगा।

दांचे को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

केंद्रीय बजट : विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए मिले 250 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, (भाषा)। भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बीच केंद्रीय बजट 2026-27 में विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्चों को निपटाने के लिए 500 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है। प्रत्येक राज्य अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात में राशि का भुगतान करता है। भारत में मतदाताओं की संख्या वर्तमान में लगभग 99 करोड़ है। केंद्रीय बजट 2026-27 के

अनुसार, संशोधित अनुमानों के तहत 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट अनुमानों के अनुसार, यह राशि 300 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, चुनाव कानूनों, संबंधित नियमों और निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले विधि मंत्रालय को 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के लिए 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी चुनाव के बाद विभिन्न एजेंसियों और राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए धराराशि उपलब्ध कराई जाती है।

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

सरकार के पास कोई नीति, समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं : कांग्रेस

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय बजट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि इस सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि वंचित वर्गों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई तथा किसानों की भी उपेक्षा हुई है। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार के पास अब नए विचारों की कमी दिखती है। बजट-2026 भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। मिशन मोडै अब चैलेंज रूठे बन गया है। सुधार एक्सप्रेस शायद ही कभी किसी सुधार जंक्शन पर रुकती है। उन्होंने दावा किया कि अब कोई नीति-दृष्टि नहीं है और

कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे अनन्यता किसान आज भी सार्थक कल्याणकारी समर्थन या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के दौर से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है। सुधार, वित्त आयोग की अनुसंधान, वित्त आयोग की सुधारपरिषद का और अध्ययन करना होगा, लेकिन वे भी गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिखती तथा संघवाद इसकी बलि बन गया है। उन्होंने कई अन्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा, यह बजट कोई समाधान नहीं देता।

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में अवसरचना को विकसित भारत 2047 की ओर देश की यात्रा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संपर्क, विनिर्माण की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट तरीके से ध्यान देने के साथ, बजट में विश्वस्तरीय, भविष्य के लिए तैयार अवसरचना बनाने के लिए एक

Office of The Superintending Engineer
Public Works Department, E/M Circle, Raipur (C.G.)
e-Procurement Tender Notice
Online tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh from contractors, C.G. P.W.D in new Registration system (unified Registration system) for the following work:-

91/SE E/M/2025
Providing And Fixing of Street Lighting Work (I/Call) System Tender No. 18.4525 Registered contractor class in "D" & above For Form A (Percentages Rate Basis)
Rs 81.86 Lacs

92/SE E/M/2025
Providing And Fixing Of Street Lighting Work At Overpass Near Jarway Road Bangali Hotel Square Ring Road No 2 Under Pwd Workshop E/M. Sub Dn. Raipur (C.G.)
Rs 87.99 Lacs

93/SE E/M/2025
Providing And Fixing Of Street Lighting Work At Overpass Near Hirapur Square Ring Road No 2 Under Pwd Workshop E/M. Sub Dn. Raipur (C.G.)
Rs 81.86 Lacs

Date of bid submission will be 18.02.2026
The tender documents can be downloaded from the web-portal http://eproc.cgstate.gov.in. Only those contractors/bidders, interested in bidding shall pay the tender document cost online.

Superintending Engineer
P.W.D., E/M Circle Raipur (C.G.)

For Publication
In The Court of Sh. Anshul Mehta, Administrative Civil Judge-cum-Commercial Judge-cum-Additional Rent Controller, (West) Court Room No. 112, 1st Floor, Tis Hazari Courts, Delhi.
Case No. Succ. Court-01/2026
Title as:-
Deepika V/s State (NCT Delhi) & Ors. For Succession Certificate Under Indian Succession Act, 1925
To, Deepika W/o Late Sh. Himmat Singh, D/o Late Kamal Singh, R/o R-105, J.J. Colony, Raghubir Nagar, Tagore Garden, New Delhi-110027.
Where in the above noted Petition the applicant/petitioner has applied for Succession Certificate to the Hon'ble Court Under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 in respect of the debt and Securities Amount Lying in Deferent Banks of to be standing in the name of Late Sh. Himmat Singh, deceased.
Whereas at 10 (Ten) O' clock in the forenoon has been fixed for 28th February, 2026 hearing on the application notice is hereby given to all concerned.
Given under my hand and the seal of the court, this 13th day of January, 2026.
Seal Sd/- Admn. Civil Judge-cum-Addl. Rent Controller, (West), Delhi.

वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

मोदी ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया

वीर अर्जुन संवाददाता
जालंधर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर किया और लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर सिविल टर्मिनल भवन का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न लगभग तीन बजकर 45 मिनट पर आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे। गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर मोदी यहां डेरा सचखंड बल्लू भी गये। इस बीच, मोदी ने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया, जिससे पंजाब में बुनियादी विमानन ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा। रायकोट उपखंड के हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे पर विकसित इस टर्मिनल से क्षेत्र में हवाई संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने और औद्योगिक एवं



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जालंधर कार्यक्रम में भाग लेते हुए।

आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हवाई अड्डे की टर्मिनल भवन परियोजना को पंजाब सरकार और भारतीय विमानन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 54.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से

स्थापित किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य गणमान्य व्यक्ति लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर मौजूद

धे प्रधानमंत्री मोदी के जालंधर दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के शुरू होने से क्षेत्र में हवाई संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे औद्योगिक गतिविधि, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार पंजाब के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि हवाई संपर्क में सुधार और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसमें ३20 जैसे विमानों को संभालने में सक्षम लंबा रनवे है। लुधियाना से हवाई संपर्क शहर के उद्योगपतियों की प्रमुख मांगों में से एक रहा है, जिन्हें या तो दिल्ली, चंडीगढ़ या अमृतसर से उड़ान भरनी पड़ती है।

पिछले कुछ वर्ष में आठ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया : गोयल

नई दिल्ली, (भाषा)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 37 विकसित देशों के साथ आठ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चिली, पेरू और कनाडा सहित कई देशों के साथ इसी तरह के समझौतों के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। गोयल ने कहा कि चिली के साथ व्यापार वार्ता लगभग अंतिम चरण में है जहां भारत के महत्वपूर्ण खनिजों में हित है। मंत्री ने पीटीआई-भाषा से कहा, नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने पिछले कुछ वर्षों में 37 विकसित देशों के साथ आठ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। वर्ष 2014 से अब तक भारत ने आठ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया है। गोयल ने बताया कि मौजूदा पीटीए (तरजीही प्राप्त

व्यापार समझौता) का विस्तार करने के लिए मर्कोसुर देशों के समूह के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है। मर्कोसुर व्यापार समूह के सदस्य अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, पेरू और उरुग्वे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र के छह देशों के समूह जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि भारत और एसएसयू (दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ) भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या दोनों पक्ष व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए कई संभावित व्यापार समझौते होने की कगार पर है। आने वाले वर्ष में हमें निश्चित रूप से और भी कई अच्छी खबरें सुनने की मिलेंगी।

जनगणना 2027 के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन
नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय बजट में 2027 की जनगणना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कोविड महामारी की वजह से लगभग छह साल की देरी के बाद, 1 अप्रैल से 16वीं जनगणना की कवायद शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट अनुमान पेश किए, उनमें जनगणना, सर्वे और सांख्यिकीय भारत के महापंचायक (आरजीआई) के लिए 6,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान में आवंटित 1,040 करोड़ रुपये से लगभग छह गुना अधिक है। बजट दस्तावेज में कहा गया है, 'इसमें भारत के महापंचायक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय और आरजीआई की अलग-अलग योजनाओं, जिनमें राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) और जनगणना 2027 पर व्यय शामिल है, के लिए प्रावधान शामिल हैं। जनगणना 2027 में की जाएगी, जिसमें लड़ाकू जैसे बर्ष से ठके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि। अक्टूबर 2026 और देश के शेष हिस्सों के लिए। मार्च 2027 होगी।

बुनकरों और कारीगरों की खुल गई किस्मत
नई दिल्ली (विप्र)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने खादी और हस्तशिल्प वस्त्रों को मजबूती देने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना लाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नेशनल फाइबर स्कीम लाई जाएगी जिसके माध्यम से रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों के साथ-साथ भविष्य के 'मानव-निर्मित' और औद्योगिक रेशों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने 'टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम' की भी घोषणा की जो पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित होगी। इसके तहत सरकार मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत सहायता, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के परीक्षण केंद्र स्थापित करने में मदद करेगी।

एनसीआरटीसी को 2,000 करोड़ आवंटित किए गए
नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय बजट 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निगम परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम है। रोजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किए गए एनसीआरटीसी को इस वित्त वर्ष के लिए 2,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2025-26 में यह राशि 2,918 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3,855 करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए क्षेत्रीय रैपिड रेल परियोजना के लिए राजस्व व्यय के तौर पर 1,324 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के रूप में 876 करोड़ रुपये आवंटित किए।

विधि मंत्रालय की ई-अदालत परियोजना को 1,200 करोड़ रुपए का आवंटन
नई दिल्ली, (विप्र)। देश की सभी अधीनस्थ अदालतों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विधि मंत्रालय की ई-अदालत परियोजना के महत्वाकांक्षी तृतीय चरण के लिए 2026-27 के केंद्रीय बजट में 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक, इस परियोजना को बजट अनुमान के 1,500 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,200 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। सितंबर 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसे चार साल में लागू किया जाना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत भारतीय न्यायालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सक्षम बनाने के लिए 2007 से ई-अदालत परियोजना क्रियान्वयन में है। परियोजना का दूसरा चरण 2023 में खत्म हुआ।

बजट युवाओं के साथ विश्वासघात : युवा कांग्रेस
नई दिल्ली, (विप्र)। भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद रविवार को बेंगलूरु और महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि यह बजट युवाओं के साथ विश्वासघात है। युवा कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञापित के अनुसार, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, 'यह बजट नहीं, जनता खासकर युवाओं के साथ विश्वासघात है। शोचर बाजार में मची अफरा-तफरी इस बात का प्रमाण है कि यह बजट देश को प्रगति नहीं, बल्कि गर्त में ले जाने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार युवाओं के सपने को कुचलकर कौन सा विकसित भारत बनाना चाहती है। चिब ने दावा किया कि लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी साबित कर रही है कि मोदी सरकार विफल है।

बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजटीय अनुमान
नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3,400 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजटीय अनुमान से 50 करोड़ रुपये और 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 1,240 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। पिछले बजट में मंत्रालय का बजट अनुमान 3,350 करोड़ रुपये था, हालांकि संशोधित अनुमान 2,160.45 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बार सीतारमण द्वारा किये गये बजट आवंटन में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए 831.7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 1,197.97 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

डीआरडीओ के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा : संयुक्त निदेशक
कोलकाता, (भाषा)। डीआरडीओ के संयुक्त निदेशक बिनाय कुमार दास ने रविवार को कहा कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों के डिजाइन और विकास में लगे प्रमुख सरकारी अनुसंधान संगठन के लिए बजट कभी भी बाधा नहीं रहा है। दास ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमेशा से भरपूर सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा, सरकार ने हमेशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को वित्त शर्त सहयोग दिया है और बजट हमारे लिए कभी बाधा नहीं रहा है। दास के मुताबिक, डीआरडीओ से आगती पीढ़ी की ऐसी तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उन्होंने यहां साइंस सिटी सभागार में कहा, हमें ऐसे उपकरणों पर काम करना होगा, जिनका हमारे सशस्त्र बल सपना देख रहे हैं। हम ऐसे उपकरणों के आयात का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और युद्ध के परिदृश्यों में समीकरण बदल गए हैं।

आयुष मंत्रालय के बजट आवंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी
नई दिल्ली, (विप्र)। आयुष मंत्रालय के बजट आवंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के 3,671.82 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 4,408.93 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार ने इस क्षेत्र में शोध कार्यों को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की भी घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान मिलता है, को तब बड़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। यह कहते हुए कि कोविड के बाद आयुर्वेद को भी इसी तरह की वैश्विक स्वीकृति और पहचान मिली है, सीतारमण ने कहा कि गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात उन किसानों की मदद कर सकता है जो जड़ी-बूटियां उगाते हैं और उन युवाओं को जो उनका प्रसंस्करण करते हैं।

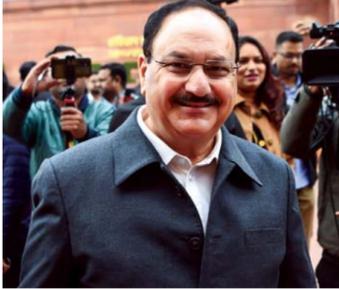
बजट वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने की गति तेज करेगा: शाह

नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम बजट भारत को वैश्विक मंच पर परंपरिक से लेकर नये दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, विनिर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट एक ऐसा बजट है जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के सपनों को सहायता बनाता है, ताकि वे उन सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने सरकार द्वारा राजकोषीय विवेक के साथ विकास और प्रगति को रफ्तार देने की प्रतिबद्धता पर जबर्दस्त तरीके से मुहर लगाये जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि बजट

राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लक्ष्य को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की परिकल्पना और अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप पेश करता है। गृह मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित करके, बजट ने प्रधानमंत्री के भविष्य के लिए तैयार भारत के दृष्टिकोण को गति प्रदान की है, जहां विकास प्रमुख शहरों से परे तक फैला है। उन्होंने कहा कि नये रेल गलियारों, राष्ट्रीय जलमार्गों और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की आकांक्षाएं नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी। उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है।

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी बजट: नड्डा

वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आम बजट 2026-27 को लोक-कल्याणकारी और ठविकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी बजट बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक विकास गति को नई दिशा देने वाला है और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में स्थापित करने की मजबूत आधारशिला रखता है। नड्डा ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी है, जिसमें समाज के हर वर्ग-श्री, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग-का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे उद्युवा शक्ति का बजट बताते हुए कहा कि इसमें रोजगार सृजन, कौशल विकास और नवाचार को प्राथमिकता दी गई है, जिससे आने वाले वर्षों में युवाओं



स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा

को व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता इसी बात से ज़ाहिर होती है कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 176 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष आवंटित 1 लाख 5 हजार करोड़ से अधिक का बजट पिछले वर्ष के बजट से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। बजट में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के एम्स जैसे दो संस्थान खोले जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। यही इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं निमहंस 2 की घोषणा भी सरकार की जनकल्याण की सोच को प्रदर्शित करती है।

बजट: विशेषज्ञों ने एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की नियुक्ति की घोषणा का स्वागत किया

नई दिल्ली, (भाषा)। कई चिकित्सा विशेषज्ञों ने रविवार को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की सरकार की घोषणा का स्वागत किया। कई विशेषज्ञों ने भारत को चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए एक योजना शुरू करने के केंद्रीय बजट प्रस्ताव की भी सराहना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसर के रूप में कार्य करेंगे, जहां चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं मिलेंगी। अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. प्रताप

सी. रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 से यह आश्चर्य करने वाला संदेश मिलता है कि भारत का विकास स्वस्थ नागरिकों और मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य क्षमता विस्तार, रोकथाम को सुदृढ़ करने और द्वितीय व तृतीय स्तर के शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर निरंतर ध्यान देना विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। रेड्डी ने कहा, 'लोगों पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से उत्साहजनक है। 1.5 लाख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना व संबद्ध स्वास्थ्य विषयों का विस्तार करना, प्रधानमंत्री की भारत में उपचार, भारत द्वारा उपचार की परिकल्पना को सुदृढ़ कर सकता है। राज्यों को चिकित्सा पर्यटन में सहायता देने से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए

नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है, जो 2025-26 के बजट अनुमान 2.33 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 9.44 प्रतिशत अधिक है। बजट में गृह मंत्रालय के लिए कुल धनराशि का 68 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपये पुलिस मद के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, वीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, सीमा विकास कार्यक्रम, तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के पुलिस बलों के लिए निधि शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 1,348.0 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आंतरिक खुफिया एंजिसी आईबी को 2026-27 में 6,782.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आईबी के आवंटन में पिछले बजट की तुलना में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले बजट में आईबी के लिए 4,159.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट दस्तावेज में कहा गया है, 'यह प्रावधान खुफिया ब्यूरो के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है।

बजट आर्थिक, राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता: चिदंबरम

नई दिल्ली, (बीओ)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनका भाषण तथा बजट आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरते। पूर्व वित्त मंत्री ने यह कटाक्ष भी किया कि सीतारमण ने या तो आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा या फिर उसे जानबूझकर दरकिनार कर दिया। चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, आज संसद में वित्त मंत्री के भाषण में जो कुछ सुनने को मिला उससे अर्थशास्त्र का हर छत्र अवश्य ही स्तब्ध रह गया होगा। बजट केवल वार्षिक राजस्व और व्यय का बयान भर नहीं होता। मौजूदा परिस्थितियों में बजट भाषण को उन प्रमुख चुनौतियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए, जिनका जर्जि कुल दिन पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-

26 में किया गया था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे संदेह है कि सरकार और वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा भी है या नहीं। अगर उन्होंने पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे पूरी तरह से दरकिनार करने का फैसला कर लिया है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (लगभग 30 प्रतिशत) का कम स्तर और निजी क्षेत्र की निवेश करने में हिचकिचाहट, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को लेकर अनिश्चित दृष्टिकोण और पिछले कई महिनों से विदेशी निवेश का बाहर जाना, राजकोषीय समेकन की बेहद धीमी गति, राजकोषीय घाटा बढ़ना, लाखों एमएसएमई का बंद होना, युवाओं में बेरोजगार, बढ़ता शहरीकरण और शहरी क्षेत्रों (नगरपालिकाओं और नगर निगमों) में बिगड़ता बुनियादी ढांचे जैसी कई चुनौतियां हैं।

राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना की

नई दिल्ली, (विप्र)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उसने अपने हथियारों और साजो-सामान को तैनात किया था और तटीय क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बनाए रखी थी। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पिछले पांच दशकों में आईसीजी भारत के रणनीतिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। एक फरवरी, 1977 को स्थापित आईसीजी का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटना और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने समुद्र में गश्त करने से लेकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने तक, और जान बचाने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तक, आईसीजी द्वारा निभाई गई विभिन्न प्रमुख भूमिकाओं का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने कहा, इसके अलावा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए कार्य हैं, जिसे समुद्री क्षेत्र में संवेदनशील हालात के माहौल में अंजाम दिया गया था। भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव आर के सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिदेश के त्रिपाठी और आईसीजी के महानिदेशक परमेश शिवमणि उपस्थित थे।

बजट में रेलवे को पूंजी व्यय के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

नई दिल्ली, (विप्र)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ-साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, क्योंकि रेलवे की कमाई इतनी कम है कि वह परिसंपत्ति बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती,

इसलिए उन्से सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिमल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहराकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024-25 में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

पाकिस्तान को हराकर भारत अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में

बुलावायो, (भाषा)। युवा कनिष्क चौहान के हरफनमौला खेल के दम पर भारत ने अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में रविवार को यहां चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की।

भारत के सामने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की चुनौती होगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने होंगे। कनिष्क ने बल्ले से 29 गेंद में 35 रन की पारी खेलने के अलावा आठवें विकेट लिए खिलान पटेल (15 गेंद में 21 रन) के साथ 50 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की जिससे टीम ने 49.5 ओवर में 252 रन बनाये।

पाकिस्तान को भारत से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 33.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना था लेकिन टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कभी ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने 33.3 ओवर में चार विकेट पर 167 रन बनाये थे और फिर पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर आउट हो गयी।

गेंदबाजी विभाग में कनिष्क ने 10



ओवर में महज 30 रन देकर एक विकेट चटकاته हुए पाकिस्तान टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने इस दौरान 40 डॉट गेंदे डाली। पिच से स्पिनरों को मदद मिलने के बीच बाएं हाथ के स्पिनर खिलान पटेल (9.2 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट) और कप्तान आयुष म्हात्रे (8 ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट) ने भी बीच ओवरों में रन गति को पूरी तरह बांधे रखा।

एशिया कप के नायक रहे पाकिस्तान के समीर मिन्हास को हेनिल पटेल ने

शुरुआती ओवरों में ही अपनी ऑफ-कटर पर पबेलियन का रास्ता दिखाया जिसके बाद टीम के बल्लेबाजों ने बेहद रक्षात्मक रवैया अपना लिया। म्हात्रे ने मैच के बाद कहा, शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बीच के ओवरों में गेंद स्पिन होने लगी। केंसी (कनिष्क का उपनाम) ने शानदार बल्लेबाजी की। वेदांत (त्रिवेदी) ने नेट में अच्छी बल्लेबाजी की थी, इसलिए मुझे उन पर भरोसा था। खिलाड़ियों ने शानदार योगदान दिया। पाकिस्तान के

►**भारत के सामने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की चुनौती होगी**

बल्लेबाजों ने पहले 25 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद हमारे स्पिनरों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। हम एक बार में एक मैच पर ध्यान दे रहे हैं। हम अब फाइनल जीतना चाहते हैं। इससे पहले कनिष्क और खिलान ने महज 5.1 ओवर में 50 रन जोड़े और पारी के अंत में तेजी से रन जुटाये। इससे पहले वेदांत त्रिवेदी ने 98 गेंदों में संयमित 68 रन की पारी खेलकर टीम को ठोस आधार दिया था। पाकिस्तान के लिए अब्दुल सुभान ने तीन जबकि मोहम्मद सय्याम ने दो विकेट लिये जिससे भारतीय पारी 49.5 ओवर में सिमटी। वैभव सूर्यवंशी (22 गेंदों में 30 रन) ने पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाई लेकिन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सय्याम को खिलाफ जीवनदान मिलने के बावजूद वह लगातार दूसरी गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए।

कप्तान आयुष म्हात्रे (0) का युवा बनड़ें में खराब दौर जारी रहा और वह पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए।

वही दूसरे सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज (16) को लंबे कद के तेज गेंदबाज सुभान ने चलता किया। सुभान ने अपने कद का फायदा उठाते हुए असहज उछाल हासिल कर बल्लेबाजों को परेशान किया।

विहान मल्होत्रा (21) ने 47 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवाने के बाद वेदांत के साथ चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी कर भारतीय पारी को संभाला। हालांकि पिच की धीमी गति के कारण शॉट खेलना मुश्किल रहा और वेदांत समेत शीर्ष क्रम का कोई भी बल्लेबाज रन गति नहीं बढ़ा सका।

दाएं हाथ के बल्लेबाज वेदांत ने 98 गेंदों की पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया, लेकिन बाएं हाथ के कलाई स्पिनर मोमिन खमर की फुल-टाॅस गेंद पर खराब शॉट छलकर आउट हो गए।

खिलान और कनिष्क ने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम को 250 रन के पार पहुंचाया। इस मैच में वह भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया।

ब्रेक और बल्लेबाजी में कुछ बदलाव से फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम, (भाषा)। भारत

की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली।सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेलीं।

सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जुड़ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने

खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था।सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया।

उन्होंने कहा, नए साल की शुरुआत से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। विशेष रूप से शुरुआती ओवरों में मेरे स्ट्राइक रेट पर मैंने चिंतन किया। सूर्यकुमार ने कहा, मैं 2021-23 में शुरुआती पांच-दस गेंदों पर आक्रामक बल्लेबाजी करता था और मेरा स्ट्राइक रेट 200-250 रहता था।

जोकोविच को हराकर करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने अल्कारेज

मेलबर्न, (एपी) कार्लोस अल्कारेज रविवार को यहां फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम- ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकार्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न आर्ग में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की।जीत दर्ज करने के बाद कोर्ट से जाते हुए अल्कारेज ने टीवी कैमरा के लेंस पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, काम पूरा हुआ। चार में से चार पूरे हुए। बाइस साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा। जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैंकेट छोड़ दिया और दोनों टीम

बजट: सरकार ने खेलों इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली, (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगले दशक में प्रशिक्षण केंद्री और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रविवार को खेलों इंडिया मिशन शुरू करने के प्रस्ताव रखा जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख खेलों इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।सीतारमण ने वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा। खेलों इंडिया कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान के लिए सभी आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था।सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा, खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलों इंडिया कार्यक्रम से खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मैं आगले दशक में खेल क्षेत्र में आमूलकूल बदलाव करने के लिए 'खेलों इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा, यह मिशन मूलभूत, मध्यवर्ती और विशिष्ट स्तरों के प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से एकीकृत प्रतिभा विकास, प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास,

खेल

भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप

9 वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

लाहौर, (भाषा)। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम को भागीदारी को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को इस विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किये जाने के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी लेकिन आईसीसी ने उसे टुकरा दिया था।

पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में

मैदान पर नहीं उतरेगी। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट के बीच यह फैसला क्षेत्र में बड़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है।

सरकार ने सोशल मीडिया पर कहा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा था कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बाद टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा।

देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स के रूप में अपना पहला सुपर 300 खिताब जीता

इसके साथ ही वह इंडोनेशिया के रहने वाले कोच इरवानस्याह आदि प्रतामा की देखरेख में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू के साथ अपने खेल को निखार रही हैं।देविका की इस शानदार जीत की सराहना करते हुए सिंधू ने कहा कि इस युवा खिलाड़ी की सफलता उनकी नियमित अनुशासन और कड़ी मेहनत का नतीजा है। सिंधू ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जब मेरे ट्रेनिंग पार्टनर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा, देविका बैंगलुरु में मेरे और कोच इरवानस्याह के साथ ट्रेनिंग करती हैं और उनकी लगन को करीब से देखना अद्भुत अनुभव रहा है। उन्होंने मेरी टीम के साथ मिलकर स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर काफी मेहनत की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके खेल को धीरे-धीरे विकसित होते, परिपत्र होते और आगे बढ़ते देखा है। उन्होंने कहा, यह जीत उनके अनुशासन, कड़ी मेहनत और विश्वास का प्रतिबिंब है। मुझे उन पर बहुत गर्व है।

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह लगातार परेशान दिख रही थीं।देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बद्दौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया।भारतीय खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट और सीधे स्मैश लगाने की अपनी क्षमता और साथ ही बड़ी कुशलता से ड्रॉप शॉट लगाने से जल्द ही 9-2 से आगे हो गईं। इंटरवल तक उन्होंने 11-4 की बढ़त हासिल कर ली।

कोहली ने मुझे दिल्ली के लिए 200 प्रतिशत देने के लिए प्रेरित किया: दोसेजा

मुंबई, (भाषा)। रणजी ट्रॉफी के ग्रुप चरण का समापन सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर करने वाले दिल्ली के आयुष दोसेजा भारतीय सुपरस्टार फिटनेस रूटीन को अपनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। इस 23 साल के बल्लेबाज ने इस सत्र की शुरुआत में हैदराबाद के खिलाफ पदार्पण किया था। उन्होंने मौजूदा रणजी सत्र को चार शतक और पांच अर्धशतक की मदद से 94.9 रन के साथ खत्म किया। इस दौरान उनका औसत 105.44 का रहा। अपने पदार्पण सत्र में ही कप्तानी का दायित्व मिलने के बाद दोसेजा ने मुंबई के खिलाफ दूसरी पारी में नाबाद 159 रन बनाकर मैच ड्रॉ करने में अहम भूमिका निभाई। मौजूदा सत्र में उनके शानदार प्रयास के बावजूद दिल्ली आठ टीमों की ग्रुप तालिका में छह ड्रॉ और एक हार से सातवें पायदान पर रही। दोसेजा ने मैच के बाद कहा, कोहली ने मुझसे कहा

जम्मू-कश्मीर ने मुंबई के साथ एलीट ग्रुप डी से रणजी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

मुंबई, (भाषा)। कप्तान आयुष दोसेजा की नाबाद 159 रन की पारी की बदौलत दिल्ली ने रविवार को यहां रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी में तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कर लिया। इसी ग्रुप से जम्मू-कश्मीर ने भी 42 बार की चैंपियन मुंबई के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

दोसेजा ने एमसीए-बीकेसी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में 230 गेंदों में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 159 रन बनाए और मुंबई को जीत से दूर रखा। दोनों टीमों में चार के विश्राम से करीब आधा घंटा पहले मुकाबला बराबरी पर समाप्त करने पर सहमति जता दी। दिल्ली ने दूसरी पारी छह विकेट पर 407 रन बनाकर घोषित की। उस समय उसकी कुल बढ़त 311 रन की थी। दिल्ली ने पहली पारी में 96 रन से पिछड़ने के बाद पिछले दो दिनों में मुंबई को कड़ी चुनौती दी। मुंबई ने सात मैचों में सात जीत और दो ड्रॉ

^[1] बुलावायो, (भाषा)। युवा कनिष्क

^[2] चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रन से हराकर

^[3] सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की

^[4] आमने-सामने होंगे

^[5] कनिष्क ने बल्ले से 29 गेंद में 35 रन की पारी खेलने के

^[6] अलावा आठवें विकेट लिए खिलान पटेल

^[7] (15 गेंद में 21 रन) के साथ 50 रन की ताबड़तोड़

^[8] साझेदारी की जिससे टीम ने 49.5 ओवर में

^[9] 252 रन बनाये

^[10] पाकिस्तान को भारत से बेहतर नेट रन रेट

^[11] हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए

^[12] 33.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना था लेकिन

^[13] टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कभी ऐसा करने में

^[14] दिलचस्पी नहीं दिखाई

^[15] पाकिस्तान ने 33.3 ओवर में चार विकेट पर

^[16] 167 रन बनाये थे और फिर पूरी टीम

^[17] 46.2 ओवर में 194 रन पर आउट हो गयी

^[18] गेंदबाजी विभाग में कनिष्क ने

^[19] 10

^[20] ओवर में महज 30 रन देकर एक विकेट

^[21] चटकاته हुए पाकिस्तान टीम की रफ्तार पर ब्रेक

^[22] लगा दिया

^[23] उन्होंने इस दौरान 40 डॉट गेंदे डाली

^[24] पिच से स्पिनरों को मदद मिलने के बीच बाएं हाथ के

^[25] स्पिनर खिलान पटेल (9.2 ओवर में 35 रन देकर

^[26] तीन विकेट) और कप्तान आयुष म्हात्रे (8 ओवर में

^[27] 23 रन देकर तीन विकेट) ने भी बीच ओवरों में रन गति को

^[28] पूरी तरह बांधे रखा

^[29] एशिया कप के नायक रहे पाकिस्तान के समीर

^[30] मिन्हास को हेनिल पटेल ने

^[31]
^[32]
^[33]
^[34]
^[35]
^[36]
^[37]
^[38]
^[39]
^[40]
^[41]
^[42]
^[43]
^[44]
^[45]
^[46]
^[47]
^[48]
^[49]
^[50]
^[51]
^[52]
^[53]
^[54]
^[55]
^[56]
^[57]
^[58]
^[59]
^[60]
^[61]
^[62]
^[63]
^[64]
^[65]
^[66]
^[67]
^[68]
^[69]
^[70]
^[71]
^[72]
^[73]
^[74]
^[75]
^[76]
^[77]
^[78]
^[79]
^[80]
^[81]
^[82]
^[83]
^[84]
^[85]
^[86]
^[87]
^[88]
^[89]
^[90]
^[91]
^[92]
^[93]
^[94]
^[95]
^[96]
^[97]
^[98]
^[99]
^[100]
^[101]
^[102]
^[103]
^[104]
^[105]
^[106]
^[107]
^[108]
^[109]
^[110]
^[111]
^[112]
^[113]
^[114]
^[115]
^[116]
^[117]
^[118]
^[119]
^[120]
^[121]
^[122]
^[123]
^[124]
^[125]
^[126]
^[127]
^[128]

भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा : ट्रंप

भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है

न्यूयॉर्क, (भाषा)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा। ट्रंप ने कहा, चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है। ट्रंप को इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी। ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों और इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

आए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और

निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों के बीच संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मंत्रालय ने कहा था, दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और ग्लोबल साउथ के लिए अपने घनिष्ठ सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। ग्लोबल साउथ से ताल्लुक उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में हैं।

डेमोक्रेट नीत शहरों में प्रदर्शनों के दौरान मदद मांगे जाने तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे : ट्रंप

वाशिंगटन, (एपी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम को निर्देश दिया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी शासित शहरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान तब तक दखल नहीं दिया जाएगा जब तक स्थानीय प्रधिकारी संघीय मदद न मांगें। ट्रंप ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब आब्रजन संबंधी कार्वाई को लेकर उनसे प्रशासन को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, हम खराब ढंग से संचालित विभिन्न डेमोक्रेट शहरों के विरोध प्रदर्शनों और यात्रा दलों में किसी भी परिस्थिति में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक वे हमसे मदद नहीं मांगेंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके आदेश का अमेरिकी सीमा

शुल्क एवं आब्रजन प्रवर्तन और गृह मंत्रालय के कर्मियों या अन्य संघीय एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्वाइयों पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप ने हालांकि कहा कि उनका प्रशासन उन संघीय इमारतों की रक्षा करेगा जो प्रदर्शनकारियों के कारण खतरे में होंगी। ट्रंप ने कहा कि नोएम को दिए निर्देशों के अलावा उन्होंने आईसीई (आब्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन) और अमेरिकी सीमा गश्ती बल को संघीय सरकार की संपत्ति की सुरक्षा करते समय बहुत कठोर रहने का भी निर्देश दिया है।

बलूचिस्तान में अशांति पर पाकिस्तान के आरोप भारत ने सिरे से खारिज किए

नई दिल्ली, (भाषा)। भारत ने बलूचिस्तान में शांति भंग करने की कोशिशों में उसका हाथ होने को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए रविवार को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह इस्लामाबाद की अथवा अंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान के दमन, बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों के रिपोर्टों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। यह उसकी अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। जायसवाल पाकिस्तान की सेना के उस बेबुनियाद दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि भारत बलूचिस्तान में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकवादी तत्वों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा, हर बार किसी हिंसक घटना के बाद निरर्थक आरोप दोहराने के बजाय पाकिस्तान को क्षेत्र में अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ध्यान देना चाहिए। दमन, बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों का उसका रिकॉर्ड जगजाहिर है। इस बीच, पाकिस्तान सेना ने कहा कि बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए कई आतंकवाद-रोधी अभियानों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक और 92 चरमपंथी मारे गए। सेना के बयान के अनुसार, ये अभियान शनिवार को जातीय बलूच समूहों से जुड़े चरमपंथियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हमलों के बाद शुरू किए गए। पाकिस्तान सेना ने कहा कि चरमपंथियों ने ट्रेटा, मस्तुग, नुशकी, दलबंदीन, खारान और पंजगुर तथा आसपास के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देकर शांति भंग करने की कोशिश की।

बलूचिस्तान में आतंकवाद रोधी अभियानों में 15 पाकिस्तानी सैनिक, 92 आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद, (भाषा)। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को बताया कि अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के कई आतंकवाद-रोधी अभियानों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक और 92 आतंकवादी मारे गए हैं।

सेना ने एक बयान में कहा कि ये अभियान शनिवार को जातीय बलूच समूहों से जुड़े आतंकवादियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हमलों के बाद शुरू किए गए। सेना ने बताया कि आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तुग, नुशकी, दलबंदीन, खारान, पंजगुर, तुम्म, ग्वादार और पसनी के आसपास आतंकी गतिविधियां करके शांति भंग करने की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि अत्यधिक सतर्क सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तेजी से कार्वाई करते हुए आतंकियों की शांति भंग करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसमें कहा गया है, हमारे बहादुर जवानों ने पूरी सटीकता के साथ आतंकवादियों का सामना किया और बलूचिस्तान भर में लंबे, भीषण और साहसिक अभियानों के बाद तीन आत्मघाती हमलावरों सहित 92

आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तुग, नुशकी, दलबंदीन, खारान, पंजगुर, तुम्म, ग्वादार और पसनी के आसपास आतंकी गतिविधियां करके शांति भंग करने की कोशिश की

आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने बताया कि आतंकियों ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों सहित 18 लोगों की मौत हो गई। अभियानों और बाद में हुई मुठभेड़ों के दौरान 15 सैनिकों ने भी अपनी जान गंवायी। शुक्रवार को पंजगुर और हरनाई जिलों में अलग-अलग सुरक्षा अभियानों में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तलिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े 41 आतंकवादी मारे गए थे। सेना ने कहा, पिछले दो दिनों में सफल अभियानों के साथ बलूचिस्तान में जारी अभियान के तहत मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 133 हो गई है।

कांग्रेस ने भारत के वेनेजुएला से तेल खरीदने वाली ट्रंप की टिप्पणी को लेकर सरकार पर तंज कसा

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर रविवार को नरेन्द्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया कि भारत ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इसकी जानकारी देते आ रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है या क्या करने जा रही है। रमेश ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब ट्रंप ने एयर फोर्स वन विमान में यात्रा करते समय एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, चीन का स्वागत है... हम तेल को लेकर एक शानदार सौदा करेंगे। हम चीन का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं... भारत ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हमने पहले ही वह सौदा कर लिया है। रमेश ने ट्रंप के इस बयान का आँडोंडो विशाल मीडिया में एक पक्ष पर साझा किया। मुख्य वित्तीय दल के नेता लिखा, ट्रंप ने हमें बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। और अब यहाँ रमेश ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हमें यह जानकारी देते रहते हैं कि हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने जा रही है।

बलूचिस्तान में अशांति पर पाकिस्तान के आरोप भारत ने सिरे से खारिज किए

नई दिल्ली, (भाषा)। भारत ने बलूचिस्तान में शांति भंग करने की कोशिशों में उसका हाथ होने को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए रविवार को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह इस्लामाबाद की अथवा अंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति है।

अमेरिका युद्ध शुरू करेगा तो पूरा क्षेत्र चपेट में आ जाएगा : खामेनेई

दुबई, (एपी)। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्वाई की धमकी पर पकटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्वाई किए जाने के बाद भेजा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं। उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को सत्तापलट जैसा बताया और कहा कि इससे सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। खबरों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाठियों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी देने



ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई

जैसी कार्वाई कर सकता है। ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास करने की योजना भी बनाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य वह संकरा मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में दुनियाभर में तेल की दुलाई होती है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई के

संक्षिप्त

तुर्किये में बस दुर्घटना में आठ की मौत, 26 घायल

इस्तांबुल, (एपी)। तुर्किये के अंताल्या प्रांत में एक यात्री बस के सड़क से फिसलकर पलट जाने से इसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारक टीआरटी द्वारा प्रसारित तस्वीरों में बस डोसेमेल्टी जिले में एक राजमार्ग से फिसलकर पलटती दिखती है। प्रांतीय गवर्नर हुसुसी साहिने ने बताया कि इस दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी डीएचए के अनुसार, बस के पलटने के बाद कुछ यात्री इसमें से बाहर निकलने में सफल रहे। भूमध्य सागर के किनारे स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल अंताल्या में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई है।

रूस-यूक्रेन के बीच अगले दौर की वार्ता अगले सप्ताह निर्धारित है : जेलेस्की

कीव, (एपी)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेस्की ने रविवार को कहा कि रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता का अगला दौर बुधवार और बृहस्पतिवार को होगा। वार्ता के अगले दौर के दौरान रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दूत अबू धाबी में मुलाकात करेंगे। जेलेस्की ने सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, हमें अभी-अभी हमारी वार्ता टीम से एक सूचना मिली है। अगली त्रिपक्षीय बैठकों की तारीखें तय हो गई हैं, जो चार और पांच फरवरी को अबू धाबी में होंगी। यूक्रेन सार्थक बातचीत के लिए तैयार है, और हम ऐसे परिणामों में रुचि रखते हैं, जो हमें युद्ध के वास्तविक और सम्मानजनक अंत के करीब ले जाएं। हालांकि, वार्ता के अगले दौर के संबंध में अमेरिकी या रूसी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई।

सरकार ने हर जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना की घोषणा की

नई दिल्ली, (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की रविवार की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। सीतारमण ने प्रगु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ढुंगा से जुड़ी पुंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आयुष औषधालयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा गुजराने के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए भी सहायता प्रदान करेंगे।

अमेरिकी राजदूत सात साल बाद राजनयिक मिशन दोबारा खोलने के लिए वेनेजुएला पहुंचीं

काराकस, (एपी)। अमेरिकी राजदूत लौरा डोगु शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस पहुंचीं, जहां उन्होंने सात साल बाद अमेरिका के राजनयिक मिशन को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की। यह कदम उस सैन्य कार्वाई के लगभग एक महीने बाद उठाया गया है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अंजाम दिया गया था और जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अमेरिकी देश के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया था। डोगु ने वेनेजुएला स्थित अमेरिकी दूतावास के

आधिकारिक एक्स खाते पर साझा किए गए संदेश में कहा, मेरी टीम और मैं काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। दूतावास ने माइग्रेटिया हवाई अड्डे पर उनके आगमन की तस्वीरें भी पोस्ट कीं। वेनेजुएला और अमेरिका ने फरवरी 2019 में राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। यह फैसला मादुरो सरकार ने तब किया था, जब ट्रंप ने जनवरी 2019 में विश्वी नेता और सांसद जुआन गुएदो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में सार्वजनिक समर्थन दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के दूतावास बंद कर दिए थे।

सिंगापुर में हिंदुओं ने थाईपुसम उत्सव मनाया, संस्कृति मंत्री भी हुए शामिल

सिंगापुर, (भाषा)। सिंगापुर के संस्कृति मंत्री दिनेश वासु दास ने यहां श्रद्धालुओं के साथ एक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। यहां भारतीय मंदिरों का प्रबंधन करने वाली एक सरकारी एजेंसी ने यह जानकारी दी मंत्री ने रविवार को थाईपुसम उत्सव में भाग लिया। उत्सव के तहत श्री श्रीनिवास पेरुलम मंदिर से श्री शंभुदायपुनी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं ने 3.2 किलोमीटर तक यात्रा की। श्रद्धालु अपने साथ

पालकुडम आदूष के पात्रा लिए हुए थे। हिंदू एंडोमेंटस बोर्ड एचईबी ने बताया कि शोभायात्रा शनिवार देर रात शुरू हुई और रविवार तक जारी रही। इसमें बताया कि शोभायात्रा में शामिल होने वालों में सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय और युवा एवं श्रमशाक्ति मंत्री दिनेश वासु दास और उनकी पत्नी डॉ. रथिणा वेलाइलुम भी थीं। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक यात्रा में शामिल होने से मुझे उनके अनुभव के बारे में जानने को मिला।

अमेरिका युद्ध शुरू करेगा तो पूरा क्षेत्र चपेट में आ जाएगा : खामेनेई

दुबई, (एपी)। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्वाई की धमकी पर पकटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्वाई किए जाने के बाद भेजा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं। उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को सत्तापलट जैसा बताया और कहा कि इससे सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। खबरों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाठियों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी देने

यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी समूह मानता है ईरान

दुबई, (एपी)। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि इस्लामी गणराज्य अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान उस फैसले के बाद आया है, जिसमें यूरोपीय संघ ने देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई खूनी कार्वाइ को लेकर ईरान के अर्धसैनिक बल रिवालयूनररी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ द्वारा की गई यह घोषणा मुख्यतः प्रतीकात्मक मानी जा रही है। ईरान 2019 में पारित एक कानून के तहत पहले भी अमेरिका द्वारा रिवालयूनररी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन करार दे चुका है।

एक अप्रैल से लागू होगा आयकर अधिनियम 2025

नई दिल्ली, (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा और इसके नियम तथा टैक्स रिटर्न फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा। बजट 2026-27 में कर कानूनों में किए गए बदलावों को इस नए कानून में शामिल किया जाएगा। सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, इसे (पत्यक्ष सहित) रिपोर्टों के अनुसार, एफबीआई ने जुलाई 2006 में एपस्टीन के मामले में जांच शुरू की थी। जारी किए गए रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि हुई कि एपस्टीन के ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ दोस्ताना संबंध थे। अभियोग लगने के एक महीने बाद अंगस्त 2019 में एपस्टीन ने न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी।

केंद्रीय बजट में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय बजट में इस बार चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई। अमेरिका द्वारा ईरान पर नये प्रतिबंध लगाये जाने की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है। भारत पिछले कुछ वर्षों से ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में जारी विशाल कनेक्टिविटी परियोजना पर प्रतिबंधों से भारत एक प्रमुख साझेदार है। पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लागू प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी थी। यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। पिछले महीने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना से संबंधित मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप प्रशासन द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने की धमकी के बाद भारत इस परियोजना से संबंधित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत और ईरान मिलकर चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिल सके। दोनों देश चाबहार बंदरगाह के अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएस्टीसी) का अधिन अंग बनाने के लिए भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आईएनएस्टीसी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल दुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी परिवहन परियोजना है।

एपस्टीन मामले के कारण स्लोवाकिया में शीर्ष अधिकारी ने दिया इस्तीफा

न्यूयॉर्क, (एपी)। जेफरी एपस्टीन से संबंधित अमेरिकी सरकार की हाल में सामने आई फाइल के कारण स्लोवाकिया के एक शीर्ष अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। वहीं, इस मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस को एपस्टीन के दुनिया भर के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध के बारे में प्राधिकारियों के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए। अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को एपस्टीन से जुड़ी कई फाइल जारी की जिसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। ये फाइल फ्लोरिडा में यौन अपराधों के लिए सजा काटने वाले एपस्टीन के अमीर और महारुह लोगों के साथ संबंधों की जानकारी प्रदान करती हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने शनिवार को मिरोस्लाव लाजैक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके लाजैक पर किसी भी प्रकार के रालत काम का आरोप नहीं था लेकिन एपस्टीन के जेल से रिहा होने के बाद के वर्षों में दोनों की मुलाकात की तस्वीरें और ईमेल सामने आने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इन खुलासों से ये सवाल फिर से

एपस्टीन से जुड़ी ताजा फाइलों में कई नामी हस्तियों के नाम

न्यूयॉर्क, (एपी)। अमेरिका के न्याय विभाग ने अरबपति कारोबारी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी जिन जांच फाइलों को शुक्रवार को सार्वजनिक किया, उनमें प्रौद्योगिकी जागत के दिग्गज बिल गेट्स और एलन मस्क, फिल्म निर्देशक मीरा नायर और व्हाइट हाउस के कुछ पूर्व सलाहकारों सहित अन्य नामी हस्तियों का जिक्र शामिल है। विभाग ने कहा कि वह एपस्टीन के खिलाफ दो दशक से अधिक समय तक की गई जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज, 2,000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी करेगा। विभाग की वेबसाइट पर जारी हालिया फाइल में ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रह चुके स्टीव बैनन के साथ एपस्टीन के ईमेल संवाद से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। रिपोर्टों में ट्रंप से संबंधित कई जगह संदर्भ हैं, जिनमें ऐसे ईमेल भी शामिल हैं जिनमें एपस्टीन और अन्य लोगों ने उनके बारे में समाचार लेख साझा किए, उनकी नीतियों या राजनीति पर टिप्पणी की, या उनके और उनके परिवार के बारे में चर्चा की। रिपोर्टों से पता चलता है कि टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने एक कैरिबियाई द्वीप की यात्रा की योजना के सिलसिले में कम से कम दो बार एपस्टीन से संपर्क किया था, जहां उससे कथित तौर पर जुड़ी यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई थीं। हालांकि, मस्क की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी की मां एवं फिल्म निर्देशक मीरा नायर का नाम भी एक ईमेल में सामने आया है।

उठने लगे हैं कि क्या एपस्टीन के मित्र रहने ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने शनिवार को सुझाव दिया कि माउंटबेटन-विंडसर को एपस्टीन की गतिविधियों के बारे में जो कुछ भी पता है, उसके बारे में उन्हें अमेरिकी जांच अधिकारियों को बता देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तावेजों के जारी होने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा, मैंने इसे खुद नहीं देखा, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे

सरकार का बजट में मछली पालन और पशुधन उपायों के साथ ग्रामीण विविधीकरण पर जोर

नई दिल्ली, (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार के अवसर पैदा करने के मकसद से रविवार को पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की।

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 करोड़ रुपये से 7.12 प्रतिशत ज्यादा है। अपना लगातार नौवां बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के अपने नजरिये को विकसित भारत की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा, इसके लिए उत्पादकता बढ़ाने और उद्यमशीलता के

जरिये किसानों की आय बढ़ाने को लक्षित प्रयासों की जरूरत है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों पर खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक खेती से हटकर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। मछली पालन के लिए, भारतीय जहाजों द्वारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और गहरे समुद्र में पकड़ी गई मछलियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ऐसी मछलियों को विदेशी बंदरगाहों पर उतारने को सामान का निर्यात माना जाएगा। सीतारमण ने कहा, 'मछली पकड़ने, पारगमन और ट्रांसशिपमेंट से दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि इन उपायों का मकसद भारतीय मछुआरों को देश के समुद्री क्षेत्र से बाहर समुद्री संसाधनों

के आर्थिक मूल्य का पूरा फायदा उठाने में मदद करना है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात किए गए समुद्री खाद्य उत्पादों के विशिष्ट कच्चे माल के लिए लदान मूल्य (एफओबी) सीमा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। देश के भीतर मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास करेगी और तटीय इलाकों में मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगी, जिससे स्टार्टअप, महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और मछली किसान उत्पादक संगठनों के जरिये बाजार संपर्क कायम किया जा सके। उन्होंने 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गुण-सम्बद्ध पूंजी सन्निधि योजना का प्रस्ताव भी रखा।

दूरसंचार मंत्रालय के लिए प्रावधान 38 प्रतिशत बढ़ाकर 73,990 करोड़ करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, (भाषा)। सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के लिए परिव्यय को 38 प्रतिशत बढ़ाकर 73,990 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के लिए पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी।

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बढ़ा हुआ आवंटन विभिन्न परियोजनाओं के लिए है। इसमें भारतनेट, स्पेक्ट्रम की लागत सहित बीएसएनएल की पूंजीगत आवश्यकताएं, नेटवर्क का विस्तार और आंतरिक जरूरतों को पूरा करना शामिल है। मंत्री ने कहा कि हमने पिछले साल के 53,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में दूरसंचार पर आवंटन में बहुत अच्छी वृद्धि देखी है। अब हम 73,000 करोड़ रुपये तक

पहुंच गए हैं, जो लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि है। दूरसंचार मंत्रालय और विशेष रूप से बीएसएनएल के लिए आवंटन बढ़ाने के बारे में पूछने पर सिंधिया ने कहा कि सरकार बीएसएनएल को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा, मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) नौ प्रतिशत बढ़कर 90 रुपये से लगभग 99 रुपये हो गया है। हम जल्द ही तीन अंक को छूना चाहेंगे। हमने अपने सभी कार्यक्रमों में राजस्व बढ़ाया है और अब हम अपने आंतरिक नकदी प्रवाह के साथ इस पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है ताकि हम बीएसएनएल को पुनरुत्थान की राह पर ले जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना भारतनेट के लिए भी धनराशि शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा: सीतारमण

नई दिल्ली, (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का रविवार को प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दो स्थाणों पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा परिवेश बनाने के लिए कंटेनर निर्माण को एक योजना का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तीन समर्पित रासायनिक पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। यह कदम देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों के बीच उठाया गया है। मोबाइल

विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन मूल्य में करीब 30 गुना वृद्धि देखी गई जो वित्त वर्ष 2014-15 में 18,000 करोड़ रुपये से 2024-25 में 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गई। भारत से आईफोन का निर्यात 2025 में 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह 2024 में एप्पल द्वारा निर्यात किए गए 1.1 लाख करोड़ रुपये के करीब दोगुना है। देश में मोबाइल फोन का उत्पादन चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक करीब 6.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक या लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। अगस्त, 2025 तक देश के छह राज्यों में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 10 सेमीकंडक्टर विनिर्माण तथा पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

वायदा सौदों पर एसटीटी बढ़ाने से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़का

मुंबई, (भाषा)। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़का गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ।

विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान बाजार को पसंद नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक के अहम स्तर से भी नीचे फिसलकर 79,899.42 अंक पर खिसक गया था। हालांकि, बाद में सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ 1,546.84 अंक यानी

1.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मानक सूचकांक निफ्टी भी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 748.9 अंक यानी 2.95 प्रतिशत लुढ़ककर 24,571.75 अंक के निचले स्तर तक चला गया। इस बड़ी गिरावट के लिए बजट भाषण में वायदा कारोबार पर एसटीटी की दर 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने की घोषणा को जिम्मेदार माना गया। अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कारण रविवार होने के बावजूद शेयर बाजारों में विशेष कारोबारी सत्र आयोजित किया गया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशकों की चिंता का मुख्य कारण वायदा एवं विकल्प (एफ एंड ओ) कारोबार पर एसटीटी में की गई वृद्धि रही। एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक (एमडी)

और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीओओ) प्रणव हरिदासन ने कहा, एफ एंड ओ पर एसटीटी में विशेष रूप से वायदा पर तेज बढ़ोतरी ने बाजार प्रतिभागियों की कुल लेनदेन लागत बढ़ा दी है। इससे तरलता, भागीदारी और भारतीय बाजार की लागत प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ने की आशंका को लेकर विदेशी और घरेलू निवेशकों में चिंता फैल गई जो बाजार को त्वरित प्रतिक्रिया में नजर भी आई। सेंसेक्स की कंपनियों में से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शेयर में सर्वाधिक 5.61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि अदाणी पोर्ट्स में 5.53 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी प्रमुख रूप से गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, सन फार्मा और टाइटेन के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद किरतपुर, समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील करती है कि -

पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिये पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करें, पर्यावरण बचाने में सहायता करें। समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद किरतपुर, जनपद बिजनौर के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सफाई कार्य ठीक प्रकार करने हेतु टोल फ्री नं. 14420 व 1533 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समस्त पंजीकृत प्राइवेट सेप्टिक टैंक खाली करने वालों से अपील की जाती है कि वह (अतिसारित मल) इधर-उधर खाली न करें। नगर पालिका द्वारा संचालित डम्पिंग ग्राउंड में ही डालें। कूड़ा गोला व सूखा पृथक-पृथक कर निकाय द्वारा चलाये जा रहे सफाई वाहनों में ही डालें तथा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में सहयोग प्रदान करें। खुले में शौच पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि नगर पालिका परिषद किरतपुर ओडीएफ++ घोषित है। खुले में शौच करते हुये पकड़े जाने पर दण्ड आरोपित किया जायेगा। यह नगर आपका है, इसको स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के अन्तर्गत नगर को हरा-भरा एवं सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर में वृक्षारोपण किया गया है, वृक्षों की रक्षा करें। नगरवासियों से अपील है कि वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचावें। पेयजल को व्यर्थ बर्बाद न करें, जल है तो कल है, इसलिये जल का संचय कर, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। नगर पालिका के करों तथा अन्य देयों को समय से भुगतान करके अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। यदि पथ-प्रकाश का कोई बिन्दु दिन में जलता दिखायी पड़े तो उसकी सूचना कार्यालय नगर पालिका को अवश्य दें। जन्म-मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित अवधि 21 दिवस के अन्तर्गत अवश्य निर्गत करावें। रोड-पटरियों व नालियों पर अतिक्रमण न करें।

(मेघा गुप्ता)
अधिकांशी अधिकारी
एवं समस्त कर्मचारीगण
नगर पालिका परिषद, किरतपुर

(अब्दुल मन्जान)
अध्यक्ष एवं समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद, किरतपुर

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद बिजनौर, समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील करती है कि -

पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिये पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करें, पर्यावरण बचाने में सहायता करें। समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद बिजनौर के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सफाई कार्य ठीक प्रकार करने हेतु टोल फ्री नं. 14420 व 1533 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समस्त पंजीकृत प्राइवेट सेप्टिक टैंक खाली करने वालों से अपील की जाती है कि वह (अतिसारित मल) इधर-उधर खाली न करें। नगर पालिका द्वारा संचालित डम्पिंग ग्राउंड में ही डालें। कूड़ा गोला व सूखा पृथक-पृथक कर निकाय द्वारा चलाये जा रहे सफाई वाहनों में ही डालें तथा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में सहयोग प्रदान करें। खुले में शौच पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि नगर पालिका परिषद बिजनौर ओडीएफ++ घोषित है। खुले में शौच करते हुये पकड़े जाने पर दण्ड आरोपित किया जायेगा। यह नगर आपका है, इसको स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के अन्तर्गत नगर को हरा-भरा एवं सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर में वृक्षारोपण किया गया है, वृक्षों की रक्षा करें। नगरवासियों से अपील है कि वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचावें। पेयजल को व्यर्थ बर्बाद न करें, जल है तो कल है, इसलिये जल का संचय कर, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। नगर पालिका के करों तथा अन्य देयों को समय से भुगतान करके अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। यदि पथ-प्रकाश का कोई बिन्दु दिन में जलता दिखायी पड़े तो उसकी सूचना कार्यालय नगर पालिका को अवश्य दें। जन्म-मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित अवधि 21 दिवस के अन्तर्गत अवश्य निर्गत करावें। रोड-पटरियों व नालियों पर अतिक्रमण न करें।

(विकास कुमार)
अधिकांशी अधिकारी
एवं समस्त कर्मचारीगण
नगर पालिका परिषद, बिजनौर

(श्रीमती इन्द्रा सिंह)
अध्यक्ष एवं समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद, बिजनौर

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद नगीना, समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील करती है कि -

पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिये पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करें, पर्यावरण बचाने में सहायता करें। समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद नगीना, जनपद बिजनौर के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सफाई कार्य ठीक प्रकार करने हेतु टोल फ्री नं. 14420 व 1533 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समस्त पंजीकृत प्राइवेट सेप्टिक टैंक खाली करने वालों से अपील की जाती है कि वह (अतिसारित मल) इधर-उधर खाली न करें। नगर पालिका द्वारा संचालित डम्पिंग ग्राउंड में ही डालें। कूड़ा गोला व सूखा पृथक-पृथक कर निकाय द्वारा चलाये जा रहे सफाई वाहनों में ही डालें तथा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में सहयोग प्रदान करें। खुले में शौच पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि नगर पालिका परिषद नगीना ओडीएफ++ घोषित है। खुले में शौच करते हुये पकड़े जाने पर दण्ड आरोपित किया जायेगा। यह नगर आपका है, इसको स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के अन्तर्गत नगर को हरा-भरा एवं सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर में वृक्षारोपण किया गया है, वृक्षों की रक्षा करें। नगरवासियों से अपील है कि वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचावें। पेयजल को व्यर्थ बर्बाद न करें, जल है तो कल है, इसलिये जल का संचय कर, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। नगर पालिका के करों तथा अन्य देयों को समय से भुगतान करके अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। यदि पथ-प्रकाश का कोई बिन्दु दिन में जलता दिखायी पड़े तो उसकी सूचना कार्यालय नगर पालिका को अवश्य दें। जन्म-मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित अवधि 21 दिवस के अन्तर्गत अवश्य निर्गत करावें। रोड-पटरियों व नालियों पर अतिक्रमण न करें।

अधिकांशी अधिकारी
एवं समस्त कर्मचारीगण
नगर पालिका परिषद, नगीना

(ताहिरा बेगम)
अध्यक्षा एवं समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद, नगीना

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद शेरकोट, समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील करती है कि -

पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिये पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करें, पर्यावरण बचाने में सहायता करें। समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद शेरकोट, जनपद बिजनौर के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सफाई कार्य ठीक प्रकार करने हेतु टोल फ्री नं. 14420 व 1533 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समस्त पंजीकृत प्राइवेट सेप्टिक टैंक खाली करने वालों से अपील की जाती है कि वह (अतिसारित मल) इधर-उधर खाली न करें। नगर पालिका द्वारा संचालित डम्पिंग ग्राउंड में ही डालें। कूड़ा गोला व सूखा पृथक-पृथक कर निकाय द्वारा चलाये जा रहे सफाई वाहनों में ही डालें तथा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में सहयोग प्रदान करें। खुले में शौच पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि नगर पालिका परिषद शेरकोट ओडीएफ++ घोषित है। खुले में शौच करते हुये पकड़े जाने पर दण्ड आरोपित किया जायेगा। यह नगर आपका है, इसको स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के अन्तर्गत नगर को हरा-भरा एवं सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर में वृक्षारोपण किया गया है, वृक्षों की रक्षा करें। नगरवासियों से अपील है कि वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचावें। पेयजल को व्यर्थ बर्बाद न करें, जल है तो कल है, इसलिये जल का संचय कर, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। नगर पालिका के करों तथा अन्य देयों को समय से भुगतान करके अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। यदि पथ-प्रकाश का कोई बिन्दु दिन में जलता दिखायी पड़े तो उसकी सूचना कार्यालय नगर पालिका को अवश्य दें। जन्म-मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित अवधि 21 दिवस के अन्तर्गत अवश्य निर्गत करावें। रोड-पटरियों व नालियों पर अतिक्रमण न करें।

अधिकांशी अधिकारी
एवं समस्त कर्मचारीगण
नगर पालिका परिषद, शेरकोट

(शबनम नाज़)
अध्यक्ष एवं समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद, शेरकोट

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय बजट से पहले सोने, चांदी के वायदा भाव में नौ प्रतिशत की भारी गिरावट
नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने से पहले रविवार को वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में नौ प्रतिशत तक की गिरावट आई और ये अपने निचले सर्किट स्तर पर पहुंच गईं। हाल ही में आई रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली जारी रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, लगातार दूसरे सत्र में गिरावट जारी रही। सोने के अप्रैल में आपूर्ति वाले अनुबंधों का वायदा भाव 13,711 रुपये या नौ प्रतिशत टूटकर 1,38,634 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में इसने अपना निचला सर्किट स्तर छू लिया। एमसीएक्स पर चांदी के वायदा भाव में भी भारी गिरावट आई क्योंकि व्यापारियों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली जारी रखी।

यूपीआई लेनदेन जनवरी में 28.33 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर
नई दिल्ली, (भाषा)। देश में यूपीआईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये होने वाला लेनदेन जनवरी में 28.33 लाख करोड़ रुपये के मूल्य और 21.70 अरब की संख्या के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। एनपीसीआई ने बताया कि दिसंबर 2025 में लेनदेन का मूल्य 27.97 लाख करोड़ रुपये रहा था। मासिक आधार पर लेनदेन के मूल्य में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में औसत दैनिक लेनदेन 70 करोड़ रहा जिसका औसत मूल्य 91,403 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया जाएगा : सीतारमण
नई दिल्ली, (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार, छोटे व मझोले शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेगी।

IFS Code: UPCCBOOB1JNR | RBI Licence: RPCC.LK.05(DCCB)/2012 Date June 07, 2012
भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त

जिला सहकारी बैंक लि., बिजनौर

प्रधान कार्यालय: सिविल लाईन्स-2, बिजनौर-246701, उ.प्र.
की ओर से समस्त देशवासियों, जनपदवासियों एवं बैंक ग्राहकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
समस्त नागरिक निक्षेप ऋण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये जिला सहकारी बैंक लि., बिजनौर की निकटस्थ बैंक शाखा से सम्पर्क करें। सभी बैंक शाखाएं सीबीएस प्रणाली पर कार्यरत हैं। जिला सहकारी बैंक लि., बिजनौर द्वारा एकत्र किये गये संसाधनों का उपयोग जनपद के विकास में ही किया जाता है।
(कृपक सेवा एवं जनपद के विकास में विगत 115 वर्षों से बैंक की 49 शाखाओं के माध्यम से सतत समर्पित)

(संजय कुमार) (दिनेश कुमार)
सचिव/मुख्य कार्यवाहक अधिकारी (अध्यक्ष)

जिला सहकारी बैंक लि., बिजनौर



मुकेश गुप्ता पलक अग्रवाल
सभासद वार्ड नं. 16, न. पा. परि. नहतौर
IVF नगर अध्यक्ष



केंद्रीय बजट प्रगतिशील व भविष्योन्मुखी: नीतीश

पटना, (भाषा)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी वाला बताते हुए रविवार को कहा कि इससे विकसित भारत के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले दिन में संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है।



उन्होंने लिखा, 'यह बजट प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी वाला है। देश के विकास की गति तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे विकसित भारत का विजन वास्तविकता बनेगा। कुमार ने बेहतर, प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि सात उच्च-गति रेल कॉरिडोर की घोषणा से देश के रेल अवसरचना के आधुनिकीकरण और लंबी दूरी की

लाभ मिलेगा, राज्य के उत्पादों के निर्यात में सुविधा होगी और वाणिज्यिक व व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में बड़े टेक्स्टाइल पार्कों (कपड़ा उद्योग से जुड़ी इकाइयां) की स्थापना और महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की घोषणा भी की गई है। कुमार ने कहा, 'इसके साथ ही बजट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ रुपये की नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास और तेज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार सृजन के लिए पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र व विशेष ध्यान देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा, 'इससे बिहार को औद्योगिक निवेश, अवसरचना और युवाओं के लिए आर्थिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, शहरी विकास के लिए बजट में किए गए प्रावधान बिहार में शहरीकरण को नई गति देंगे।

केंद्र के आंकड़ों की बाजीगरी वाला बजट: ममता बनर्जी

कोलकाता, (भाषा)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि 2026-27 का केंद्रीय बजट दिशाहीन एवं अदूरदर्शी आंकड़ों की बाजीगरी है तथा उसमें आम लोगों एवं उनके राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। बनर्जी ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर प्रचारकों के साथ बातचीत में यह भी आरोप लगाया कि बजट में प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि में भारी कटौती की गई है। उन्होंने आरोप लगाया, यह बजट दिशाहीन है, अदूरदर्शी, नीरस एवं जनविरोधी है। यह बजट महिला-विरोधी, किसान-विरोधी, शिक्षा-विरोधी है तथा यह अनुसूचित जाति (एससी),



नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (एएनआई) अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भी खिलाफ है...। बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया, शिक्षा के लिए आवंटित धन और सब्सिडी में कटौती की गई है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा सब्सिडी

बजट विकास की दिशा में मील का पत्थर : पंकज चौधरी

लखनऊ, (भाषा)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जनोन्मुखी बजट करार दिया है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में प्रस्तुत किया गया भारत का आम बजट देश की आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, 'मैं केंद्रीय बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि केंद्रीय बजट 2026-27 भारत के आर्थिक विकास को नई गति देने, नागरिकों की आकांक्षाएं पूरा करने व उनकी क्षमता बढ़ाने, विकसित भारत के लिए दक्ष एवं पेशेवर युवाओं को तैयार करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होंने सीतारमण को लगातार नौवीं बार संसद में बजट प्रस्तुत करने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल नारी नेतृत्व की सशक्त मिसाल है, बल्कि भारत के संसदीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय भी है।

जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगी : अखिलेश यादव

लखनऊ, (भाषा)। संसद में रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट 2026-2027 पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेर्य मार्केट हुआ धड़ाम। उन्होंने कहा, 'हमने तो पहले ही कहा था - सवाल ये नहीं है कि शेर्य बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा।



समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बजट सत्र के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए। (एएनआई)

सपा प्रमुख ने कहा, 'जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगी। हम तो भाजपा के हर बजट को 120 का बजट मानते हैं क्योंकि वो पांच प्रतिशत लोगों के लिए होता है।

यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा का बजट, अपने कमीशन और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का बजट होता है। उन्होंने कहा, 'भाजपा का बजट, भाजपाई भ्रष्टाचार का अदृश्य खाता-बही होता है। उन्होंने दावा किया कि इस बजट में न आम

सूरजकुंड मेला घुमाने में पर्यटकों का स्मार्ट साथी बनेगा 'मेला साथी' ऐप

नई दिल्ली, (बीओ)। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला घूमने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से 'मेला साथी' ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस 'मेला साथी' ऐप के जरिए पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इससे देश-विदेश से मेले में पहली बार अपने वाले पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मेला साथी ऐप के जरिये पर्यटकों को स्टॉलों की लोकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, कलाकारों और शिल्पकारों का परिचय, खान-पान जोन, पाकिंग व्यवस्था, आपात सेवाएं और अन्य सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। सूरजकुंड

गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है डाउनलोड

मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में पर्यटकों को लुभा रहे आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स: 39 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ-साथ भव्य और रचनात्मक सेल्फी पॉइंट्स के कारण खासा चर्चा में है। देश-विदेश से आए पर्यटक यहां न केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाओं और व्यंजनों का अंदाज ले रहे हैं, बल्कि खूबसूरती से डिजाइन किए गए सेल्फी पॉइंट्स पर तस्वीरें खिचवाकर यादगार पलों को कैमरे

राकांपा के विलय से पहले मुझे इस बारे में अवश्य सूचित करते अजित पवार : फडणवीस

मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विलय की चर्चाएं अंतिम चरण में होती, तो विगत अजित पवार ने उन्हें इसके बारे में जरूर बताया होता। फडणवीस ने यहां संबद्धताओं से कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सभी तरह की जानकारी उनके साथ साझा करते थे। राकांपा (शप) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि उनके भतीजे एवं राकांपा नेता अजित पवार ने दोनों गुटों के बीच विलय की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर ली थी, लेकिन अब उनकी (अजित पवार) मौत के कारण विलय की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अजित पवार और शरद पवार के बीच 17 जनवरी को हुई बैठक का

एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फडणवीस ने हालांकि रविवार को कहा कि उन्हें अजित पवार की चाचा शरद पवार के साथ हुई बातचीत की जानकारी नहीं है और उन्हें 12 फरवरी की तारीख के बारे में भी नहीं पता। मुख्यमंत्री ने कहा, क्या राकांपा के विलय की बातचीत हमारी जानकारी के बिना अंतिम रूप ले सकती है? हमें 12 फरवरी की उस तारीख की जानकारी नहीं है जिसे विलय की औपचारिक घोषणा की तारीख बताया जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि राकांपा एक स्वतंत्र पार्टी है जो अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी होने के नाते, उसके आगे बढ़ने से पहले भाजपा से परामर्श करने की उम्मीद की जाती है।

केंद्रीय बजट हिमाचल के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्ण: सीएम

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, नानावनों और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से निराश हैं। मध्यम वर्ग को आयरक में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसे राजस्व घाटा अनुदान (आरडीओ) कहा जाता है। वर्ष 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग के

गठन तक केंद्र सरकार द्वारा ये अनुदान नियमित रूप से राज्यों को दिए जाते रहे हैं। लेकिन पहली बार 16वें वित्त आयोग ने इस अनुदान को बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के दौरान लगभग 37,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान दिए गए थे। उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि 14वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद, जब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने में देरी हुई थी, तब भी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 11,431 करोड़ रुपये की सहायता राज्यों को प्रदान की गई थी। इससे भी अधिक वित्तजनक है। 16वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और पहाड़ी राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीओ) की सिफारिश करना। यह निर्णय राज्य की संरचनात्मक वित्तीय चुनौतियों, 67 प्रतिशत से अधिक वन एवं पारिस्थितिक आवरण, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति सेवा वितरण की अधिक लागत और हाल के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्राकृतिक आपदा नुकसान की घोर उपेक्षा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि आरडीओ की समाप्ति से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिरता, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति और विकासत्मक निवेश गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इससे राज्य को सेवा वितरण और बढ़ते कर्ज के बीच कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बार-बार पक्ष रखने, विप्लव ज्ञापन और तकनीकी प्रस्तुतियों के बावजूद केंद्र सरकार और वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश की वास्तविकताओं को नजरअंदाज किया जो पूर्णव्यापक है। यह स्थिति इस आशंका को और मजबूत करती है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

केंद्रीय बजट से हरियाणा को मिलेगी ऐतिहासिक गति: मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, (बीओ)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे हरियाणा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, उद्योग और युवाओं के रोजगार को नई दिशा और नई ऊर्जा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार है जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया गया है। यह केंद्रीय नेतृत्व के दूरदर्शी विजन और देश को तेजी से आगे ले जाने के मजबूत संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों आर्थिक वृद्धि को तेज करना, लोगों की क्षमताओं व आकांक्षाओं का निर्माण



करना और 'सबका साथ, सका विकास' की भावना से प्रेरित है। इसका सीधा लाभ हरियाणा के युवाओं, किसानों, महिला शक्ति, एमएसएमई और श्रमिक वर्ग को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस जनहितैषी बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2

योगदान देता है, इससे मजबूत और स्थिर वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़कों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर किया जाएगा, जिससे जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय देशभर में रेल, सड़क, आरआरटीएस, इवी चाजिंग नेटवर्क, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देगा। हरियाणा में आईएमटी (खरखोटा, मानेसर और अन्य क्षेत्रों में नए निवेश आएं, जिससे लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आरआईडीएफ और यूआईडीएफ में बढ़ोतरी से ग्रामीण और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय बजट ने महाराष्ट्र की अनदेखी की : आदित्य ठाकरे

मुंबई, (भाषा)। शिवसेना (उबाटा) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के बारे में नागरिकों में कोई विश्वास नहीं जागाया और सरकार के खजाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले महाराष्ट्र को अनदेखी की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके आदित्य ने एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह चुनावों से परे मुद्दों के बारे में सोचें, तो यह वास्तव में भारत के लिए एक उपहार होगा। उन्होंने लिखा, 'महाराष्ट्र को अनदेखी की गई, जो केंद्र सरकार के खजाने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। चाहे जीडीपी हो, जोईएसटी हो या आयकर, महाराष्ट्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, लेकिन वह अनुपातिक रूप से सबसे अधिक उपेक्षित है। आदित्य ने मुंबई और पुणे तथा सात अन्य शहरों के बीच हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर के संबंध में बजट में भी कोई घोषणा को लेकर सवाल किया कि केंद्र या राज्य सरकार में से कौन इस परियोजना को वित्त पोषित करेगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैथिली भाषा के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार का सकारात्मक कदम

पटना, (बीओ)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में शून्य काल के दौरान मैथिली लिपि (तिरहुत/वैदेही लिपि) को गूगल कीबोर्ड और एंड्रॉइड-आईओएस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राकृतिक, सहज और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने की मांग उठाने के लिए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा का धन्यवाद किया है। जितिन प्रसाद ने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली मैथिली भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने बताया कि मैथिली (देवनागरी) को यूनिकोड के मौजूदा देवनागरी कोड चार्ट में शामिल किया गया है, जिसके कारण यह बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन (बीएमपी) का हिस्सा है। उन्होंने डिजिटल माध्यमों पर इसका उपयोग सुचारु रूप से हो रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तिरहुत/वैदेही लिपि के लिए

डिजिटल सपोर्ट अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती मांग, प्रतिक्रिया और तकनीकी अपडेट के साथ इसमें लगातार सुधार किया जा रहा है। इस दिशा में ठोस पहल करते हुए तिरहुत लिपि के लिए डिस्ट्रो, कीबोर्ड इनपुट और यूनिकोड-अनुरूप टेक्स्ट प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं विकसित करने हेतु एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को पत्र भेजे गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे जानकारी दी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा डिजिटल मानकों की समीक्षा, सुधार और उनके प्रभावी अनुपालन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सचिव की अध्यक्षता में एक 'डिजिटल मानक समिति' का भी गठन किया गया है। संजय कुमार झा द्वारा मैथिली भाषा और उसकी लिपियों को डिजिटल युग में समुचित स्थान दिलाने के लिए उठाया गया यह विषय लाखों मैथिली भाषियों की भावना और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है।

बजट भारत को वैश्विक बायो-फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम: सम्राट चौधरी

पटना, (भाषा)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट (2026-27) की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट भारत को वैश्विक बायो-फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से भारत के बायोफार्मास्ट्रिकल क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है।

नवाचार क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके चौधरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत को वैश्विक बायो-फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिच्यय के साथ बायो फार्मा शक्ति परियोजना बायोलाॅजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी।

माघी पूर्णिमा पर करीब 1.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई

वीर अर्जुन संवाददाता प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे माघ मेले में रविवार को माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर दोपहर 12 बजे तक करीब 1.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम और गंगा में डुबकी लगाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मेला प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद शनिवार आधी रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आगमन और गंगा स्नान जारी है। उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर 12 बजे तक करीब 1.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले एक महीने से मेले में कल्याण कर रहे कल्पवासियों का रविवार को अंतिम गंगा स्नान है, इसलिए उनके परिजन उन्हें घर वापस



ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह घने कोहर के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सभी घाटों पर स्नान सुचारु रूप से जारी है। उन्होंने कहा, सभी घाटों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राज्य आपदा मोचन बल

(एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम तैनात है। इसके अलावा नाविकों और गोताखोरों को भी सभी घाटों पर तैनात किया गया है। वर्मा ने बताया कि मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी को जा

रही है और सभी अधिकारी मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। त्रिवेणी संगम आरती सेवा समिति के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र मिश्र ने बताया कि माघ मेले में करीब पांच लाख कल्पवासियों का एक माह का कल्पवास माघी पूर्णिमा स्नान के साथ संपन्न हो जाएगा और आगामी

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में हैं केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री यादव

भोपाल (ब्यूरो प्रमुख)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है।

5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण



और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट की सभी क्षेत्रों में सराहना हो रही है। केन्द्रीय

विचारों के आदान-प्रदान के बाद केन्द्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट की सभी क्षेत्रों में सराहना हो रही है। केन्द्रीय

बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टैक्सटाइल

क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर को दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री का अभिवादन किया। बजट में इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रतियोगिता आसान करने की व्यवस्था है। राजकोषीय घाटे का 4.33 का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है, जिससे मध्यप्रदेश को भी लाभ प्राप्त होगा। भारत को बायोफार्मा हब बनाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का भी विकास होगा। केन्द्रीय बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान किए गए हैं। इससे बुजुर्गों के

इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारियों को दवाई भी सस्ती होगी, जिससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी। केन्द्रीय बजट में विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास करने को प्राथमिकता दी गई है, इससे भारत ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब बनेगा। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ए.आई. के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त गाइड उपलब्ध कराने की व्यवस्था से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित स्थलों को खोलने के निर्णय से देश-विदेश के लोग हमारी समृद्ध प्राचीन विरासत से परिचित और प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों को टैक्स में दी गई राहत से वैश्विक स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट सबका साथ- सबका विकास की भावना के अनुरूप है।

वैदिक घनाद सनातन संस्कृति का मूल आधार : कमलेश मिश्र यज्ञाचार्य

रायपुर, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। वैदिक सनातन संस्कृति घनाद हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। जिस पर सम्पूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली से निपुण संस्कारवान संतति से विश्व में भारत का नाम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को आलोकित करता रहा है। भारतीय प्राचीन संस्कृति में ज्योतिष वास्तु यज्ञ अनुष्ठान संस्कार कथा प्रवचन शांति सेवा और पवित्र पूजन पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज विश्व में भारत अपनी सम्पन्न संस्कृति से पहचाना जाता है।

उत्कृष्ट उद्गार वैदिक घनाद संस्थान के आचार्य कमलेश मिश्र यज्ञाचार्य ने प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित प्रकाशकारवां में व्यक्त किए। आचार्य मिश्र ने बताया कि वे विगत 30 वर्षों से वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए देश-विदेश में प्रयासरत हैं। वैदिक मंत्रों एवं अनुष्ठानों का आयोजन

भारत सहित विदेशों में भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में मुम्बई हैदराबाद, बैंगलोर, पटियाला, प्रयागराज, चंडीगढ़, सूरत, हरियाणा, इंदौर, गुडगांव लखनऊ आदि में निवासरत लाखों श्रद्धालु उनके जन जागरूकता अभियान से जुड़े चुके हैं। उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति वहां निवासरत लोगों में काफी अनुराग है। दुबई, ओमान, वाशिंगटन, इंग्लैण्ड, सिंगापुर में वैदिक घनाद आयोजन के दौरान वहां के निवासियों ने वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने में अपनी रूचि का प्रदर्शन किया। संस्था का मूल उद्देश्य जनसामान्य में सनातन संस्कृति का प्रचार-प्रसार और जोड़ना है। संस्था की भावी योजनाएं, भावी पीढ़ी को मंत्रोच्चारण, नित्य कर्म पद्धति, श्लोक, वैदिक शिक्षा के अध्ययन के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षित करना है।

ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिलायंस के कार्य सराहनीय: जयसिंह

वीर अर्जुन संवाददाता शहडोल । रिलायंस सीबीएम परियोजना शहडोल की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चौथी शहडोल जूनियर फुटबॉल लीग का आयोजन 28 से 30 जनवरी 2026 तक शासकीय मिडिल स्कूल मैदान लालपुर में सफलतापूर्वक किया गया। समापन समारोह के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित किए गए। इसके पश्चात रिलायंस सीबीएम परियोजना के ऑर्गनाइजर एवं मेटेनेंस हेड फणीधर अडला द्वारा मुख्य अतिथि जैतपुर विधायक जयसिंह मरावी का शाल्लश्रीफलन पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। सीबीएम टीम द्वारा अन्य सभी अतिथियों का भी पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एवं रूपरेखा बताते हुए साइट सीएसआर हेड राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि इस तीन

दिवसीय फुटबॉल लीग में कुल 30 टीमों ने भाग लिया, जिनमें रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित 13 फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्रों की 26 टीमों तथा परियोजना क्षेत्र के बाहर से बिचरपुर, ज्ञानोदय रेलवे एवं धनपुरी की 04 टीमों शामिल रही। प्रतियोगिता में 400 से अधिक ग्रामीण बालक एवं बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने रिलायंस सीबीएम परियोजना द्वारा शहडोल जिले के ग्रामीण अंचलों में फुटबॉल के विकास हेतु किए जा रहे सतत एवं समग्र प्रयासों की भी जानकारी दी। प्रतियोगिता के फाइनल मुकामलों में बालिका वर्ग में रिलायंस फाउंडेशन प्रशिक्षण केंद्र, कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर की टीम विजेता रही, जबकि बालक वर्ग में रिलायंस फाउंडेशन एकलव्य ध्रुवार प्रशिक्षण केंद्र की टीम ने खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में जैतपुर विधायक श्री जयसिंह मरावी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्री रईस अहमद

सहायक संचालक खेल शहडोल संभाग, लालपुर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रामकली बैगा, जनपद सदस्य निसाबि नयक, उपसरपंच दीपू सिंह, फणीधर अडला, साइट ऑर्गनाइजर एवं मेटेनेंस हेड तथा सुशील शरण, साइट प्रोडक्शन हेड, रिलायंस सीबीएम परियोजना विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विधायक जयसिंह मरावी ने अपने संबोधन में रिलायंस सीबीएम परियोजना द्वारा शहडोल जिले में फुटबॉल के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मैचों के दौरान खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित खेल तनिकों की प्रशंसा करते हुए बच्चों से शिक्षा एवं शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर फुटबॉल कोच के रूप में विकसित करना एक अभिनव एवं सराहनीय पहल है, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है तथा बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करती है।

कोरबा (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का सफल आयोजन किया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी की मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया। सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर करतला से हाटी रोड पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोरबा कलेक्टर श्री कुणाल देवदत्त एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान सड़क किनारे स्थित पेड़ों पर कलर एवं रेडियम पट्टी लगाए जाने का अभियान चलाया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने स्वयं श्रमदान करते हुए पेड़ों पर रेडियम पट्टी लगाई और रात्रि के समय वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता उपलब्ध कराने का संदेश दिया, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सड़क जिलेभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें स्कूल एवं कॉलेजों

में 12 यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2820 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। एक हेलमेट रैली में करीब 150 नागरिकों ने सहभागिता की, जबकि नुकुड नाटक के माध्यम से लगभग 400 लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 9 जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लगभग 1910 नागरिकों को लाभान्वित किया गया। सड़क सुरक्षा पोस्टर चस्पा कर करीब 1000 नागरिकों तक संदेश पहुंचाया गया। यातायात नियमों का पालन करने वालों को गुलाब देकर सम्मानित करने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 350 लोगों को प्रोत्साहित किया गया। वही, स्कूली वाहनों की जांच हेतु एक विशेष अभियान में 75 वाहनध्व्यक्तियों की जांच की गई। इस सभी गतिविधियों के माध्यम से कुल 27 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसने लगभग 6705 नागरिक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हुए। कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा सुरक्षित गति से वाहन चलाएं।

तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खांडे, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम अध्यक्ष क्षितिज सिंघल, सुमित मिश्रा आदि भी विशेष रूप से मौजूद थे।

2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट: अमिता चपरा

वीर अर्जुन संवाददाता शहडोल । 1 फरवरी 2026 को 80 वां केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया शहडोल नगर के जिला भाजपा कार्यालय में केन्द्रीय बजट का प्रसारण भाजपा जिला जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा को उपस्थिति में लाइव प्रसारण के माध्यम से एलईडी स्क्रिन पर बजट का लाइव प्रसारण देखने के लिए भाजपा जिला पदाधिकारी, बरिष्ठ भाजपा नेता, मंडल अध्यक्ष गण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण, जिले के संप्रभू नागरिक गण, व्यापारी बंधु, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसान, युवाजन, प्रबुद्धजन, समाजसेवी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता ने बजट का लाइव प्रसारण देखा व सुना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा सदन के पटेल पर वर्ष 2026-27

आम बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया यह बजट विकसित भारत और युवाओं महिलाओं किसानों और गरीब मजदूरों 2047 विकसित और समृद्ध भारत निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य सड़क पानी एवं भारत को आत्मनिर्भर की दिशा से जोड़ने के लिए केन्द्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। उक्त आशय के उद्गार भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एके श्रीवास्तव ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मंडिकल के क्षेत्र में बजट से हातिकाकारी बदलाव होगा। मंडिकल के लिए 10000 करोड़ बायो मेडिकल के लिए रखा गया है, जिसके कारण कैंसर व डायबिटीज व अन्य प्रकार

की बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयां उपलब्ध होगी और सभी वर्गों को सस्ती चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होगी। बजट कार्यक्रम के संयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2026-2027 के केन्द्रीय बजट (जो 2027 के वित्तीय वर्ष के लिए है) में महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास (उर्दू ट्रेनिंग) का निर्माण, कक्षाकामी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास, तथा उद्यमिता बढ़ाने के लिए एंटी-ई और 210,000 करोड़ का एंटी-ग्रोथ फंड है। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश शुक्ला ने पेश किए गए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट में नवीन आयकर अधिनियम कई मामलों में ऐतिहासिक और हातिकाकारी साबित होगा। यह सब बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा है।

संतों की वाणी आज भी समाज को सकारात्मक दिशा दे रही है : डॉ. यादव

भोपाल (ब्यूरो प्रमुख)। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संतों की वाणी आज भी समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रही है। रिवार को इंदौर प्रवास के दौरान संत रविदास जयंती के अवसर पर नगर निगम के झोन कार्यालय फ्लॉक-1 में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संत रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती की। इस अवसर पर उन्होंने संत रविदास जी के सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश को स्मरण किया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान से जुड़ी 'स्वच्छता दीदियों' का पुष्पहार से स्वागत किया और उनके योगदान की सराहना करते हुए अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पहचान पूरे देश



के लिए प्रेरणास्रोत है और इसमें स्वच्छता कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी नागरिकों से संत रविदास के विचारों को संत रविदास करते हुए स्वच्छ, समरस और जागरूक समाज के निर्माण में सहभागिता बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री

तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खांडे, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम अध्यक्ष क्षितिज सिंघल, सुमित मिश्रा आदि भी विशेष रूप से मौजूद थे।

महंगी जमीन को धोखे से बेचा, मां ने बेटे के खिलाफ की शिकायत

रायपुर, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। जिले की रहने वाली एक महिला ने अपने ही बेटे और उसके दोस्त पर धोखाधड़ी कर जमीन-मकान बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता मनोरमा भिवंडे निवासी अमर चौक शर्मा बाड़ा राजातालाब रायपुर ने बताया कि अमलेश्वर शिखर प्रीति विहार के सामने उनके नाम पर 1420 वर्गपीट की जमीन है, जिस पर उन्होंने मकान का निर्माण कराया है। पैसों की आवश्यकता होने पर उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रवीण भिवंडे और उसके दोस्त पारस प्रसाद केसरी को केवल लोन निकलवाने के उद्देश्य से ठग पुस्तिका और रजिस्ट्री के कागजात दिए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पोर्टो काराक दस्तावेज लौटा दिए जाएं। मामला दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना इलाके का है। महिला का आरोप है कि उनके बेटे और उसके दोस्त ने आपसी मिलीभगत से उनकी अनुपस्थिति और बिना जानकारी के उस जमीन और मकान को विभाजित गुप्ता नाम के व्यक्ति को पर्जा तरीके से बेच दिया। इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें 16 जनवरी 2026 को मिली, जब उन्होंने देखा कि मकान में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी हुई। 17 जनवरी को जब मनोरमा भिवंडे अपने बच्चों के साथ अमलेश्वर स्थित मकान पहुंची, तो वहां निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों और विभाजित गुप्ता से पूछताछ में चौकाने वाले खुलासे हुए। बताया गया कि प्रवीण भिवंडे और पारस प्रसाद केसरी ने 17 लाख रुपए में इकरारनामा कर 5.50 लाख रुपए कैश एडवांस लिए हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया कि उसी संपत्ति का सौदा संजना पाण्डेय से 18 लाख रुपए में तय कर 7.50 लाख रुपए लिए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि 7.50 लाख रुपए उनके बैंक ऑफ न्यूटाइला खाते में आए थे, जिसे बेटे ने यह कहकर निकलवा लिया कि यह किसी मित्र की रकम है और इसमें से उन्हें कमीशन मिलेगा। बाद में उन्हें समझ आया कि यह रकम संपत्ति के सौदे से जुड़ी थी। महिला ने आरोप लगाया कि, उनके नाम से दो पर्जा इकरारनामा और एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है, जबकि उन्होंने किसी भी नोटरी के सामने हस्ताक्षर नहीं किए और न ही किसी प्रकार की रकम प्राप्त की। पीड़िता ने पुलिस से भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ठेकेदार की फिल्टर प्लांट में मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी

बलौदाबाजार, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। जिले के नगर पंचायत पलारी में उस समय हड़कप मच गया, जब महानदी नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार की लाश फिल्टर प्लांट परिसर में मिली। मृतक का शव रोहंसी रोड स्थित फिल्टर प्लांट की ऊपरी मंजिल पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जिसके माथे पर हल्के चोट के निशान और खून बहने के प्रमाण मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है। ठेकेदार उस समय कार्यस्थल पर अकेला था। जबकि, मजदूर महानदी-अमेठी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कार्य में गए हुए थे। इसी दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन पोंग कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर अधिकारियों ने एक कर्मचारी को मौके पर भेजा। कर्मचारी जब फिल्टर प्लांट की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां ठेकेदार का शव जमीन पर पड़ा मिला, जिसके बाद तत्काल थाना पलारी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को जांच की। प्रारंभिक जांच में कोई भी वस्तु या परिस्थिति संदिग्ध नहीं पाई गई। कमरे की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉरिसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अपचारी बालकों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, तीन वाइक बरामद

कोरबा (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाइन रामपुर एवं चौकी सीएसईबी की संयुक्त टीम ने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार थाना सिविल लाइन रामपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 80/2026 एवं अपराध क्रमांक 599/2025 (धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता) के तहत दर्ज मामलों में अपचारी बालकों को अधीरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं स्वीकार की। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि अपचारी बालकों द्वारा होडा लिबो मोटरसाइकिल (सीजी 11 एन्यू 9955) को बलौदा, जिला जांजगीर-चोंपा से चोरी कर कोरबा लाया गया था। संबंधित थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त वाहन के संबंध में अपराध क्रमांक 326/25, धारा 303(2) बीएनएस के तहत 01 अगस्त 2025 को चोरी दर्ज है। थाना सिविल लाइन रामपुर एवं चौकी सीएसईबी की संयुक्त कार्रवाई में अपचारी बालकों के कब्जे से कुल 03 नम चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। बरामद वाहनों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में संलिप्त अपचारी बालकों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिभंग्यमत्त कार्रवाई कर उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

तीरथगढ़ माघ पूर्णिमा मेले की शुरुआत, विधायक किरण देव का लोक परंपरा से स्वागत

जगदलपुर, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। बस्तर के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल तीरथगढ़ जलप्रपात में आयोजित माघ पूर्णिमा मेले का शुभारंभ शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक किरण देव ने किया। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाले इस तीन दिवसीय मेले में क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में आगमन पर ग्रामवासियों ने विधायक का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर ध्रुवा नाचा दल ने अपनी लोकनृत्य प्रस्तुति से अतिथियों का अभिनंदन किया, जिसने कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। साधा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बस्तर की कला, संस्कृति और परंपराएं पूरे देश में विशिष्ट पहचान रखती हैं। यहां के मेले, मंडई, जात्रा और लोक उत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। उन्होंने मेला आयोजन से जुड़े सभी ग्रामवासियों को बधाई देते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि तीरथगढ़ जलप्रपात की ख्याति देश-विदेश तक फैली हुई है। माघ पूर्णिमा मेले के दौरान यहां हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करती है। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी, जनपद अध्यक्ष मानकदेश कश्यप, उपाध्यक्ष हरिप्रसाद कश्यप, मंडल अध्यक्ष देवीप्रसाद बेजाम, सरपंच मंगलू कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन मौजूद रहे।

माघ पूर्णिमा पर स्नान-दान का महापर्व राजिम कल्प कुंभ का शुभारंभ

रायपुर, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। माघ पूर्णिमा के पवन अवसर पर रवि पुण्य और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। राजधानी के महादेवघाट में श्रद्धालु पुण्य स्नान करेंगे, वहीं राजिम त्रिवेदी संगम पर आज से कल्प कुंभ का शुभारंभ होगा। स्नान-दान, व्रत पूजन की विशेष तिथि माघ पूर्णिमा रविवार को है। पंडितों के अनुसार इस पुण्य तिथि पर रवि पुण्य और सर्वार्थ सिद्धि योग में हजारों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर विशेष प्लत प्राप्त करेंगे। राजधानी के पवित्र धार्मिक स्थल महादेवघाट में सुबह से आस्था का मेला लगेगा और राजिम त्रिवेदी संगम पर कल्प कुंभ शुरू होगा। जिसका समापन महाशिवरात्रि पर्व पर होगा।

केंद्रीय बजट से हरियाणा को मिलेगी ऐतिहासिक गति: मुख्यमंत्री

पवन आश्री
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे हरियाणा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, उद्योग और युवाओं के रोजगार को नई दिशा और नई ऊर्जा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार है जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया गया है।

यह केंद्रीय नेतृत्व के दूरदर्शी विजन और देश को तेजी से आगे ले जाने के मजबूत संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट तीन

हरियाणा को बजट में कोई नई सौगात नहीं : आप नेता सुरेंद्र राठी

पंचकूला, (पवन आश्री)। केंद्रीय बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व लोकसभा अध्यक्ष अंबाला सुरेंद्र राठी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट हरियाणा समेत देश के आम नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। हरियाणा के लिए किसी भी नए बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की गई, जिससे प्रदेशवासियों में निराशा है। राठी ने कहा कि बजट पेश होते ही शेयर बाजार में गिरावट आई, जिससे पहले से महंगाई और बेरोजगारी से जुड़ा रहे मिडिल क्लास की परेशानियाँ और बढ़ गईं। उन्होंने इस बजट को 'फैंक और लोपट्टू' बताया है, जो विकास के लिए नारा केवल एक मजाक बनकर रह गया है।



प्रमुख कर्तव्यों आर्थिक वृद्धि को तेज करना, लोगों की क्षमताओं व आकांक्षाओं का निर्माण करना और 'सबका साथ, सका विकास' की भावना से प्रेरित है। इसका सीधा लाभ हरियाणा के युवाओं, किसानों, महिला शक्ति, एमएसएमई और श्रमिक वर्ग को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस जनहितैषी बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय हरियाणा जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य

के लिए बरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्यों को कुल 1.4 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्तव्य देने का प्रावधान किया गया है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। हरियाणा, जो केंद्र को करों में बड़ा योगदान देता है, इससे मजबूत और स्थिर वित्तीय

विकसित भारत के लिए बजट, लोगों तक विकास की लहर पहुंचेगी: बड़ौली

सोनीपत/चंडीगढ़ (पवन आश्री)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने सोनीपत के भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाले बजट को कार्यकर्ताओं के साथ लाइव देखा और सुना। लाइव बजट सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह बजट हरियाणा के विकास को नई गति देगा और आने वाले समय में इंफ्रा, कृषि और रोजगार पर बड़ा फोकस रहेगा। श्री बड़ौली ने कहा कि वित्तमंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट में विकास का लाभ सभी समाज के लोगों तक पहुंचाने पर फोकस है। श्री बड़ौली ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले बजट की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का आभार जताया। बड़ौली ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की यात्रा को और तेज करेगा। यह युवा शक्ति बजट है। युवाओं की सोच और सपने बजट में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा



कि बजट में आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत मजबूती मिलेगी। सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर बजट में दिया गया है। श्री बड़ौली ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना ही बजट का मूल लक्ष्य है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश गए बजट ने हरियाणा के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए

केंद्रीय बजट 2026-27 ग्रामीण भारत, पंचायती राज को मजबूत करेगा: कृष्ण लाल पंवार

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट जन-केंद्रित और दूरदर्शी है, जिसका लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास को भावना और विकसित भारत2047 के लक्ष्य के अनुरूप समाज के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए है। वित्त मंत्री और उनकी टीम के समर्पण और दूरदर्शिता की प्रशंसा करते हुए श्री पंवार ने कहा कि ग्रामीण संरक्षण और ग्राम स्वशासन से संबंधित केंद्रीय बजट के मुख्य

बजट में घोषित 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल' खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और गांवों में उद्योगों को मजबूत करने में मदद करेगी

प्रवधान महात्मा गांधी के आदर्शों और दृष्टिकोण से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल' खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और गांवों में उद्योगों को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे खादी वस्त्रों के उत्पादन में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से पारंपरिक बुनकरों को फायदा होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विकास और पंचायत मंत्री ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी आगामी बजट 2026-2027

आवंटित करते समय विकास और पंचायत विभाग पर विशेष जोर देंगे। उन्होंने कहा कि यह विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और ज़मीनी स्तर पर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री पंवार ने आगे विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय बजट 2026-27 समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होगा और पूरे देश में समावेशी और सतत विकास को गति देगा।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन पंजीकरण

कुरुक्षेत्र, (प्रकृति आश्री)। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपत्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी मुठी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बी.पी.एल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

पंडित जसराज की जयंती पर आज

पीलीमंदोरी में होगा राज्य स्तरीय समारोह
चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा सरकार द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विख्यात पंडित जसराज जी की जयंती पर जिला फतेहाबाद के गांव पीलीमंदोरी में 2 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुंबई से पंडित जसराज जी के परिजनों के साथ कई प्रसिद्ध संगीतकार और भजन गायक शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में गायक सोनू निगम व अनूप जलोटा सहित अन्य विख्यात कलाकारों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पंडित जसराज जी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने भारतीय संगीत में अद्वितीय योगदान दिया तथा अपनी मधुर आवाज से विचर में भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर को समृद्ध किया।

पुलिस ने छात्र/छात्राओं को जागरूक किया

कुरुक्षेत्र, (प्रकृति आश्री)। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्ग-दर्शन में जिला को नशामुक्त बनाने को लेकर पुलिस टीम के लगातार कार्य कर रही है। पुलिस की नशामुक्त टीम गांव दर गांव नशामुक्ति का सन्देश पहुंचा रही है। रविवार को जिला पुलिस के ग्राम प्रहरी नोडल ऑफिसर सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार व ऋषिपाल की टीम नशामुक्ति का सन्देश लेकर डीवीए पब्लिक स्कूल ग्राम खेडी रामनगर कम्युनिटी सेंटर पहुंची तथा छात्र/छात्राओं को जागरूक किया। पुलिस टीम ने छात्र/छात्राओं को नशा न करने की शपथ दिलावाई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रविवार को ग्राम प्रहरी नोडल ऑफिसर राजेश कुमार ने डीवीए पब्लिक स्कूल ग्राम खेडी रामनगर कम्युनिटी सेंटर का दौरा कर छात्र/छात्राओं को नशा न करने के प्रति जागरूक किया। छात्र/छात्राओं से बात करते हुए ने सहायक उप निरीक्षक ने कहा कि पुलिस और छात्र/छात्राओं व समाज एक के साथ कार्य करे तो नशे जैसी बुराई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने स्कूल में छात्र/छात्राओं से कहा कि यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति नशा करता है या नशा बेचता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सहायक उप निरीक्षक ने छात्र/छात्राओं को नशा न करने की शपथ दिलाई और बच्चों से अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर पढ़ाई और खेलों में अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।

अवैध शराब बेचने का आरोपी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र, (प्रकृति आश्री)। जिला पुलिस ने अवैध शराब बेचने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्ग-निर्देश में थाना शाहबाद की टीम ने बिना लाईसेंस शराब बेचने के आरोप में कुनाल वासी माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 8 बोतल ठेका शराब देशी बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया 31 जनवरी 26 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना शाहाबाद प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुमार के दिशा-दर्शन में सहायक उप निरीक्षक यादवेन्द्र व संदीप कुमार की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध अनाज मंडी के पास मौजूद थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुनाल वासी माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र अवैध शराब बेचता है। पुलिस टीम ने मिली सूचना के आधार पर अनाज मंडी के पास सैकड़ गेट से कुनाल को बिना लाईसेंस/अनुमति के शराब बेचने के आरोप में काबू किया। आरोपी के कब्जा से 8 बोतल ठेका शराब देशी बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत के निर्देशानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया।

ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र, (प्रकृति आश्री)। जिला पुलिस ने अलग-अलग मामलों में ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के दो आरोपियों को प्रोडक्शन वार्ड पर लेकर मामले में गिरफ्तार किया है। थाना लाडवा की टीम ने ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के आरोप में साजिद व अरफात वासीयान जिला सहारनपुर थपू की प्रोडक्शन वार्ड पर लेकर मामले में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एसडीओ विजली विभाग लाडवा कुरुक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के माध्यम से बताया गया कि मामला नामालूम चोरी द्वारा 1 फरवरी 25 व 4 मार्च 25 की रात्रि को थाना लाडवा एरिया वासी किसानों के खेतों से 16/20 केवीए ट्रांसफार्मरों से सामान चोरी कर लिया था।

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली नई दिशा: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गई घोषणाएं हरियाणा में स्वास्थ्य अवसरचना को सुदृढ़ करेंगी और आम जनता को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगी।

केंद्रीय बजट 2026 आत्मविश्वास और अवसरों का बजट : सांसद नवीन जिन्दल

कुरुक्षेत्र/कैथल/रादौर (प्रकृति आश्री)। सांसद नवीन जिन्दल ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित 'कैलिब्रेटेड रियलिज्म' की भावना को प्रतिबिंबित करता है और देश के भविष्य को लेकर विश्वास का बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति देने वाला सिद्ध होगा। सांसद नवीन जिन्दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि यह बजट 'अवसरों का राजमार्ग' है, जो देश के युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नए द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि यह दूरदर्शी बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि बजट में विनिर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढांचे,

विषयों को कवर किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में इससे लगभग एक लाख नए एएनपी तैयार होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आरती सिंह राव ने बजट में प्रस्तावित मजबूत केयरगिविंग इकोसिस्टम को भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जैरियाट्रिक केयर और एलाइड केयर सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एनएएसक्यूएफ से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से मल्टी-स्किलड केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य, योग और मेडिकल व सहायक उद्योगों के संकलन जैसी क्षमताओं को जोड़ते हुए आने वाले वर्षों में 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाना एक दूरदर्शी कदम है। मेडिकल वैल्यू चूरीय को बढ़ावा देने के लिए पांच चूरीय मेडिकल सेंटरों की स्थापना के प्रस्ताव को उन्होंने

ऐतिहासिक बताया। निजी क्षेत्र की भागीदारी से बनने वाले ये केंद्र चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ एकीकृत स्वास्थ्य परिसरों के रूप में विकसित होंगे। इनमें आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक्स, पोस्ट-केयर और रिहैबिलिटेशन के लिए मेडिकल वैल्यू चूरीय फैसिलिटेशन सेंटरों भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे डॉक्टरों, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और स्वास्थ्य कर्तव्यों के लिए फायदा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आयुष को लेकर किए गए प्रावधानों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मिली पहचान भारत की सांस्कृतिक विरासत की शक्ति को दर्शाती है। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना, आयुष फार्मेशियाँ और ड्रग टेस्टिंग लैब्स के उन्नयन तथा पारंपरिक चिकित्सा पर प्रमाण-

आधारित शोध को बढ़ावा देने से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और इससे जुड़े युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उन्नयन के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रांमिा केयर के क्षेत्र में बजट को एक बड़ा कदम बताते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि उत्तर भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को कमी को दूर करने के लिए निम्नहांस-2 की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय एपेक्स संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। जिला अस्पतालों के 50 प्रतिशत हिस्से में आपातकालीन और ट्रांमिा केयर सेंटर स्थापित करने की निर्णय भी आमजन के लिए राहतकारी होगा।

हरियाणा में आवश्यकतानुसार नए अस्पताल खोले और अपग्रेड किए जा रहे

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में आवश्यकतानुसार नए अस्पताल खोले जा रहे हैं तथा अपग्रेड किये जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 2 नए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोले, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करने तथा दूसरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बेड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इन सभी पर करीब 55 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि रेवाड़ी जिला के गांव लिसान तथा गांव करारावा मानकपुरा में एक-एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई है, इनमें प्रत्येक पर 50 लाख से 60 लाख रुपये तक

लागत आने का अनुमान है। इसके अलावा, यमुनानगर जिला के रादौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 50 बेड के अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है जिस पर लगभग 36.39 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ जिला के गांव नांगल सिरौही में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पर करीब 17.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी। आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

किसानों, कृषि और ग्रामीण भारत के लिए दूरदर्शी एवं समावेशी बजट है : कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे किसानों, कृषि, मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्रों के लिए दूरदर्शी, संतुलित और परिवर्तनकारी बताया है। श्री राणा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। बजट में किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, युवा सशक्तिकरण और आधुनिक तकनीक को समान प्राथमिकता दी गई है, जो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र

सरकार बुनियादी ढांचे, कृषि लॉजिस्टिक्स, ग्रामीण कनेक्टिविटी, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को तकनीक, नवाचार और उच्च-मूल्य वाली फसलों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश की 46.1 प्रतिशत कृषि कार्यबल को ध्यान में रखते हुए यह बजट छोटे एवं सीमांत किसानों को आया बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। श्री राणा ने कहा कि जलाशयों और अन्य जल स्रोतों के एकीकृत विकास से मत्स्य पालन को

रोजगार का एक मजबूत माध्यम बनाया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा तथा स्टार्टअप, महिला-नेतृत्व वाले समूहों और मछली किसान उत्पादक संगठनों को बाजार से जोड़ा जाएगा। पशुपालन क्षेत्र में क्रेडिट-लिंकड सब्सिडी, पशुधन उद्यमों के आधुनिकीकरण और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से ग्रामीण और परि-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में प्रस्तावित एआई - सक्षम 'भारत विस्तार' के एकीकरण से किसानों को फसल, मौसम और बाजार से जुड़ी सटीक एवं अनुकूलित जानकारी उपलब्ध होगी। इससे जोखिम कम होगा, बेहतर निर्णय संभव होंगे और छोटे किसानों के लिए प्रिंसिपल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा।

बजट 2026-27 विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने वाला: राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2026-27 के आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह बजट हरियाणा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकसित भारत की यात्रा में हरियाणा औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले ही अपनी औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन करते

हुए विकसित हरियाणा का रोडमैप तैयार कर चुकी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि यह बजट देश के समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा को विकसित भारत की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनाए रखने के अनुरूप उद्योग विभाग के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करेंगे। उन्होंने स्मरण कराया कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग का बजट 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 1800 करोड़ रुपये किया था, जो लगभग 125 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि थी। उन्हें विश्वास

है कि इस वर्ष भी यह वृद्धि और अधिक सशक्त रूप में देखने को मिलेगी। श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की थी, जिनमें से पांच पर कार्य प्रगति पर है और शेष पर भी चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी आईएमटी का कार्य पूर्ण करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्व में कोई भी देश केवल कृषि के आधार पर विकसित राष्ट्र नहीं बना वह अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान। औद्योगिक विकास ही इन देशों के विकास की रीढ़ रहा है।

विकसित भारत की ओर निर्णायक कदम : धनखड़

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री चौधरी औपप्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक दूरदर्शी, संतुलित और जनहितैषी बजट है। यह बजट आम आदमी, किसान, युवा, महिला और उद्यमी वर्ग, सभी के सशक्तिकरण का रोडमैप प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देश को शानदार बजट देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आम नागरिक के लिए राहत और अवसर प्रदान करता है यह बजट। महंगाई के प्रभाव को कम करने, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के केंद्रित है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और आधारभूत ढांचे में निवेश से जीवन-स्तर में सुधार होगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औपप्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और कृषि क्षेत्र में सिंचाई, फसल

विविधोकरण, भंडारण, प्रसंस्करण और ग्रामीण अवसरचना के सुदृढ़ीकरण से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। तकनीक-आधारित कृषि, कृषि-उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने से किसानों की समृद्धि का लक्ष्य मजबूत होगा। डेयरी उद्योग बढ़ावा देने की नीति से पशुपालकों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय सचिव श्री धनखड़ ने कहा कि युवा भारत के सपनों को पंख देने के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप, नवाचार और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा-प्रशिक्षण को उद्योग से जोड़कर युवाओं को नौकरी चाहने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में यह बजट निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्रों में निवेश से भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। यह बजट आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ करते हुए भारत को वैश्विक विकास का केंद्र बनाने की क्षमता रखता है। औपप्रकाश धनखड़ ने कहा कि देशवासियों को आश्चस्त करता है कि यह बजट समावेशी विकास, आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित है।

स्टार्टअप, डीप टेक और डेटा सेंटर का नया गढ़ बनेगा हरियाणा : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी ने कहा कि वोक्ल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया के संकल्प को साकार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रही है।

उन्होंने कहा कि "ग्लोकल एआई रियल इम्पैक्ट" केवल एक विषय नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता है, जिसमें वैश्विक सोच को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावित ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित टी.आई.ई. एआई शिखर बजट 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डि डिंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन भविष्य की तकनीक, नवाचार और



उद्यमिता को नई दिशा देने वाला सशक्त मंच है। इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री श्री असीम गोयल, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री जे. गणेशन तथा टी.आई.ई. चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट श्री प्रनीत वर्मा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 275 टी.आई.ई. के अनुसंधान, नवाचार और उत्तरदायी

नीति निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एआई स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों की पहचान और उपचार को अधिक सटीक बना रही है, शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया को सशक्त कर रही है तथा कृषि क्षेत्र में किसानों को उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बाजार और मूल्य संवर्धन में सहायता प्रदान कर रही है। छोटे और मध्यम उद्यम एआई के माध्यम से अपनी दक्षता बढ़ाकर वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एआई को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा एआई मिशन' स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 470 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन प्राप्त

हुआ है। इस मिशन के अंतर्गत गुरुग्राम और पंचकुला में एक-एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार और शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड' की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसे 20 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये से अधिक का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

सूरजकुंड मेला घुमाने में पर्यटकों का स्मार्ट साथी बनेगा 'मेला साथी' ऐप

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला घूमने आने वाले पर्यटकों को सुविधा के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से 'मेला साथी' ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस 'मेला साथी' ऐप के जरिए पर्यटकों को मेले से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इससे देश-विदेश से मेले में पहली बार अपने वाले पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मेला साथी ऐप के जरिये पर्यटकों को स्टॉलों की लोकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय, कलाकारों और शिल्पकारों का परिचय, खान-पान जोन, पार्किंग व्यवस्था, आपात सेवाएं और अन्य सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। सूरजकुंड

►गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है डाउनलोड

►ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध

मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में पर्यटकों को लुभा रहे आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स: 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ-साथ भव्य और रचनात्मक सेल्फी पॉइंट्स के कारण खासा चर्चा में है। देश-विदेश से आए पर्यटक यहां न केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक कलाओं और व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, बल्कि खूबसूरती से डिजाइन किए गए सेल्फी पॉइंट्स पर तस्वीरें खिचवाकर यादगार पलों को कैमरे

में कैद कर रहे हैं। इस वर्ष मेले की थीम राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश की झलक दिखाने वाले सेल्फी पॉइंट्स में उसकी ऐतिहासिक वास्तुकला, भव्य पारंपरिक द्वार और सांस्कृतिक प्रतीकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं मेघालय की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक हट्स को प्राकृतिक परिवेश के साथ दर्शाया गया है, जो पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। इन स्थानों पर दिन भर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है, जो परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

मान ने पीएम को हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की अपील

वीर अर्जुन संवाददाता लुधियाना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज लुधियाना के हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अवसर पर भारत सरकार से हवाई अड्डे का नाम महान शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की अपनी मांग दोहराई और कहा कि यह कदम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के नायकों में से एक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मोहली हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि करने की भी अपील की।

उन्होंने कहा कि पंजाब लगातार उस मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहाँ इसके चारों हवाई अड्डों के नाम राज्य के महान

गुरुओं और शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे को राज्य की आध्यात्मिक और क्रांतिकारी विरासत से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हवाई अड्डे के वर्तुअल उद्घाटन के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापु राम मोहन नायडू की उपस्थिति में यह मुद्दा उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'शहीद करतार सिंह सराभा ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके महान बलिदान ने लाखों लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया और शहीद-ए-आजम भगत सिंह भी उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे।'

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल घोष ने संत शिरोमणि श्री रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की

चंडीगढ़, (वीओ)। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने रविदास जी को लोक भवन में संत शिरोमणि श्री रविदास जी के प्रकाश उत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा, समानता, करुणा और सामाजिक सद्भाव की उनकी कालातीत शिक्षाएं हमें हमेशा एक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

संतों के मार्गदर्शन में कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता: कृष्ण कुमार बेदी

चण्डीगढ़, (वीओ)। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी नितानंद जी का यह धाम आध्यात्मिक चेतना से जोड़ता है। जटोला धाम की यह पवित्र तपोभूमि संतों के आशीर्वाद से आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचान स्थापित कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रविदास जी के जन्मदिन के गांव माजरा दूबलधन स्थित तपोभूमि जटोला धाम स्वामी नितानंद जी महाराज के आश्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब संत मार्गदर्शन करते हैं तो समाज सही दिशा में चलता है और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। स्वामी नितानंद जी महाराज जैसे महान संतों की बढौलत ही मजबूत भारत हमें मिला है। उन्होंने कहा कि स्वामी नितानंद महाराज जी के जीवन मूल्यों को धारण करते हुए समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। स्वामी नितानंद मिशन फाउंडेशन समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के मिशन में निरंतर कार्य कर रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री बेदी ने कहा कि स्वामी नितानंद मिशन फाउंडेशन के साप्ताहिक 225 बेंच का आयुर्वेद चिकित्सायुग मानवता की सेवा का उच्च स्तर का संस्थान बन रहा है। इस संस्थान के बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस संस्थान से झज्जर ही नहीं बल्कि साथ लगते क्षेत्रों के लोगों भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार भी निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रही है। हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्माणार्थी आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महंत राजेंद्र दास महाराज जी ने कहा कि स्वामी नितानंद समाज के महान स्तंभ थे जो समाज को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसे संतों के विचारों पर चलते हुए समाज आगे बढ़ता है।

औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं

रोहतक, (वीओ)। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों से हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, छात्रवृत्ति, विवाह, प्रसूति सहायता, साइकिल, सिलार्ड मशीन, श्रवण यंत्र, ट्यूब-साइकिल, कृत्रिम अंग, दुर्घटना सहायता सहित अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपायुक्त ने बताया कि श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें व कॉपीयां खरीदने हेतु 3 हजार से 4 हजार रुपये, छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 हजार से 21 हजार रुपये, कन्यादान योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये, शगुन योजना में 21 हजार रुपये, प्रसूति योजना में लडका होने पर 12 हजार रुपये तथा लडकी होने पर 15 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत योग्य पात्रों की प्लॉट बुकिंग प्रारंभ

रोहतक, (वीओ)। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत योग्य पात्र लाभार्थियों के लिए प्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिला में लगभग 231 पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। नगर एवं ग्राम आयोगन 231 पात्र लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित प्लॉटों के आवंटन की नीति 23 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया आगामी तीन से चार दिनों तक जारी रहेगी। योजना के तहत पात्र आवेदकों की सूची एवं उपलब्ध प्लॉटों का विवरण हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर मात्र 10 हजार की राशि जमा कर अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पात्र लाभार्थी को योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वह जिला विकास भवन स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकता है।

दयालु योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांग होने पर दी जाती है आर्थिक सहायता:मीणा

कुरुक्षेत्र, (वीओ)। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योद्यम परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के दायरे में एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे। ऐसे परिवारों में 1 अप्रैल 2023 से किसी की मृत्यु हुई है या 100 प्रतिशत दिव्यांग हुआ है तो वह परिवार इस योजना का पात्र माना जाएगा। आवेदन के लिए परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। यदि परिवार में किसी की एक्सिडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सिडेंट में दिव्यांग हुआ है, तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल से डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है।

डा.कल्पना चावला की 23वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का किया आयोजन

►डा. कल्पना चावला के जीवन से प्रेरित होकर बड़े सपने को कर सकते हैं साकार

कुरुक्षेत्र, (प्रकृति आश्री)। कल्पना चावला स्मारक तारामंडल में डॉ. कल्पना चावला की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कल्पना चावला तारामंडल में कल्पना को श्रद्धांजलि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विद्यार्थियों अध्यापकों व दर्शकों के लिए भिन्न-भिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, सर्पार्थ इंडिया (अंतरंगत ग्लोबल स्काई पार्टनर्स कार्यक्रम, लॉस कॅम्पेस ओम्बेवैं ट्री) भोपाल अमृतानु वाजपेयी रहे। उन्होंने कल्पना चावला को श्रद्धांजलि देते हुए



चंद्रमा एवं उससे जुड़े नागरिक विज्ञान पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि धरती एवं चंद्रमा के रिश्ते पर प्रकाश डालते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खोल विज्ञान के आलोक में चंद्रमा के महत्व के बारे में जानकारी दी तथा साथ ही भारतीय ज्ञान परम्परा

में काल गणना (समय की गणना) में छुपे हुए विज्ञान पर चर्चा करते हुए तिथि, नक्षत्र आदि की गणनाओं की भूमि पर भी वक्ता द्वारा जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने जाना कि किस प्रकार अपने छात्र जीवन में ही वे मात्र

मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से ही विभिन्न सिटीजन साइंस कार्यक्रमों में एक शोधार्थी की भांति प्रतिभांगिता कर वैज्ञानिक पुनर्जागरण व विज्ञान के विकास में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान दे सकते हैं।

मंत्री अनिल विज ने गुरु रविदास मंदिर में टेका माथा व आशीर्वा प्राप्त किया

अम्बाला/चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने सबसे बड़ा संदेश दिया कि "मन चंगा तो कठौती में गंगा" यानि हम मन को ठीक कर लें तो सब कुछ हमारे पास बैठे बिठाए जा जाएगा तथा हम जो भी कार्य करें उसे गर्व से करें, यहीं गुरुजी का संदेश है। श्री विज आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के पानन अवसर पर रविदास मंदिर में माथा टेकने के उपरांत श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने गुरु रविदास जयंती की बधाई देते हुए कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का हमारे समाज व सभ्यता के निर्माण

परिवहन विभाग से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई, 14,111 वाहन जप्त, 57.47 करोड़ से अधिक जुर्माना

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो द्वारा अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा करते हुए वर्ष-2025 में 1264 मुकदमे दर्ज करते हुए 1286 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। इस अवधि के दौरान प्रवर्तन ब्यूरो की टीम द्वारा प्रदेश में मिट्टी/रेत/बजरी का अवैध खनन करने को लेकर 6898 स्थानों पर छापेमारी की गई और 2637 वाहनों को मौके पर जप्त किया गया।

विजय 2026: स्मार्ट, सख्त और संवेदनशील प्रवर्तन पर फोकस: पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि वर्ष 2026 के लिए ब्यूरो का स्पष्ट दृष्टिकोण 'स्मार्ट, सख्त और संवेदनशील प्रवर्तन' पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ब्यूरो को

तकनीक आधारित, परिणामोन्मुख और पूर्णतः जवाबदेह इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि अवैध खनन, निजाली चोरी, अवैध शराब, जल चोरी और शहरी विकास सम्बन्धी अवैध गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार किया जा सके। वर्ष 2026 में राज्यभर में रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स, इंटर-डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस शेयरिंग और एकसाथ समन्वित कार्रवाई को और मजबूत किया जाएगा। श्री सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस का लक्ष्य केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून का भय और नियमों के प्रति सम्मान स्थापित कर एक सुरक्षित, अनुशासित और विकासोन्मुख हरियाणा का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवैध खनन माफिया के खिलाफ अभियान: प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी ने कुशल नेतृत्व में ब्यूरो द्वारा अवैध गतिविधियों विशेष कर अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में वर्ष-2025 में अवैध खनन वाले भू-माफियों पर 19.84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया जिसमें 9.57 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया तथा बकाया जुर्माना वसूल करने की प्रक्रिया जारी है।

द्वारा वर्ष 2025 में खनन की 6898 साइटों का निरीक्षण किया गया। इस मामले में 1264 मामले दर्ज करते हुए 1286 लोगों को गिरफ्तारी करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें से 1122 एफआईआर का निस्तारण किया जा चुका है। हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो के प्रमुख नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि ब्यूरो द्वारा वर्ष-2025 में 6 विभागों के संबंधित अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए परिवहन विभाग के 18819 वाहनों की चैकिंग की गई जिनमें से 14111 वाहनों को जप्त किया गया। इन वाहनों पर 57.47 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का जुर्माना लगाते हुए इन पर कार्यवाही की गई।

टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स - जॉर्डन 2026 में भारत की ऐतिहासिक सफलता, हरियाणा पुलिस के जवान ने बढ़ाया देश व विभाग का मान

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जिसका आयोजन आगामी नवंबर माह में किया जाएगा। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में हरियाणा पुलिस के एएसआई जितेंद्र कुमार अहलावत को अहम भूमिका रही, जिन्होंने भारतीय टीम के सदस्य के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश और विभाग का नाम रोशन किया।



कुमार अहलावत तीनों टीम स्पर्धाओं का हिस्सा रहे और टीम को गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। समग्र प्रदर्शन के आधार पर भारत ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उल्लेखनीय है कि एएसआई जितेंद्र

पूरे प्रदेश और पुलिस बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि एएसआई जितेंद्र कुमार अहलावत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा पुलिस के जवान न केवल कानून-व्यवस्था में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करने की पूरी क्षमता रखते हैं। डीजीपी ने जवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि यह उपलब्धि पुलिस बल के अन्य अधिकारियों व जवानों को भी प्रेरित करेगी। डीजीपी ने इस मौके पर ब्रिगेडियर(सेवानिवृत्त) संदीप सिंह कश्यप कंसल्टेंट के-9 एवं माउंटेंट पुलिस को भी बधाई दी और कहा कि टीम के प्रशिक्षण, तैयारी और समग्र प्रदर्शन में उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार मेहनत से सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे।

प्रतियोगिता के दौरान भारतीय टेंट पेगिंग टीम ने ऐतिहासिक और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने टीम स्पर्धाओं में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। समग्र प्रदर्शन के आधार पर भारत ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उल्लेखनीय है कि एएसआई जितेंद्र

केंद्रीय बजट 2026-27 हिमाचल के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्ण: मुख्यमंत्री

शिमला, (पवन आश्री)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानी और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से निराश हैं। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवर्धन के अनुकूल 275(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान है,

युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाएगी गौड़ शिक्षण संस्थाएं: डॉ अरविंद शर्मा

रोहतक, (तारीफ शर्मा)। सहकारिता, कारागार, निर्वचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि देश की बड़ी शिक्षण संस्थाओं में से एक गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा की शिक्षण संस्थाएं हमारी युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लेकर जाएंगी, ताकि होनहार युवा भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि पहरावर धाम में स्थापित होने वाले कैम्पस के शिक्षण संस्थान नवाचार और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू किया जा रहा है, ताकि युवाओं को स्वरोजगार के साथ-साथ आत्मनिर्भर और देश को दिशा बनाने के अनुकूल तैयार किया जा सके। रविवार को सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के तहत भगवान परशुराम कैम्पस 3 पहरावर पहुंचे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के साथ-साथ निबंध रखते हुए शुरू करवाया। हवन में पूर्णाहुति डालने उपरांत अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद



शर्मा ने कहा कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा की शिक्षण संस्थाओं की साक्षर पूरे देश में है, हमें इस साक्षर को बढ़ाते हुए नए स्थापित होने वाले शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि समाज के सशक्त होना पहरावर धाम परिसर में जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित किए जाएंगे, उनके माध्यम से आने वाली पीढ़ी के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समाज 36 बिरादरी को हमेशा साथ लेकर चलता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्षमता है। हमें अपनी ताकत को संभालना है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को नए मुकाम पर लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के नेतृत्व की सरकार में समाज के प्रति निरंतर सम्मान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गौड़ संस्था के तीसरे कैम्पस की नींव में हर वो व्यक्ति सांझीदार है, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, उसी प्रकार हम सभी को मिलकर सेवाभाव के साथ संस्था को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पहरावर धाम में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के तीसरे कैम्पस के प्रशासनिक भवन के निर्माण, भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एवं मैरिड निर्माण कार्य शुरू हुआ है, इसके लिए हम सभी मिलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।

पुलिस महानिरीक्षक एन.एस. नपलच्याल एवं पुलिस उपाधीक्षक नवीन चन्द्र सेमवाल को सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, देहरादून स्थित सभागार में पुलिस महानिरीक्षक एन.एस. नपलच्याल एवं पुलिस उपाधीक्षक नवीन चन्द्र सेमवाल के सम्मान में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन ए.पी. अंशुमान सहित अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं द्वारा दोनों अधिकारियों की गौरवशाली सेवा यात्रा, उनके कर्तव्यनिष्ठ योगदान, नेतृत्व क्षमता एवं अनुकरणीय कार्यशैली का उल्लेख करते हुए भूरि-भूरि सराहना की गई।

इस अवसर पर पुलिस



महानिदेशक दीपम सेठ ने अपने सम्बोधन में कहा कि ठसेवानिवृत्ति पर जा रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने हर जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्यनिष्ठा और गरिमा के साथ निभाया। मैं आशा करता हूँ कि इनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ भविष्य में भी उत्तराखण्ड पुलिस को निरंतर प्राप्त होता रहेगा। मैं उत्तराखण्ड पुलिस परिवार की ओर से दोनों

अधिकारियों को इनके समर्पित सेवाकाल के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इनके आगामी जीवन के लिए सुख, स्वास्थ्य व सक्तिता से परिपूर्ण भविष्य की मंगलकामनाएँ करता हूँ। एन. एस. नपलच्याल एवं नवीन चन्द्र सेमवाल ने भी समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों व सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग, समर्थन एवं कर्मठता के कारण ही वे अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके। समारोह के अंत में पुलिस महानिदेशक द्वारा एन. एस. नपलच्याल एवं नवीन चन्द्र सेमवाल को एक स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया। एन.एस. नपलच्याल का चयन वर्ष 1995 में

प्रांतीय पुलिस सेवा में हुआ। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने उत्तराकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, मेरठ तथा पीटीसी मुरादाबाद में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। भारतीय पुलिस सेवा में इंडक्शन के उपरान्त उन्होंने वर्ष 2012 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र मिशन, सूडान में सेवा प्रदान की। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, प्रशिक्षण तथा ँञ्छे सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 2019 में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत के पश्चात् उन्होंने फायर, प्रशिक्षण एवं सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। वर्ष 2023 में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त उन्होंने सीआईडी तथा निदेशक यातायात जैसे अहम

पदों पर सेवाने प्रदान की। वर्तमान में वे निदेशक यातायात के पद पर कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र मेडल, वर्ष 2019 में सराहनीय सेवा के लिये राष्ट्रपति पदक एवं वर्ष 2025 में राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नवीन चन्द्र सेमवाल वर्ष 1985 में पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर नियुक्त हुए। अपने सेवाकाल में वे वर्ष 1998 में उप निरीक्षक, वर्ष 2016 में निरीक्षक तथा वर्ष 2024 में पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत हुए। उन्होंने नैनीताल, मेरठ, उत्तराकाशी, देहरादून, पीडी गढ़वाल, हरिद्वार सहित पुलिस मुख्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। भारत सरकार द्वारा सराहनीय सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2025 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया।

अवैध खनन पर लगी रोक तो चार गुना बढ़ा राजस्व

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। खनन गतिविधियों को लेकर सामान्य तौर लोगों में नकारात्मक अवधारणा रहती है। लेकिन उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन आवंटन और खनन परिवहन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही अवैध खनन पर सख्ती दिखाई, इसी का नतीजा है कि डेढ़ साल से कम समय में सालाना खनन राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ के पार पहुंच गया है।

प्रदेश सरकार ने सितंबर 2024 को नई खनन नीति लागू की थी। नई खनन नीति में ई निलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन, खनन गतिविधियों की सेटलाइट निगरानी जैसे कई नए प्रयोग किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस-प्रशासन को भी अवैध खनन पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। सितंबर 2024 से पहले राज्य को खनन से सिर्फ 300

करोड़ रुपए तक ही सालाना राजस्व प्राप्त हो पाता था, लेकिन अब यह राजस्व 1200 करोड़ के पार चला गया है। यही नहीं उत्तराखण्ड को खनन सुधार लागू करने के लिए देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हो चुका है, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'पूँजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के लिए 200 करोड़ की विशेष सहायता स्वीकृत की है। इन सुधारों से बदली तस्वीर-ई निलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन, अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई, खनन परिवहन के लिए माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, खनन गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग और निरीक्षण शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आम लोगों को आवासीय या अन्य निर्माण के लिए खनन सामग्री की आवश्यकता होती है, साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भी खनन की आवश्यकता है।

पवित्र धामों में गैर हिन्दू प्रवेश मुद्दे पर, आस्था एवं विश्वास अनुरूप हो निर्णय: भट्ट

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। भाजपा ने पवित्र धामों में गैर हिन्दू प्रवेश के मुद्दे पर धार्मिक आस्था और देवभूमि छवि अनुरूप निर्णय पर जोर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस विषय पर कांग्रेसी बयानों को कड़ी आलोचना करते हुए कहा, जिन्हें तीर्थटन और पर्यटन का अंतर नहीं मालूम, उनके लिए चारों धामों का महत्व सिर्फ धार्मिकी तक समिति है। वहीं हैरानी जताई तमाम स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर, जो देवभूमि में राजनीति हैं और हर अच्छे सनातनी निर्णय को बाधित करने का पाप करते हैं।

उन्होंने हाल फिलहाल में हरिद्वार के बाद चार धामों में गैर सनातनी प्रवेश के विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, धार्मिक जन आस्था, विश्वास और परंपरा मान्य होनी चाहिए। संबन्धित पावन धामों से जुड़े तीर्थ पुरोहित, स्थानीय पुजारी एवं अन्य लोग या



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट।

धर्मावलंबी यदि प्रवेश को लेकर नियम बनाना चाहते हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि इस तरह का प्रतिबंध अनेकों स्थानों पर जनसहयोग से अनेकों स्थानों पर है। यहां बेहद स्पष्ट है कि जिसकी धार्मिक स्थलों के प्रति कोई भी आस्था, विश्वास या धार्मिक जुड़ाव नहीं है तो वे किस मकसद से वहां जाएंगे। दरअसल मंदिर एक सामूहिक सामूहिक पूजा स्थल है, लिहाजा वहां सिर्फ धूमने के नाम पर अत्यावहारिक व्यवहार

सामने आने या माहौल खराब होने की अनुमति किसी को नहीं दी सकती है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और विशेषकर गणेश गोदियाल के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने चार धामों को धूमने फिरने से जोड़ा। कटाक्ष करते हुए कहा, लगातार है कांग्रेस का सनातन से दूर दूर तक नाता नहीं है, तभी वे तीर्थटन और पर्यटन में अंतर महसूस नहीं करते। तभी वे चार धाम की पवित्रता और परंपरा पर

आर्थिकी को तरजीह देने की बात कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, हम भी जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिकी में चार धाम यात्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन पावन स्थलों के अंदर तो सब प्रक्रिया तो सनातनी परिप्रेक्ष्य में ही होनी चाहिए। इसीलिए तो राज्य निर्माण के बाद जनभावना के अनुसार पर्यटन के साथ तीर्थटन को भी महत्व दिया गया। निसंदेह प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन धार्मिक स्थलों में आस्था, विश्वास एवं परंपरा के अनुसार ही पर्यटन होना चाहिए, जिसे तीर्थटन ही कहते हैं।

वहीं उन्होंने राज्य कांग्रेस नेताओं के ऐसे तमाम मुद्दों पर अपनाए हुए रुख पर हैरानी और निराशा जताई। कहा, ये सब उत्तराखण्डित के मुद्रा पर देवभूमि में राजनीति का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रदेश के सनातनी निर्णय का विरोध भी करते हैं। इन्हें धार्मिक स्थलों में

पहाड़ पर शीतकाल में वीरानी नहीं, बल्कि यात्रियों के उत्साह के हो रहे दर्शन

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। शीतकाल में पहाड़ पर इस बार भी वीरानी नहीं है, जो कि चार धामों के कपाट बंद हो जाने के बाद अक्सर दिखाई देती थी। पिछले वर्ष से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा के बाद पहाड़ में तस्वीर बदली हुई है। यात्रियों की चहल-पहल सुखद अनुभूति करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर पहले उत्तराखण्ड आकर जिस शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन किया था, वह अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चार सरकार के भीमारी प्रयासों से उत्तराखण्ड की शीतकालीन यात्रा एक नया अध्याय लिख रही है।

चारों धामों से संबन्धित पांडुकेश्वर, ऊखीमठ, मुखवा और खरसाली जैसे शीतकालीन प्रवास स्थलों तक देश-दुनिया के यात्री आच्छी-खासी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार चार धाम यात्रा के कपाट बंद होने के बाद से अभी तक 34,140 यात्री इन स्थानों पर पहुंच

चुके हैं। अभी करीब ढाई महीने शीतकालीन यात्रा अभी और चलनी है। यह लगातार दूसरा वर्ष है, जबकि राज्य सरकार के स्तर पर सफलतापूर्वक शीतकालीन यात्रा का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में जब पहली बार यह यात्रा शुरू की गई, तो तब 73,381 यात्री शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखण्ड आए थे। शीतकालीन यात्रा में अभी तक सबसे ज्यादा यात्री बाबा केदारनाथ के गद्दीस्थल ऊखीमठ पहुंचे हैं। चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के विशेष कार्याधिकारी डॉ. प्रजापति नैटियाल के अनुसार-अभी तक सबसे ज्यादा 20,338 यात्रियों ने ऊखीमठ में दर्शन किए हैं। इसके बाद, ज्योतिमठ में यात्री पहुंचे हैं। खरसाली और मुखवा में भी लगातार यात्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। डॉ. नैटियाल के अनुसार- एक से डेढ़ हजार यात्री प्रतिदिन उत्तराखण्ड पहुंचकर शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर रहा है।

8 फरवरी की महापंचायत के लिए तैयारियां तेज

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून। अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम के खुलासे और न्याय की मांग को लेकर चल रहा जन आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होने जा रहा है। इसी क्रम में 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली महापंचायत को सफल बनाने हेतु शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 40 से अधिक सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी महापंचायत में शामिल होने की सहमति जताई है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक गौरव गढ़वल नरेंद्र सिंह नेगी ने भी महापंचायत के समर्थन में अपील जारी की है। बैठक में मौजूद संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महापंचायत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का संकल्प लिया। आयोजन के सुचारु संचालन के लिए सुरक्षा समिति और अनुशासन समिति का गठन किया गया। साथ ही यह नारा दिया गया कि उत्तराखण्ड के हर परिवार से

कम से कम एक-दो व्यक्ति महापंचायत में अवश्य शामिल हों। बैठक में सरकार के रवैये को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित सीबीआई जांच को लेकर अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। जनता की मांग केवल सीबीआई जांच नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों की निगरानी में सीबीआई जांच की है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्य सरकार ने जांच की संस्कृति केंद्र को भेजी है या नहीं, तथा जांच का दायरा क्या होगा।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार का रवैया यह दर्शाता है कि सीबीआई जांच की घोषणा केवल 11 जनवरी के बंद को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई थी। जनता इस मंशा को समझ चुकी है, यही कारण है कि बंद को व्यापक समर्थन मिला। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी को महापंचायत के बाद भी आंदोलन लगातार जारी रहेगा। महापंचायत में ही फरवरी माह के आगामी कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी

किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर तक आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही। युवाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार का यही रवैया रहा, तो उत्तराखण्ड में राजनीतिक परिवर्तन के लिए विन्यक्त तलाशना परिहार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में 2027 में युवाओं के बीच भ्रम की स्थिति बनेगी, जिसका सीधा लाभ सत्ताधारी दल को मिलेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि महापंचायत में अंकिता न्याय से संबंधित बैनर-पोस्टर-झंडों को स्वीकार स्वीकार किया जाएगा। पूरी कार्यवाही महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से गठित संचालन समिति की देखरेख में संपन्न होगी। सभी राजनीतिक दलों द्वारा दिए जा रहे समर्थन और सहयोग की सराहना की गई। महिला संगठनों ने विशेष रूप से कहा कि राज्य में बढ़ती नरशा संस्कृति, रिजॉर्ट संस्कृति और उत्तराखण्ड को थर्डवैल्यूड बनाने जैसी सोच को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आज की बैठक में 32 संगठनों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि 11 संगठनों ने अनुपस्थित रहते हुए भी पूर्ण समर्थन और सहयोग के संदेश भेजे। बैठक की अध्यक्षता यशवीर आर्य ने की तथा संचालन निर्मला बिष्ट ने किया। बैठक का संयोजन कमला पंत द्वारा किया गया। इस अवसर पर संघर्ष मंच के सदस्य मोहित डिमर, गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन धसमान, जगमोहन मेहदीरा, प्रदीप कुकरेती, देवचंद उत्तराखण्ड, मुकेश बहगुणा, उमा भट्ट, विमला कोली, महावीर राणा, धन सिंह नेगी, बलराज नेगी, विशंभर दत्त बोठियाल, विपिन नेगी, सुरज नेगी, अप्पु गोदियाल, स्वाति नेगी, आकांक्षा नेगी, कनिष्क जोशी, गगन बौड़्राई, परमजीत ककड़, वीरेंद्र अस्वाल, हरबीर सिंह कुशवाहा, रंजु नौडियाल, नितिन मलेठा, कविता कृष्ण पल्लवी, संजय शर्मा, सुरेंद्र अग्रवाल, आईपी शर्मा, जेपी तडियाल, रामचंद्र तडिया, शंकर गोपाल, लक्षित श्रीवास्तव, मनीष केडियाल, ललित, पंचम सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

सूचना विभाग में सेवानिवृत्त हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पटवाल एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राणा देहरादून (बीअ)। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्यालय में आयोजित सेवानिवृत्त कार्यक्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जगदीश सिंह पटवाल एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सिंह राणा को भावभीनी विदाई दी गई। अपर निदेशक सूचना आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय, उप निदेशक रवि विजयराजिया एवं अन्य अधिकारियों द्वारा श्री पटवाल एवं श्री राणा को शील एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर निदेशक सूचना आशिष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी कार्मिक द्वारा 40 और 34 वर्ष की सेवा करना ही अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक अपने साथ का लंबा अनुभव साथ लेकर जाते हैं। हम सभी को आपसी संबंध और अधिक बेहतर बनाने चाहिए। आपसी संबंध के कारण हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा कि सूचना संघ को भविष्य में सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु कार्यक्रम करना चाहिए। इससे पुराने और नये कार्मिकों के विचारों का आदान-प्रदान होगा। श्री त्रिपाठी ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री जगदीश सिंह पटवाल एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सिंह राणा द्वारा विभाग में दिये गये योगदान की सराहना की। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय ने कहा कि विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विभाग की प्रगति में सेवानिवृत्त कार्मिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर फोटो फिल्म अधिकारी शंकर चन्द्र जोशी, सहायक लेखाकार कीर्ति सिंह पंवार, व्यवस्थाधिकारी रामपाल सिंह रावत द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक अधिकारी विजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एल.पी.भट्ट सहायक निदेशक, मनोज कुमार शुक्ला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाकार राकेश कुमार धीमान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रणजीत सिंह बुदियाल, सहित सूचना कर्मचारी संघ के महामंत्री अंकिता वैहान, उपाध्यक्ष प्रशांत रावत, संगठन मंत्री सत्येन्द्र विजल्वण सहित अन्य पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

वाटर स्पोर्ट्स में टिहरी आज विश्व के मानचित्र में अपना स्थान बना रही: सुबोध उनियाल

देहरादून, (बीअ)। जनपद टिहरी में आयोजित एफो फेस्टिवल एवं नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिभाग किया तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज टिहरी वाटर स्पोर्ट्स एवं एफो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान बना रही है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश-विदेश से आए 11 देशों के 25 पायलटों तथा विभिन्न राज्यों से आए 57 खिलाड़ियों की सहभागिता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उत्तराखण्ड अब अंतरराष्ट्रीय साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से न केवल प्रदेश की वैश्विक पहचान प्रकाश होती है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार एवं पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलती है। इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय, शक्ति लाल शाह, भाजपा टिहरी जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष ईशिता सजवान सहित अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

बीएलओ आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी

देहरादून, (बीअ)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीबीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संबन्ध स्थापित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ, ईआरओ सहित पूरी इलेक्शन मशीनरी ने बेहद उत्साहपूर्वक तरीके से 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश के युवा एवं महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस रहेगा। आउटरीच अभियान के दूसरे चरण को 15 फरवरी 2026 तक सम्पादित किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्री एसआईआर फेज में प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अभियान में अपने बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने तथा अपने पिता/पति के नाम के आधार पर मतदाता फ्रामक एवं बूथ संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गली, मोहल्लों और एरिया के नाम से भी मतदाता सूची खोजने की सुविधा प्रदान की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त न्युट्रिय राजनैतिक दलों से अपने-अपने बूथ लेवल एंजेंट्स (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के 12070 बीएलए की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने राजनैतिक दलों से शतप्रतिशत बीएलए नियुक्त करने की अपील की है।

प्लीजग्रोअप नाम से फिजिटल सड़क सुरक्षा कैम्पेन शुरू किया

देहरादून, (बीअ)। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण मानवीय भूल है। इसे देखते हुए उज्जीवन स्मॉल फाइनस बैंक ने प्लीजग्रोअप नाम से एक फिजिटल (डिजिटल प्लस फिजिकल) सड़क सुरक्षा जागरूकता कैम्पेन शुरू किया है। इस कैम्पेन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के सबसे अनेक कारणों में से एक- सड़क पर अपरिपक्व और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना है। अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का दोष बुनियादी ढांचे या यांत्रिक विफलता पर मढ़ दिया जाता है, जबकि हकीकत में अधिकांश मौतें टाले जा सकने वाले मानवीय व्यवहार जैसे कि तेज रफ्तार, सिग्नल तोड़ना, गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकना, नशे में गाड़ी चलाना और बुनियादी सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण होती है। इस कैम्पेन का इरादा रोजमर्रा की ड्राइविंग आदतों को आईना दिखाकर आत्म-चिंतन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है। प्लीजग्रोअप के माध्यम से, उज्जीवन बैंक सड़क की लापरवाही को उसके वास्तविक स्वरूप में पेश करता है, जो न तो बहादुरी है, न ही कूल है और न ही व्यक्तियों वाला व्यवहार है, बल्कि पूरी तरह से बचकानी है। यह कैम्पेन व्यंग्य और दृश्यात्मक विषमता का उपयोग करता है, जिसमें गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग व्यवहार को बेबी टॉक (बच्चों जैसी भाषा) और बच्चों वाली कल्पनाओं के जरिए दिखाया गया है। यह रचनात्मक दृष्टिकोण इस तरह से तैयार किया गया है कि लापरवाही भरा व्यवहार सार्वजनिक सड़कों पर उताना ही अनुचित और अजीब लगे जितना कि वह वास्तव में है। शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, डिजिटल सामग्री और सोशल मीडिया कन्टेंट के माध्यम से फैला यह कैम्पेन दिखाता है कि कैसे एक लापरवाह निर्णय निर्दोष लोगों के लिए जीवन बदलने वाले गंभीर परिणाम ला सकता है।

मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल ने छह सफल रिनल डिनर्वेशन प्रक्रियाओं के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया

वीर अर्जुन संवाददाता

मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल ने छह रिनल डिनर्वेशन प्रोसीजर पूरे करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह संख्या गुजरात में सबसे ज्यादा है और भारत में सबसे ज्यादा में से एक है। ये प्रोसीजर इंटरवेंशनल कोर्डियोलॉजिस्ट की एक सीनियर टीम ने किए, जिसमें डॉ. केयूर पारिख, डॉ. विपुल कपूर और डॉ. तेजस वी. पटेल शामिल थे। यह माइलस्टोन अस्पताल को भारत में रेजिस्ट्रेंट हाइपरटेंशन के लिए एडवांस्ड थैप्री प्रदान करने वाले अग्रणी केंद्रों में स्थान दिलाता है। एक मामले में 57 वर्षीय पुरुष का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से अधिक बना हुआ था, जबकि वे सात एंटी-हाइपरटेंसिव दवाओं पर थे। उनकी मेडिकल हिस्ट्री में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज, डबल-वेसल डिजीज तथा पहले से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी स्टेंट (2014) शामिल है। इसके अलावा, प्रतिदिन 6-7 दवाएँ लेने के बावजूद स्टैंडर्ड हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट अप्रभावी रहा था। मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल के चेरमन डॉ. केयूर पारिख ने कहा कि, 'जब किसी मरीज का ब्लड प्रेशर तीन या उससे अधिक दवाएँ लेने के बावजूद 140/90 से ऊपर बना रहता है, तो स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर और किडनी को नुकसान होने का जोखिम काफी बढ़ जाते हैं। रिनल डिनर्वेशन हमें और दवाएँ जोड़ने के बजाय रेजिस्ट्रेंट हाइपरटेंशन के मूल कारण को लक्षित करने की अनुमति देता है।'

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने जनवरी 2026 में 71,066 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की

वीर अर्जुन संवाददाता

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने जनवरी 2026 के दौरान घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रदर्शन करते हुए कुल 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। यह आंकड़ा जनवरी 2025 में दर्ज की गई 48,316 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में घरेलू बाजार (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित) में 70,222 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 844 यूनिट्स की बिक्री हुई। इस प्रकार पैसेंजर व्हीकल्स की कुल बिक्री (ईवी सहित) 71,066 यूनिट्स रही। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भी कंपनी का प्रदर्शन सशक्त रहा। जनवरी 2026 के दौरान घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुल 9,052 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। जनवरी 2026 की कुल बिक्री में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बिक्री भी शामिल है।

सावधान: अब खुले में कचरा डाला तो होंगे भारी चालान

कचरा फेंकने वालों के फोटो वीडियो भी होंगे सार्वजनिक प्रदर्शित

वीर अर्जुन संवाददाता

अलवर। शहर को स्वच्छता के पायदान पर शीर्ष पर लाने के लिए नगर निगम अब समझाइश और सख्ती की नीति पर काम कर रहा है। शनिवार को नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका ने जबली बास सहित शहर के विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर कचरा फेंकने वाले लोगों को न केवल टोका, बल्कि उन्हें स्वच्छता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अहसास भी कराया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। शहर की सफाई व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए निगम ने पुख्ता प्लानिंग कर ली है।

स्वच्छता प्रहरी दस्ता: निगम के विशेष दस्ते अब गलियों और मुख्य सड़कों पर गश्त करेंगे।

सीसीटीवी कैमरों से नजर: शहर के प्रमुख स्थानों पर लगे कैमरों के जरिए कचरा फेंकने वालों की पहचान की जाएगी।

ऑन-द-स्पॉट चालान: बार-बार समझाने के बाद भी मर्यादा तोड़ने वालों के खिलाफ भारी चालान काटने की कार्यवाही शुरू होगी।

डिजिटल स्क्रीन पर दिखेगा कचरा फेंकने वालों का चेहरा: आयुक्त सोहन सिंह नरुका ने एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छ अलवर बनाना केवल सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग बार-बार समझाने पर भी नहीं मानेंगे, उनका भारी चालान होगा और उनकी कूड़ा डालते हुए फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग शहर के प्रमुख चौराहों पर लगी बड़ी स्क्रीन पर सार्वजनिक रूप से दिखाई जाएगी।

जनता से अपील: निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखें और कचरा केवल निगम के कचरा संग्रहण वाहनों में ही डालें। शहर को सुंदर बनाना साझा प्रयास है, और इसमें कोताही बरतने वालों के साथ अब निगम कोई रियायत नहीं बरतेगा।

रोबोटिक सर्जरी: अब रोबोटिक सर्जरी से और भी बेहतर होंगे परिणाम - डॉ. राजेश शर्मा

सी के बिरला हॉस्पिटल्स, जयपुर में अब तक 600 से अधिक रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है

वीर अर्जुन संवाददाता

अलवर/जयपुर। सी के बिरला हॉस्पिटल्स, जयपुर में अत्याधुनिक दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की स्थापना के बाद अब मरीजों को रोबोटिक सर्जरी के लिए जयपुर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनिमल इनवेसिव एवं बैरिएट्रिक सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ. राजेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी तकनीक यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहित कई स्पेशलिटी की सर्जरी को अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी। रोबोटिक तकनीक से कोलोरैक्टल सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, यूरोलॉजी, कैंसर सर्जरी एवं बैरिएट्रिक सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाएँ अब बेहतर परिणामों के साथ की जा सकेंगी। डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के कई लाभ हैं-जैसे कम दर्द, कम रक्तस्राव, छोटे चीरे, कम जटिलताएँ और तेजी से रिकवरी-जिससे मरीज इलाज के बाद जल्दी सामान्य जीवन में लौट पाते हैं।

राजस्थान के चिकित्सा इतिहास में नया अध्याय: सी के बिरला हॉस्पिटल्स के सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ. राजेश शर्मा ने एक बार फिर राजस्थान के चिकित्सा इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्हें दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का प्रॉक्टर घोषित किया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे राजस्थान के पहले चिकित्सक हैं। उनकी यह नियुक्ति प्रदेश में उन्नत शल्य-चिकित्सा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। इस उन्नत तकनीक के माध्यम से अब पित्तशय, हृदय, आंतों, रेक्टल, बैरिएट्रिक तथा एंडोमिनल ट्यूमर जैसी जटिल सर्जरीयें बेहद छोटे चीरे से, अधिक सटीकता के साथ और कम जोखिम में सफलतापूर्वक की जा रही हैं। जिस तरह पहले सभी ऑपरेशन्स चीरे द्वारा किये जाते थे फिर दूरबीन शल्य चिकित्सा की शुरुआत हुई एवं जब उसके उन्नत परिणाम सामने आये उसके फलस्वरूप सभी रोगी अब चीरे वाले ऑपरेशन की जगह दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कराते हैं। रोबोटिक सर्जरी दूरबीन शल्य चिकित्सा का सबसे अत्याधुनिक स्वरूप है, इस विधि ने सभी ऑपरेशन्स को और अधिक सुरक्षित, सुगम, एवं दर्द रहित बना दिया है, डॉ. राजेश शर्मा स्वयं 170 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं कई चिकित्सक जिसमें स्वयं सर्जन भी शामिल हैं, इस विधि द्वारा खुद का ऑपरेशन करवा चुके हैं।

जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026 का भव्य शुभारंभ, पंखों की उड़ान और आर्द्रभूमियों की पुकार के साथ संरक्षण का उत्सव शुरू

वीर अर्जुन संवाददाता

जयपुर। धरती की आर्द्रभूमियों को बचाने और आसमान में परिंदों की चहचहाहट को फिर से सजीव करने के संकल्प के साथ जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026 का भव्य शुभारंभ शनिवार को कानोता कैम्प रिजॉर्ट, जामडोली (जयपुर) में हुआ। Join the Celebration of Wings & Wetlands थीम पर आधारित इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन ने पहले ही दिन प्रकृति प्रेम, संरक्षण चेतना और रचनात्मक अभिव्यक्ति के रांग बिरांघ दिए।

ग्रीन पीपल सोसायटी (जयपुर चैप्टर) द्वारा राज्य सरकार के वन विभाग एवं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल का उद्घाटन संरक्षण विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और प्रकृति प्रेमियों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। ग्रीन पीपल सोसायटी के उपाध्यक्ष एवं जयपुर बर्ड फेस्टिवल के संयोजक विक्रम सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) ने बताया कि यह आयोजन पिछले 12 वर्षों से राष्ट्रीय पहचान बना चुके उदयपुर बर्ड फेस्टिवल से प्रेरित है और जयपुर में यह पहल प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

शिक्षा, संवेदना और रचनात्मकता से सजा पहला दिन: फेस्टिवल के पहले दिन आयोजित मुख्य सत्र में विद्यार्थियों के लिए नेचर क्रिज, पेंटिंग प्रतियोगिता, बर्ड फोटोग्राफी, बटरफ्लाई एवं पेंटिंग प्रदर्शनी, फिलेटली (डक टिकट) प्रदर्शनी, रैप्टर्स प्रदर्शनी तथा अत्याधुनिक वीआर एक्सपेरियंस आकर्षण का केंद्र रहे। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में पक्षियों व आर्द्रभूमियों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा।



बच्चों ने देखें 25 से अधिक प्रजातियों के पक्षी: फेस्टिवल के तहत आयोजित बर्ड वाचिंग सत्र में बर्ड एक्सपर्ट डॉ. सतीश शर्मा, विक्रम सिंह, राहुल भटनागर, वीरेंद्र सिंह बेड़सा, मनोज कुलश्रेष्ठ, डॉ. कमलेश शर्मा, निर्मल मेनारिया सहित अन्य विशेषज्ञों ने बच्चों को शॉव्लर, स्पॉट-बिल डक, ग्रे हेरॉन, झोट, कॉरमोरेंट, ग्रेब, कूट्स, पेरार्किट्स, मैना सहित 25 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों से रूबरू कराया और उनके आवास, भोजन, प्रवास व प्रजनन से जुड़ी रोचक जानकारियाँ दीं।

बटरफ्लाई की लाइव लाइफ साइकल ने किया आकर्षित: डूंगरपुर के बटरफ्लाई एक्सपर्ट मुकेश पंवार ने राजस्थान की प्रमुख तितलियों पर जानकारी देते हुए पाँच तितलियों की लाइव लाइफ साइकल प्रदर्शित की, जिसने बच्चों में विशेष उत्सुकता जगाई। वहीं उदयपुर की फिलेटली एक्सपर्ट पुष्पा खमेसरा द्वारा भारत सहित विभिन्न देशों के 2 हजार से अधिक पक्षी-आधारित डक टिकटों की प्रदर्शनी लगाकर

संरक्षण संदेश दिया गया। इस मौके पर क्रिज व पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

फोटो, पेंटिंग, लाइव आर्ट और किरिगामी ने मोहा मन: राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षियों पर आधारित फोटो व पेंटिंग्स की प्रदर्शनी ने विद्यार्थियों और आगंतुकों का मन मोहा। लाइव पेंटिंग में संतकुमार, शिवानी, महक भूरिया, आयुषी शर्मा ने अपनी कला प्रस्तुत की, वहीं विवेक तोमर और अनुज तोमर ने ऑरिगामी व किरिगामी आर्ट के माध्यम से बिना कैंची और गोंद के कागज से आकर्षक पक्षी आकृतियाँ बनाकर बच्चों को रचनात्मकता से जोड़ा।

बच्चों के गालों और ललाट पर उकेरे गए पक्षी: फेस्टिवल स्थल पर आमंत्रित टेडू कलाकारों ने बच्चों के गालों और ललाट पर रंग-बिरंगे पक्षियों के टेडू बनाकर उन्हें प्रकृति के और निकट लाने का प्रयास किया।

वर्कशॉप और राज्य स्तरीय विमर्श: पहले दिन ही लगभग 30 रिसोर्स पर्सन्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला तथा 15 उभरते लेखकों के

लिए लेखन कार्यशाला आयोजित की गई। साथ ही राज्य स्तरीय सम्मेलन में वन, पर्यावरण, पर्यटन विभाग, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, एनजीओ, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने संरक्षण से जुड़े विषयों पर गहन विमर्श किया।

रविवार को आर्द्रभूमियों से होगा सीधा संवाद: फेस्टिवल के दूसरे दिन रविवार को प्रतिभागी सांभर साल्ट लेक, बरखेड़ा-चंदलाई-मुहाना क्षेत्र, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर), तालछपर अभयारण्य (चूरू) तथा रणथाम्भौर या सरिस्का टाइगर रिजर्व का फील्ड विजिट कर प्रकृति से सीधा संवाद स्थापित करेंगे।

देश-प्रदेश के दिग्गज विशेषज्ञों की सहभागिता: फेस्टिवल में हॉफ पीके उपाध्याय, वरिष्ठ पक्षिविद डॉ. असद रहमानी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सीईओ रवि सिंह, रिटायर्ड सीएसएस एस अहमद, रिटायर्ड आईएएस गिरिराज कुशवाहा उमेश कुमार व मालविका पंवार, उषेंद्र कुमार, रिटायर्ड आईपीएस बहादुर सिंह, वाइल्डलाइफ बोर्ड सदस्य राजपाल सिंह, प्रकृति प्रेमी दिनेश दुगानी, पद्मश्री फोटोग्राफर अनूप शाह, बॉलीवुड एक्टर राहुल सिंह, आउल एक्सपर्ट डॉ. प्राची मेहता, रैप्टर एक्सपर्ट रातुल साह, अजय गुप्ता, उत्तरप्रदेश के पर्यावरण विशेषज्ञ दिनेश श्रीवास्तव सहित अनेक नामी पक्षी विशेषज्ञ और पर्यावरणप्रेमी भाग ले रहे हैं।

फ्रांसीसी पर्यटक भी पहुंचें: जयपुर में बर्ड फेस्टिवल की जानकारी प्राप्त होने पर फ्रांसीसी पर्यटक बुदवा डू पोट अपनी पत्नी ओडिल के साथ पहुंचें और इस फेस्टिवल के प्रति बच्चों का उत्साह देखकर प्रसन्नता जताई। उनका कहना था कि पक्षियों और आर्द्रभूमियों का संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का संरक्षण है।

सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ने जयपुर में 'रूट फॉर मैंग्रोव्स' के जरिए मैंग्रोव संरक्षण का दिया संदेश

रूट फॉर मैंग्रोव्स' जयपुर, गुरुग्राम और हैदराबाद में संगीत, संस्कृति और कलाइमेट एक्शन को एक मंच पर जोड़ता है

वीर अर्जुन संवाददाता

जयपुर। सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ने अपनी अनोखी रूट फॉर मैंग्रोव्स कॉन्सर्ट सीरीज की शुरुआत जयपुर के जी स्टूडियोज में विशाल और शेखर के मदद और इलेक्ट्रॉनिक्स परफॉर्मंस के साथ की। यह कॉन्सर्ट तीन शहरों में होने वाली इस सांस्कृतिक पहल का पहला पड़ाव था, जिसका मकसद लाइव म्यूजिक को भारत में मैंग्रोव को बचाने और फिर से उगाने जैसे अहम काम से जोड़ना है। मैंग्रोव्स की अहमियत को सामने लाने के लिए कल्चर-लेड इनिशिएटिव के रूप में तैयार की गई रूट फॉर मैंग्रोव्स कॉन्सर्ट सीरीज, लाइव एंटरटेनमेंट को पर्यावरण जागरूकता और लोगों की भागीदारी का जरिया बनाती है। ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस और प्रमोट किए गए इस जयपुर कॉन्सर्ट ने अपनी हाई-एनर्जी परफॉर्मंस और जलवायु सुरक्षा व जागरूक जीवनशैली के मजबूत संदेश के साथ इस सीरीज की शुरुआत की।

विशाल और शेखर ने स्टेज पर अपनी पहचान वाली एनर्जी लेकर आते हुए दर्शकों को अपने लोकप्रिय और बेहद पसंद किए जाने वाले गानों-जैसे 'देसी गर्ल', 'दस बहाने', 'बचना ऐ हसीनो', 'तू मेरी' और 'दीवांगी दीवांगी'-से पूरी तरह बांधे रखा। उनकी परफॉर्मंस सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक कॉल-टू-एक्शन थी, जो दर्शकों को याद दिलाती है कि स्पीट में स्टेज से आगे जाकर भी बदलाव लाने की ताकत होती है। कलाइमेट चेंज हमें अक्सर कल की समस्या लगता है, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर आज ही पड़ रहा है, ऐसा कहना है आनंदिता दत्ता, वाइस प्रेसिडेंट और पोर्टफोलियो हेड-मार्केटिंग, डियाजियो इंडिया का। उन्होंने बताया कि रूट फॉर मैंग्रोव्स एक रोमांचक म्यूजिक फेस्टिवल है और ऑडिशन से आगे जाकर भी बदलाव लाने का जश्न भी। यहाँ सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर 62 एकड़ खराब हो चुकी मैंग्रोव जमीन को फिर से जीवित करने,

30,000 से ज्यादा पौधे लगाने और पाँच तटीय गाँवों की मदद करने में जुटा है। फेस्टिवल इन प्रयासों को सीधे मजबूती देता है-हर टिकट से 50 रुपए इस जमीनी काम में जाता है। यानी जब लोग कॉन्सर्ट में आते हैं, तो वे सिर्फ संगीत का आनंद नहीं लेते, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। इसी तरह हम एंटरटेनमेंट को प्रभाव में बदलते हैं और कलाइमेट एक्शन को सबके लिए सार्थक और खुशी देने वाला बनाते हैं। विशाल और शेखर ने कहा, संगीत हमेशा जुड़ाव की बात करता है-भावनाओं से, लोगों से और हमारे आसपास की दुनिया से। रूट फॉर मैंग्रोव्स हमें इससे भी बड़ी चीज से जुड़ने का मौका देता है। मैंग्रोव्स हमारे समुद्र किनारों, हमारे शहरों और लाखों जिंदगियों की सुरक्षा करते हैं-लोकन जयादातर लोग इनके बारे में सोचते भी नहीं। अगर हमारा संगीत आज किसी एक व्यक्ति को भी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर दे, तो हमें लगेगा कि हमारा काम पूरा हुआ। हमें गर्व है कि हम उस आंदोलन का हिस्सा हैं जो चिंता को सकारात्मक कदमों में बदल रहा है। ट्राइबवाइब एंटरटेनमेंट के फाउंडर और सीईओ शोबेन शाह ने कहा, हम हमेशा ऐसी अनुभवों की तलाश में रहते हैं जो सिर्फ स्टेज तक सीमित न रहें, और रूट फॉर मैंग्रोव्स उसी सोच का मजबूत उदाहरण है। सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के साथ साझेदारी करके हमने एक ऐसी कॉन्सर्ट सीरीज तैयार की है जहाँ संगीत असल दुनिया में सकारात्मक असर लाने का माध्यम बनता है। मैंग्रोव्स को फिर से उगाने जैसे अहम कारण को केंद्र में रखकर यह पहल दिखाती है कि लाइव एंटरटेनमेंट बड़े पैमाने पर कैसे सार्थक बदलाव ला सकता है। विशाल और शेखर जैसे आइकॉन इस पहल को बड़ी क्रिएटिव एनर्जी और पहुँच देते हैं, जिससे हम दर्शकों को उस संदेश से जोड़ पाते हैं जो वाकई मायने रखता है, और भारत में उद्देश्य-आधारित मनोरंजन के लिए एक नया मानक तैयार होता है।



सुरों और संवेदना के समावेशन के साथ हुआ 'आयो बसंत' का बसंती आगाज़ शास्त्रीय संगीत, समावेशी कला और युवा रचनात्मकता का सजीव संगम

वीर अर्जुन संवाददाता

जयपुर। डेल्टाफेक काउन्सिल ऑफ राजस्थान द्वारा वेस्ट जून कल्चरल सेंटर, नॉर्थ जून कल्चरल सेंटर एवं उस्ताद इमामुद्दीन खान डगर म्यूजिक एंड कल्चर सोसायटी के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 'आयो बसंत' का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र, जयपुर में हुआ। यह महोत्सव भारतीय कला-संस्कृति की जीवंत परंपराओं को समकालीन रचनात्मक अभिव्यक्तियों से जोड़ने वाला एक सशक्त मंच बनकर उभरा। महोत्सव के पहले दिन प्रातः कृष्णायन सभागार में आयोजित रील मेकिंग एवं मोबाइल सेल्फी वर्कशॉप में युवाओं और कला-प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कलाकार नीरज सरना द्वारा संचालित इस कार्यशाला में डिजिटल माध्यमों के जरिये विचारों, भावनाओं और कला को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के आधुनिक तरीकों पर संवाद हुआ। शाम का सत्र जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में आईएएस श्रीमती श्रेया गुहा ने अतिथियों, कलाकारों एवं दर्शकों का स्वागत करते हुए कहा कि 'आयो बसंत' केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि संवेदना, समावेशन और रचनात्मक चेतना का उत्सव है। आईएएस डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी एवं आईएएस निशांत जैन की उपस्थिति में आयोजित इस खास कार्यक्रम में सुरों और संवेदना के समावेशन के साथ 'आयो बसंत' का बसंती आगाज़ हुआ। नॉर्थ जून कल्चरल सेंटर के निदेशक फुरकान खान ने भारतीय शास्त्रीय कलाओं, युवा प्रतिभाओं और नवाचार को प्रोत्साहित करने में ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके बाद आयोजित संगीत संस्था में संतूर और बांसुरी की सुरमयी जुगलबंदी ने श्रोताओं को भावलोक में पहुँचा दिया। युवा संतूर वादक दिव्यांशु हर्षित श्रीवास्तव एवं बांसुरी साधक राग यमन की प्रस्तुति को तबले पर ईशान शर्मा और घटम पर वरुण राजशेखरन की सधी हुई संगति ने प्रभावशाली ऊँचाइयों प्रदान कीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13वें इंडिया स्टोनमार्ट 2026 की तैयारियों को लेकर दिए दिशा-निर्देश

वीर अर्जुन संवाददाता

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 13वें इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के आयोजन की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, उद्योग अनुकूल वातावरण तथा निवेश संवर्धन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, रीको की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नरेश पारीक, इंडिया स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर लाल अजमेरा, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम, सीडोओएस के अधिकारी एवं आयोजन से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट न केवल राजस्थान बल्कि देश के स्टोन उद्योग के



लिए एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसके माध्यम से राज्य की प्राकृतिक संपदा, तकनीकी क्षमता और उद्यमशीलता को वैश्विक पहचान मिलती है।

उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप आयोजित किया जाए ताकि देश-विदेश से आने वाले निवेशकों और खरीदारों को सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो। बैठक में मुख्यमंत्री को आयोजन की अब तक की तैयारियों, प्रदर्शनी ढांचे, बी2बी मीटिंग्स, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी,

लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा व्यवस्था और प्रचार-प्रसार से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्टार्ट-अप, एमएसएमई इकाइयों और स्थानीय उद्यमियों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्टोन उद्योग राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में इंडिया स्टोनमार्ट 2026 को निवेश, नवाचार और व्यापार विस्तार का प्रभावी मंच बनाया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आशस्त किया कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 को

एक भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। इंडिया स्टोनमार्ट 2026 एक चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 में जयपुर स्थित जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुर में प्रस्तावित है। यह आयोजन प्राकृतिक पत्थरों (मार्बल, ग्रैनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन), माइनिंग, प्रोसेसिंग मशीनरी, टूल्स और स्टोन आर्ट से जुड़े उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। राजस्थान देश का अग्रणी स्टोन उत्पादक राज्य है और लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के माध्यम से राजस्थान के स्टोन उद्योग, कारीगरों और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों एवं निवेशकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार, यह आयोजन 'वोकल फॉर लोकल', 'मेक इन इंडिया' और राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति देगा।